बात भारत की

₹30.00

पाञ्चजन्य

27 सितम्बर, 2020

आश्विन शुक्ल 11, वि.सं. 2077, युगाब्द 5122

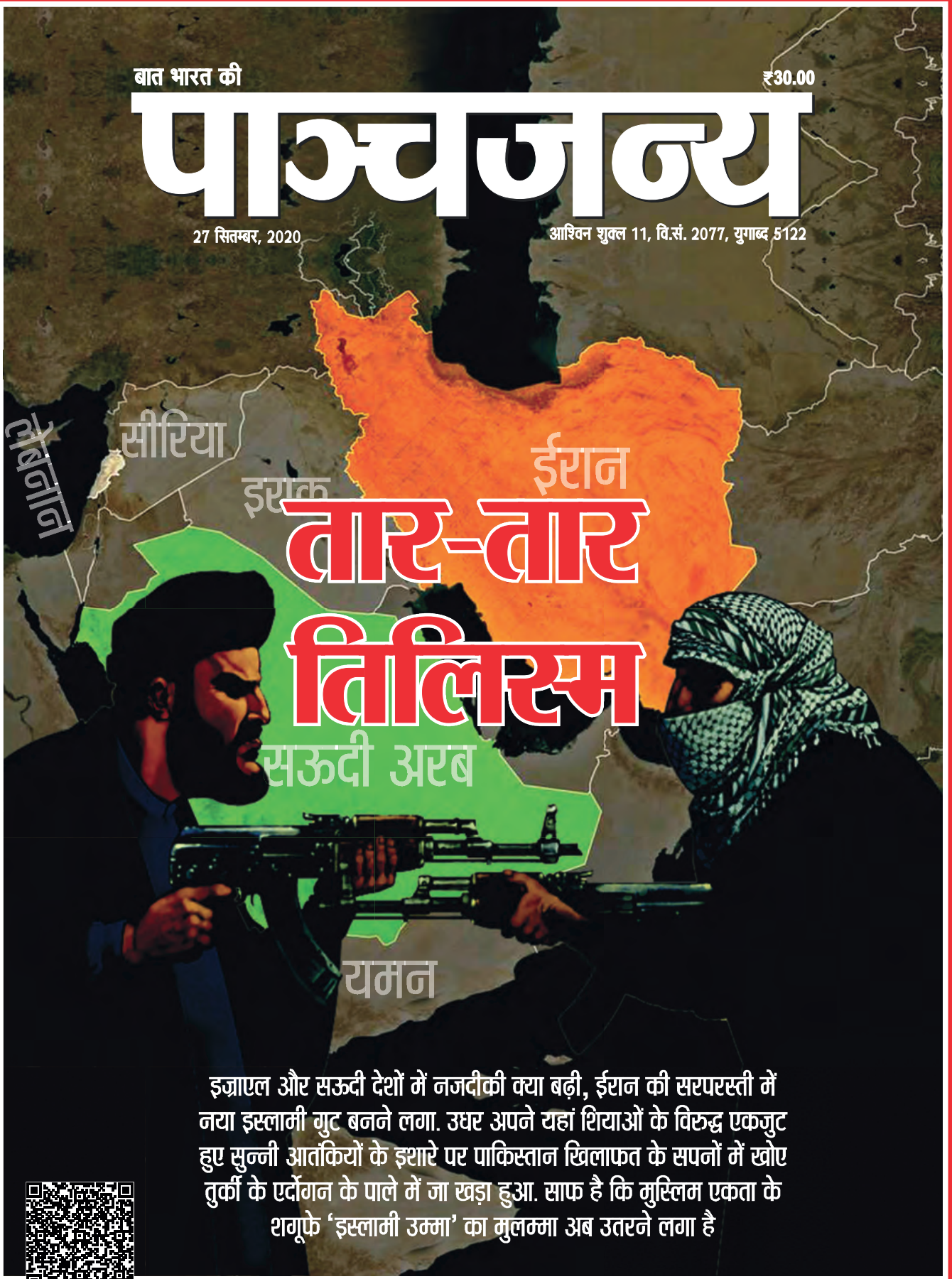

तार-तार तिलिस्म

इज़्राएल और सऊदी देशों में नजदीकी क्या बढ़ी, ईरान की सरपरस्ती में नया इस्लामी गुट बनने लगा. उधर अपने यहां शियाओं के विरुद्ध एकजुट हुए सुन्नी आतंकियों के इशारे पर पाकिस्तान खिलाफत के सपनों में खोए तुर्की के एर्दोगन के पाले में जा खड़ा हुआ. साफ है कि मुस्लिम एकता के शगूफे 'इस्लामी उम्मा' का मुलम्मा अब उतरने लगा है

www.panchjanya.com https://twitter.com/epanchjanya https://www.facebook.com/epanchjanya

VISIT…

श्री नरेन्द्रभाई मोदी
माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

श्री विजयभाई रूपाणी
माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात राज्य

गुजरात सरकार द्वारा सावधानी अभियान

"आइए, हम अपने धार्मिक स्थानों पर सतर्कता बरतें"

कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखें :

- सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें और औरों को भी ऐसा करने से रोकें।
- स्वयं गंदगी न करें और औरों को भी ऐसा करने से रोकें।
- "Aarogya-Setu" एप का रोज प्रयोग करें व अपने आरोग्य की स्वयं जांच के बाद ही धार्मिक स्थान में प्रवेश करें।
- धार्मिक स्थान में मास्क पहनकर ही प्रवेश करें।
- दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फुट का अंतर रखें।
- सामुहिक रुप से प्रार्थना, गीत, भजन, सत्संग न करें।
- धार्मिक स्थानों में कहीं भी स्पर्श न करें।

धार्मिक स्थान में प्रार्थना अथवा बंदगी के समय सोशियल डिस्टंसिंग का ध्यान रखें-आपस में दो गज की दूरी बनाये रखें।
-श्री नितिनभाई पटेल, उप मुख्यमंत्री, गुजरात राज्य

GUJARAT PAVITRA YATRADHAM VIKAS BOARD
GOVERNMENT OF GUJARAT

गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड, गुजरात सरकार

www.yatradham.gujarat.gov.in gpyvb@yahoo.co.in +91 79 23252468

बात भारत की
पाञ्चजन्य

वर्ष 72, अंक 16, अश्विन शुक्ल 11, वि.सं.- 2077
(युगाब्द 5122) 27 सितम्बर, 2020
आईएसएसएन : 2349-2392

संपादक : हितेश शंकर
सहयोगी संपादक : आलोक गोस्वामी
वरिष्ठ उपसंपादक : अरुण कुमार सिंह
मुख्य उपसंपादक : नागार्जुन
वरिष्ठ संवाददाता : अश्वनी मिश्र
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर : शशि मोहन रावत
सीनियर ग्राफिक डिजाइनर : मुक्ता सूरमा कटारिया
कला संयोजन : मंगल सिंह नेगी, राजपाल सिंह रावत, जनार्दन सिन्हा
छायाकार : हेमराज गुप्ता

E-mail: editor.panchjanya@gmail.com
Website: www.panchjanya.com

सम्पादकीय विभाग दूरभाष: 011-47642014

भारत प्रकाशन (दिल्ली) लिमिटेड

प्रबंध निदेशक : अरुण कुमार गोयल
महाप्रबंधक : जितेन्द्र मेहता
निदेशक एवं प्रकाशक : बिहारीलाल सिंघल

विज्ञापन विभाग

ईमेल : advt@bpdl.in
दूरभाष : 011-47642006, 09, 30

प्रसार विभाग

एकल ग्राहक सदस्यता : अरविंद सिन्हा-011-47642001
एजेंसी : उपेन्द्र सिंह -011-47642000
Email : circ@bpdl.in

ग्राहक शिकायत केन्द्र : 01147642015
Email : support@bpdl.in

पंजीकृत कार्यालय
संस्कृति भवन, 2322, लक्ष्मी नारायण गली
पहाड़गंज, नई दिल्ली-55,

लखनऊ ब्यूरो
ब्यूरो चीफ : सुनील राय
कार्यालय: विश्व संवाद केन्द्र,भूतल, डॉ. एम.सी. पंत मार्ग,
लोहिया पथ, जियामऊ, लखनऊ-226001

बेंगलुरु ब्यूरो
ब्यूरो चीफ : प्रशांत वैद्यराज
कार्यालय:विक्रमा प्रकाशन,न.106, 5 मेन रोड़,
पोस्ट बाक्स न.1804, चामराज पेट,बेंगलुरू-560018

संवाददाता: केरल-तिरुअनंतपुरम-प्रदीप कृष्णन, दूरभाष-0471-2732476, उत्तर प्रदेश-प्रयाग-हरिमंगल, दूरभाष-09415264688, उत्तराखण्ड-हल्द्वानी-दिनेश, दूरभाष-09897396330, बिहार-पटना-संजीव कुमार-दूरभाष-09430002248, प. बंगाल-कोलकाता-बासुदेव पाल-09674514952

मुद्रक एवं प्रकाशक बिहारीलाल सिंघल द्वारा भारत प्रकाशन (दिल्ली) लिमिटेड के लिए संस्कृति भवन, 2322, लक्ष्मी नारायण गली, पहाड़गंज, नई दिल्ली-55 से प्रकाशित तथा एचटी मीडिया लिमिटेड, प्लाट नं. 8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, (उ.प्र.) 201306 से मुद्रित। संपादक : हितेश शंकर

इस अंक में

08 आवरण कथा

उम्मा का उतरा मुलम्मा

पाकिस्तान में शिया और अहमदिया समुदायों के खिलाफ एक तरह से जंग का एलान कर दिया गया है। उन्मादी पाकिस्तान और उसके जिहादी आका खलीफा बनने का सपना पाल रहे तुर्की के एर्दोगन की गोद में जा बैठे हैं। तो उधर, अमेरिका की मध्यस्थता से इज्राएल और खाड़ी के देशों के बीच जमानों से जमी बर्फ पिघली है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बढ़ती खाई ध्वस्त हो रहे 'इस्लामी उम्मा' के ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है

सहज स्वभाव, गहन प्रभाव 5 डॉ. मनमोहन वैद्य
तार-तार होता इस्लामी उम्मा! 13 अनिल त्रिगुणायत
चीनी देह-व्यापार में पाकिस्तानी बेटियां 16 मलिक असगर हाशमी
चलो चलें आस्था की डगर 18 डॉ. संदीप कुलश्रेष्ठ
'कल्पतरु' की छांव में पल रही जिंदगी 24 अरुण कुमार सिंह
चीन की आक्रामकता और बेचैनी क्यों? 25 कर्नल शिवदान सिंह
ईसाई बाने में रोहिंग्या घुसपैठिए 30 एस. वर्मा
खिलाफत के खोल में हिंसा 33 डॉ. श्रीरंग गोडबोले
दीनों पर दया करने वाले दीनदयाल 38 प्रो. रसाल सिंह
भारतीय भाषाओं के प्रबल पक्षधर 41 प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी
मुसलमानों को पुचकारा, हिंदुओं को दुत्कारा 44 राघवेंद्र सिंह
बाहरी मदद से बढ़े चीनी कम्युनिस्ट 46 प्रो. कुसुमलता केड़िया
गेशे जम्पा 38 नीरजा माधव
बाल आयोग के पीछे पड़ा जिहादी गिरोह 50 प्रतिनिधि

आज-कल

पाक को काली सूची का खौफ

पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा काली सूची में डालने का खतरा मंडरा रहा है। इससे बचने के लिए इमरान खान सरकार ने सहकारी समितियों के पंजीयन और नियमन में ज्यादा नियंत्रण व पारदर्शिता लाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। कहने को इसका उद्देश्य आतंकी वित्त पोषण को रोकना है। पाकिस्तान जून 2018 से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। इससे निकलने के लिए उसे एक कार्ययोजना पर अमल करने को कहा गया है।

कोरोना को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी की खोज

भारतवंशी श्रीराम सुब्रमण्यम और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सबसे छोटे एंटीबॉडी की खोज की है, जो सार्स-कोवी-2 वायरस को पूरी तरह बेअसर कर सकता है। एबी8 दवा में पाया जाने वाला यह एंटीबॉडी सामान्य आकार की एंटीबॉडी से 10 गुना छोटा है। यह न केवल कोविड-19 को बेअसर करने वाले ऊतकों की क्षमता बढ़ाता है, बल्कि संक्रमण से भी बचाता है। इसके दुष्प्रभाव की आशंका नहीं के बराबर है।

बोलते आंकड़े

अप्रैल 2016 से मार्च 2020 तक चीन ने भारत की 1600 कंपनियों में 1.02 अरब डॉलर यानी 102 करोड़ 2.5 लाख डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। ऑटोमोबाइल उद्योग में सर्वाधिक 17.2 करोड़ डॉलर, जबकि सेवा क्षेत्र में 13 करोड़ 76.5 लाख डॉलर का एफडीआई आया।

मुगल संग्रहालय का नाम बदला

आगरा में ताजमहल के पूर्वी द्वार पर करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। इसलिए गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिह्नों की जगह राष्ट्र के प्रति गौरवबोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे नायक मुगल नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। देश में अकबर के नाम पर 251 गांवों और कस्बों के नाम हैं। वहीं औरंगजेब के नाम पर 177, जहांगीर 141, शाहजहां 63, बाबर 41 तथा हुमायूं के नाम पर 11 स्थानों के नाम हैं।

रूस में पाकिस्तान का बहिष्कार

मॉस्को में रूस की मेजबानी में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में पाकिस्तान ने नापाक हरकत की। बैठक में उसने वह नक्शा पेश किया, जिसे पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है। इसमें जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। पाकिस्तान की इस हरकत का विरोध करते हुए एनएसए अजीत डोवाल ने बैठक का बहिष्कार किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने जो किया, वह साफतौर पर बैठक के नियमों का उल्लंघन है। इसलिए भारत ने मेजबान के साथ इस पर विचार-विमर्श के बाद बैठक बीच में ही छोड़ दी।

आमने-सामने

कुछ लोगों की वजह से आप पूरे उद्योग की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। मुझे शर्म आती है कि लोकसभा में हमारे एक सदस्य, जो फिल्म उद्योग से हैं, उन्होंने इसके खिलाफ बोला। यह शर्मनाक है। जिन लोगों ने फिल्म उद्योग से नाम कमाया, वे इसे गटर बता रहे हैं। आप जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर फिल्म उद्योग को बदनाम किया जा रहा है।

– **जया बच्चन**, सांसद, सपा

मुझे लगा कि मैंने जो कहा, जया जी उसका समर्थन करेंगी। फिल्म उद्योग में हर कोई ड्रग्स नहीं लेता, लेकिन कुछ लोग दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने की योजना का हिस्सा हैं। इसे बचाने की जरूरत है। मैंने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में मुकाम हासिल किया है। मैं खुद की बनाई थाली में छेद नहीं करता। मैंने तो बॉलीवुड ड्रग्स माफिया की बात की थी। मैं जया बच्चन जी के बयान से हैरान हूं।

– **रवि किशन**, सांसद, भाजपा

साइबर गुटरगूं

वह तो बंगाल से आए थे। दिल्ली में रहते थे। हमने कई बार कहा- कमलनाथ जी कभी बाहर निकलो, जनता कष्ट में है। बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया। वह बोले- हम ऐसे मुख्यमंत्री थोड़े हैं जो गली-गली फिरें। हम तो यहीं बंगले में बैठकर देख लेते हैं।

–**शिवराज सिंह चौहान**, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

कांग्रेस ने कहा था कि किसानों का कर्ज हम 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि गद्दार यदि कोई है तो वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं, जिन्होंने किसानों का कर्ज आज तक माफ नहीं किया। उनको सबक सिखाने का समय आ गया है।

– **ज्योतिरादित्य सिंधिया**, सांसद, भाजपा

■ डॉ. मनमोहन वैद्य

सहज स्वभाव, गहन प्रभाव

श्रेष्ठ चिंतक, संगठक और दीर्घद्रष्टा नेता भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी की जन्मशती के अवसर पर याद आते हैं संगठन हेतु उनके दिए सूत्र और देश व समाज को उनका महती योगदान

जिस समय स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की, वह साम्यवाद के वैश्विक आकर्षण, वर्चस्व और बोलबाले का समय था। उस परिस्थिति में राष्ट्रीय विचार से प्रेरित शुद्ध भारतीय विचार पर आधारित एक मजदूर आंदोलन की शुरुआत करना तथा अनेक विरोध और अवरोधों के बावजूद उसे लगातार बढ़ाते जाना, यह पहाड़-सा काम था। श्रद्धा, विश्वास और सतत परिश्रम के बिना यह काम संभव नहीं था। तब उनकी कैसी मनःस्थिति रही होगी, इसे समझने के लिए एक दृष्टांत-कथा याद आती है–

अभी वसंत की बयार बहनी शुरू भी नहीं हुई थी। आम पर बौर भी नहीं आया था। तभी सर्द पवन के झोंकों के थपेड़े सहता हुआ एक जन्तु अपने बिल में से बाहर निकला। उसके रिश्तेदारों ने उसे बहुत समझाया कि अपने बिल में ही रहकर आराम करो, ऐसे समय बाहर निकलोगे तो मर जाओगे। पर उसने किसी की एक न सुनी। बड़ी ही मुश्किल से वह आम्रवृक्ष के तने पर चढ़ने लगा। ऊपर आम की डाल पर झूमते हुए एक तोते ने उसे देखा। अपनी

श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी

चोंच नीचे झुकाते हुए उसने पूछा, 'अरे ओ जन्तु, इस ठंड में कहां चल दिए?'

'आम खाने।' जंतु ने उत्तर दिया।

तोता हंस पड़ा। उसे वह जन्तु मूर्खों का सरदार लगा। उसने तुच्छता से कहा, 'अरे मूर्ख, आम का तो अभी इस वृक्ष पर नामोनिशान नहीं है। मैं उपर–नीचे सभी जगह देख सकता हूं!'

'तुम भले ही देख सकते होगे,' जंतु ने अपनी डगमग चाल चलते हुए कहा, 'पर मैं जब तक पहुंचूंगा तब वहां आम अवश्य होगा।'

इस जन्तु के जवाब में किसी साधक की सी जीवनदृष्टि है। वह अपनी क्षुद्रता को नहीं देखता। प्रतिकूल संजोगों से वह घबराता नहीं है। ध्येय का कोई भी चिन्ह दिखाई न देने के बावजूद उसे अपनी ध्येयप्राप्ति के विषय में सम्पूर्ण श्रद्धा है। अपने एक-एक कदम के साथ फल भी पकते जायेंगे, इस बारे में उसे रत्तीभर संदेह नहीं है।

उसके रिश्तेदार या तोता-पंडित चाहे कुछ भी कहें, उसकी उसे परवाह नहीं है।

उसके अंतर्मन में तो बस एक ही लगन है और एक ही रटन-

'हरि से लागी रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई।'

और आज हम देखते हैं कि भारतीय मजदूर संघ भारत का सर्वाधिक बड़ा मजदूर संगठन है।

अच्छे संगठक का यह गुण होता है कि आप कितने भी प्रतिभावान क्यों ना हों, अपने सहकारियों के विचार और सुझाव को खुले मन से सुनना और योग्य सुझाव को सहज स्वीकार भी करना। ठेंगड़ी जी ऐसे ही संगठक थे। जब श्रमिकों के बीच कार्य प्रारम्भ करना तय हुआ तब उस संगठन का नाम 'भारतीय श्रमिक संघ' सोचा गया था। परंतु जब इससे सम्बंधित कार्यकर्ताओं की पहली बैठक में यह बात सामने आई कि समाज के जिस वर्ग के बीच हमें कार्य करना है, उनके लिए 'श्रमिक' शब्द समझना आसान नहीं होगा। कुछ राज्यों में तो इसका सही उच्चारण करने में भी दिक़्क़त आ सकती है, इसलिए 'श्रमिक' के स्थान पर आसान शब्द 'मजदूर' का उपयोग करना चाहिए। उसे तुरंत स्वीकार किया गया और संगठन का नाम 'भारतीय मजदूर संघ' तय हुआ।

श्री ठेंगड़ी जी के साथ चर्चा में भारतीय चिंतन की गहराइयों के विविध पहलू सहज खुलते थे। मजदूर क्षेत्र में साम्यवादियों के वर्चस्व के कारण कामगार संगठनों की भाषा या नारे भी साम्यवादियों की शब्दावली में हुआ करते थे। उन्होंने साम्यवादी नारों के स्थान पर अपनी भारतीय विचार शैली का परिचय कराने वाले नारे गढ़े। 'उद्योगों का राष्ट्रीयकरण' के स्थान पर उन्होंने कहा–हम 'राष्ट्र का औद्योगीकरण–उद्योगों का श्रमिकीकरण और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण' चाहते हैं

संगठन में काम करना मतलब 'मैं' से 'हम' की यात्रा करना होता है। कर्तृत्ववान व्यक्ति के लिए यह आसान नहीं होता। वह अपने 'मैं' के प्रेम में पड़ता है। किसी तरह यह 'मैं' व्यक्त होता ही रहता है। संतों ने कहा है कि इस 'मैं' की बात ही कुछ अजीब है। वह अज्ञानी को छूता तक नहीं है। पर ज्ञानी का गला ऐसा पकड़ लेता है कि उसका छूटना बड़ा कठिन होता है। पर संगठन में, संगठन के साथ और संगठन के लिए काम करने वालों को इससे बचना ही पड़ता है। ठेंगड़ी जी ऐसे ही थे। सहज बातचीत में भी उनके द्वारा कोई महत्व की बात, दृष्टिकोण या समाधान दिए जाने को भी कहते समय 'मैंन' ऐसा कहा, ऐसा कहने के स्थान पर वे हमेशा 'हमने' ऐसा कहा, ही कहते थे। इस 'मैं' का ऊर्ध्वीकरण आसान नहीं होता। परन्तु ठेंगड़ी जी ने इसमें महारत प्राप्त की थी, जो एक संगठक के लिए बहुत आवश्यक होती है।

ठेंगड़ी जी की एक और बात लक्षणीय थी कि वे सामान्य से सामान्य मजदूर से भी इतनी आत्मीयता से मिलते थे, उसके कंधे पर हाथ रखकर, साथ चहलकदमी करते हुए उससे बातें करते थे कि किसी को भी नहीं लगता था कि वह एक अखिल भारतीय स्तर के नेता, विश्वविख्यात चिंतक से बात कर रहा है। बल्कि उसे ऐसी अनुभूति होती थी मानो वह अपने किसी अत्यंत आत्मीय बुजुर्ग, परिवार के ज्येष्ठ व्यक्ति से मिल रहा है। यह करते समय ठेंगड़ी जी की सहजता विलक्षण होती थी।

उनका अध्ययन बहुत व्यापक और गहरा था। अनेक पुस्तकों के सन्दर्भ और अनेक नेताओं के किस्से उनके साथ बातचीत में आते थे। पर एक बात जो मेरे दिल को छू जाती थी, वह यह थी कि कोई एक किस्सा या चुटकुला जो ठेंगड़ी जी ने अनेक बार अपने वक्तव्य में सुनाया होगा, वही किस्सा या चुटकुला यदि मेरे जैसा कोई अनुभवहीन, कनिष्ठ कार्यकर्ता सुनाने लगता तो वे कहीं पर भी उसे जरा भी आभास नहीं होने देते थे कि वे यह किस्सा जानते हैं। यह संयम आसान नहीं है। मैं तो यह जानता हूं, ऐसा कहने

का या जताने का मोह अनेक बड़े, अनुभवी कार्यकर्ताओं को होता है, ऐसा मैंने कई बार देखा है। पर ठेंगड़ी जी उसे ऐसी लगन से, ध्यानपूर्वक सुनते थे कि मानो पहली बार सुन रहे हों। उस पर भावपूर्ण प्रतिसाद भी देते थे और तत्पश्चात उसके अनुरूप और एक नया किस्सा या चुटकुला अवश्य सुनाते थे। जमीनी कार्यकर्ता से इतना जुड़ाव और लगाव श्रेष्ठ संगठक का ही गुण है।

अपना कार्य बढ़ाने की उत्कंठा, इच्छा और प्रयास रहने के बावजूद अनावश्यक जल्दबाजी नहीं करना, यह भी श्रेष्ठ संगठक का गुण है। परमपूजनीय श्री गुरुजी कहते थे–'धीरे-धीरे जल्दी करो'। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र में मेरे एक किसान मित्र श्री शरद जोशी द्वारा निर्मित 'शेतकारी संगठन' नामक किसान आंदोलन में विदर्भ प्रदेश के प्रमुख नेता थे। बाद में उस आंदोलन से उनका मोहभंग हुआ, तब मेरे छोटे भाई के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। मेरा भाई भी तब किसानी करता था। मेरे भाई को लगा कि किसान संघ का कार्य अभी-अभी शुरू हुआ है तो इस किसान नेता को किसान संघ के साथ जोड़ना चाहिए। उसने मुझसे बात की। मुझे भी यह सुझाव अच्छा लगा। यह एक बड़ा नेता था। किसान संघ का कार्य श्री ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में शुरू हो चुका था। इसलिए यह प्रस्ताव लेकर मैं अपने भाई के साथ नागपुर में ठेंगड़ी जी से मिला। ठेंगड़ी जी उस किसान नेता को जानते थे। मुझे पूर्ण विश्वास था कि किसान संघ के लिए एक अच्छा प्रसिद्ध किसान नेता मिलने से किसान संघ का कार्य बढ़ाने में सहायता होगी और इसलिए ठेंगड़ी जी उसे तुरंत आनंद के साथ स्वीकार करेंगे। परन्तु पूर्वभूमिका बताकर जैसे ही मैंने यह प्रस्ताव उनके सामने रखा, ठेंगड़ी जी ने उसे तुरंत अस्वीकार किया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बाद में ठेंगड़ी जी ने मुझे कहा कि हम इसलिए इस नेता को नहीं लेंगे क्योंकि हमारा किसान संघ बहुत छोटा है। वह इतने बड़े नेता को पचा नहीं पायेगा और यह नेता हमारे किसान संघ को अपने साथ खींचकर ले जायेगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इस पर मैंने कहा कि यदि किसान संघ उसे स्वीकार नहीं करेगा तो भाजपा के लोग उसे अपनी पार्टी में शामिल कर चुनाव भी लड़ा सकते हैं। इस पर ठेंगड़ी जी ने शांत स्वर में कहा कि भाजपा को जल्दबाजी होगी, पर हमें नहीं है। उनका यह उत्तर इतना स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण था कि मेरे लिए यह एक महत्वपूर्ण सीख बन गया। और तब जाकर श्री गुरूजी की 'धीरे-धीरे जल्दी करो' उक्ति का गूढ़ार्थ मेरी समझ में आया।

ठेंगड़ी जी की एक बात लक्षणीय थी कि वे सामान्य से सामान्य मजदूर से भी इतनी आत्मीयता से मिलते थे, उसके कंधे पर हाथ रखकर, साथ चहलकदमी करते हुए उससे बातें करते थे कि किसी को भी नहीं लगता था कि वह एक अखिल भारतीय स्तर के नेता, विश्वविख्यात चिंतक से बात कर रहा है। बल्कि उसे ऐसी अनुभूति होती थी मानो वह अपने किसी अत्यंत आत्मीय बुजुर्ग, परिवार के ज्येष्ठ व्यक्ति से मिल रहा है। यह करते समय ठेंगड़ी जी की सहजता विलक्षण होती थी।

श्री ठेंगड़ी जी श्रेष्ठ संगठक के साथ साथ एक दार्शनिक भी थे। भारतीय चिंतन की गहराइयों के विविध पहलू उनके साथ बातचीत में सहज खुलते थे। मजदूर क्षेत्र में साम्यवादियों का वर्चस्व एवं दबदबा था इसलिए सभी कामगार संगठनों की भाषा या नारे भी साम्यवादियों की शब्दावली में हुआ करते थे। उस समय उन्होंने साम्यवादी नारों के स्थान पर अपनी भारतीय विचार शैली का परिचय कराने वाले नारे गढ़े। 'उद्योगों का राष्ट्रीयकरण' के स्थान पर उन्होंने कहा–हम 'राष्ट्र का औद्योगीकरण-उद्योगों का श्रमिकीकरण और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण' चाहते हैं। श्रम क्षेत्र में अनावश्यक संघर्ष बढ़ाने वाले असंवेदनशील नारे-'हमारी मांगें पूरी हों-चाहे जो मजबूरी हो' के स्थान पर उन्होंने कहा 'देश के लिए करेंगे काम-काम के लेंगे पूरे दाम'। यानी, श्रम के क्षेत्र में भी सामंजस्य और राष्ट्रप्रेम की चेतना जगाने का सूत्र उन्होंने नारे में इस छोटे से बदलाव से दे दिया। भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ के अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, प्रज्ञा प्रवाह, विज्ञान भारती आदि संगठनों की रचना की नींव में ठेंगड़ी जी का योगदान और सहभाग रहा है। उन्होंने भारतीय कला दृष्टि पर जो निबंध प्रस्तुत किया वह आगे जा कर संस्कार भारती का वैचारिक अधिष्ठान बना।

श्री ठेंगडी जी के समान एक श्रेष्ठ चिंतक, संगठक और दीर्घद्रष्टा नेता के साथ रहकर, संवाद कर, उनका चलना, उठना-बैठना, उनका सलाह देना, यह सब प्रत्यक्ष अनुभव करने का, सीखने का सौभाग्य मिला। श्री ठेंगड़ी जी की जन्मशती के मंगल अवसर पर उनकी पावन स्मृति को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि।

(लेखक रा.स्व. संघ के सहसरकार्यवाह हैं)

उम्मा का उतरा मुलम्मा

पाकिस्तान के सुन्नियों ने हिन्दुओं, ईसाइयों, सिखों के साथ ही अब अहमदियाओं और शियाओं के खिलाफ भी हथियार उठा लिए हैं। आज वहां इन दोनों समुदायों के लोगों पर वैसा ही खतरा मंडरा रहा है जैसा वहां के गैर इस्लामी अल्पसंख्यक समुदाय एक लंबे अरसे से भुगते आ रहे हैं

कराची में शिया विरोधी रैली में सम्मिलित कट्टरपंथी सुन्नी गुटों के लोग

रैली में यूं गाड़ियों में भरकर पहुंचे थे आतंकी गुटों के हथियारबंद जिहादी

■ मलिक असगर हाशमी

इमरान खान का 'नया पाकिस्तान' जिहाद की नई राह पर चल पड़ा है। अभी तक पाकिस्तान पोषित जिहादी भारत, अफगानिस्तान, ईरान सहित अन्य पड़ोसी देशों के विरुद्ध हथियार उठाते रहे। अब उन्होंने अपने ही देश की उन तमाम समुदायों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान को न केवल बनाया, संवारा, बल्कि अंधेरे से निकाल कर तरक्की के रास्ते पर ले गए। ऐसे समुदायों के विरुद्ध हथियार उठाने वाले

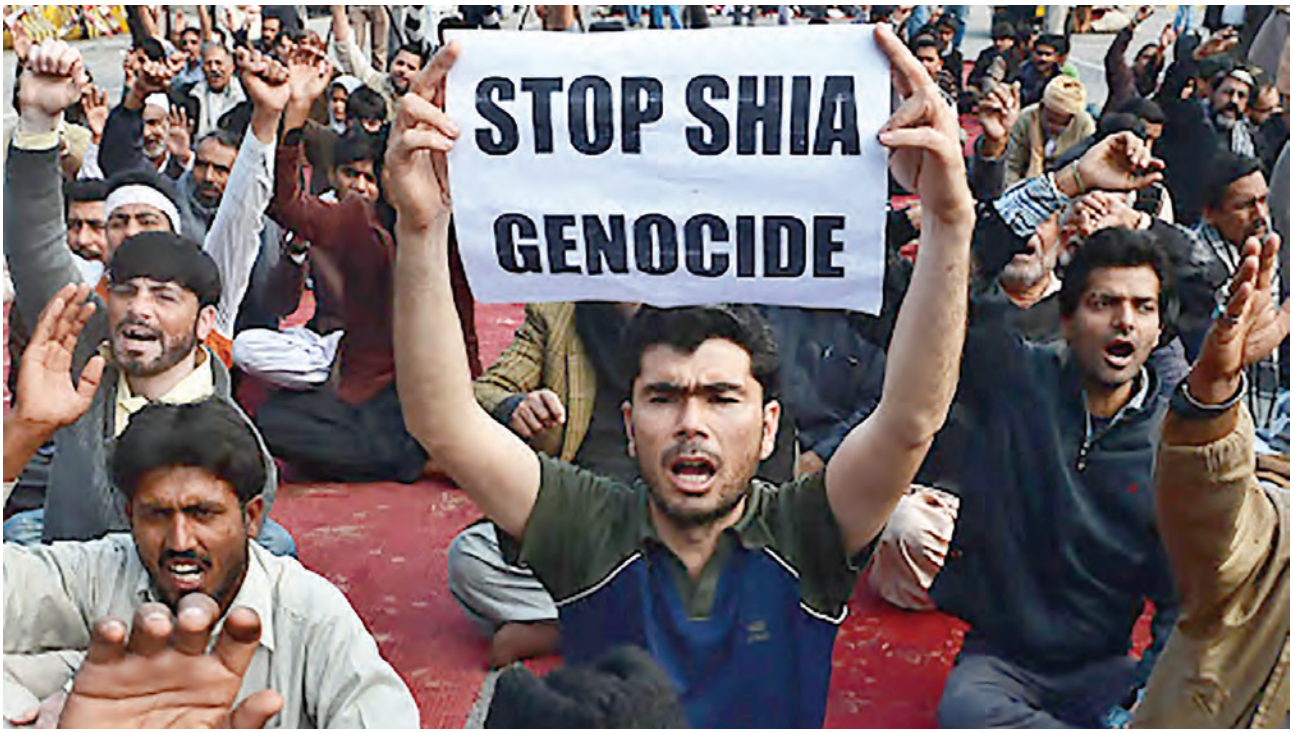

शिया नरसंहार के विरुद्ध लामबंद हो रहे हैं पाकिस्तान के शिया (फाइल चित्र)

इस्लाम की 'उम्मा' की अवधारणा को भी ध्वस्त कर रहे हैं, जो तमाम मुसलमानों के एक होने जाने की मुनादी करता है।

पाकिस्तान की कट्टरपंथी जमातों के लोग वहां हिंदुओं, ईसाइयों एवं सिखों को प्रताड़ित करते ही आ रहे हैं। आए दिन उनकी हत्या, बलात्कार, गांव के गांव जलाने की घटनाएं सुनने में आती हैं। उनकी बहू-बेटियों का अपहरण, कन्वर्जन हो रहा है। इसके साथ ही ताजा घटनाक्रम बताते हैं कि अब उन्होंने देश के शिया एवं अहमदिया समुदायों के विरुद्ध खुली जंग का एलान कर दिया है। पाकिस्तान के सुन्नी शायद भूल गए हैं कि उस मुल्क के जनक एवं उनके कायदे-आजम मोहम्मद अली जिन्ना शिया थे, जबकि पाकिस्तान का खाका तैयार करने वाले तथा भारत के बंटवारे से पहले हिंदुस्थान-पाकिस्तान की सीमा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में अग्रणी चौधरी सर मोहम्मद जफरुल्ला खान अहमदिया मुसलमान थे। मगर 'नबूवत' एवं 'नमाज' के तरीकों की आड़ में देश की स्थापना में अग्रणी रहे इन दोनों फिरकों के लोगों के खिलाफ कट्टरपंथियों एवं जिहादियों ने संघर्ष शुरू दिया है। गत 11 सितम्बर को कराची के राजमार्ग 'शहराह-ए-कैदन' पर लाखों कट्टरपंथियों ने रैली करके इसके स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। इस रैली के तुरंत बाद कोहट के बाजार में एक आतंकवादी ने शिया दुकानदार जमील अब्बास के बेटे कमर अब्बास के सीने में पिस्तौल से ताबड़तोड़ छह गोलियां उतार बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। 'अहले सुन्ना वल जमात' द्वारा आयोजित इस रैली में शिया एवं अहमदियों को निशाना बनाने वाले आतंकवादी संगठन सिपह-ए-सहाबा के लोग हथियारों के साथ शामिल थे। इसमें दूसरे इस्लामी संगठनों एवं राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। रैली में नारा लगाया गया 'शिया काफिर है, गद्दार है।'

रैली में कट्टरपंथियों के आक्रमक रवैये से पाकिस्तान ही नहीं, विश्व भर के शिया एवं अहमदिया समुदाय के लोग सशंकित हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान में बसे लोगों की अब खुलेआम 'नस्ल-कुशी' यानी नस्ल बर्बादी का खेल शुरू हो जाएगा। पहले यह ढके-छुपे ढंग से हो रहा था। ऐसी आशंका को देखते हुए आल इंडिया शिया हुसैनी फंड ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। फंड के महासचिव सैयद हसन मेहंदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखे पत्र में कहा गया कि पाकिस्तान का शिया समुदाय भयभीत है। कट्टरपंथी पिछले तीन दशक में उनकी कौम के 30 हजार लोगों की हत्या कर चुके हैं। प्रत्येक वर्ष मुहर्रम पर शियाओं को निशान बनाया जाता है। उन्हें पैगंबर के नवासों के सम्मान में 'मर्सिया' पढ़ने की इजाजत नहीं है। ऐसा ही पत्र संयुक्त राष्ट्र को विश्व के अलग-अलग हिस्सों में बसे

अहमदियाओं की ओर से भी लिखा गया है।

पाकिस्तान में तकरीबन 96 प्रतिशत मुसलमान हैं, जिनमें शियाओं की आबादी करीब 15-20 फीसदी है। बावजूद इसके उनकी मजहबी मान्यताओं के कारण उन्हें अहमियत नहीं दी जाती। नौकरियों या अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। अब तो उन्हें पाकिस्तान ही छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। बलूचियों एवं सिंधियों की तरह शियाओं एवं अहमदियों के बच्चे भी रहस्यमय तरीके से गायब किए जा रहे हैं। 16 नवंबर 2016 को सेना के लोग आधी रात को नईम हैदर को उठा ले गए थे, जिसका आज तक पता नहीं चला। बीबीसी के सिकंदर किरमानी की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 2016-18 में शिया समुदाय के 140 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जबकि 2018 में गायब हुए 1500 शियाओं का मामला अब तक अनसुलझा है। समीर अब्बास को विभिन्न आरोपों में एक साल तक हिरासत में रखा गया। अभी तक ऐसी कार्रवाइयां सरकारी स्तर पर हो रही थीं। अब तो आतंकवादियों ने उनके विरुद्ध खुला जिहाद छेड़ दिया है। गत 11 सितम्बर को कराची के अलावा मुल्क के अन्य हिस्सों में शिया-अहमदिया के विरुद्ध प्रदर्शन हुए। शिया समुदाय के मेहंदी रिजवी ने ट्वीट करके इसे 'काला शुक्रवार' बताया, जबकि अमेरिकी अखबार फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि, रैली से अल्पसंख्यकों में भय पैदा होगा। पाकिस्तान में हिंसा के एक नए दौरान की शुरुआत हो चुकी है।

अल्पसंख्यकों में 'अहमदिया गए-गुजरे'

अहमदियाओं का मामला शिया समुदाय से थोड़ा भिन्न है। उन्हें मुसलमान माना ही नहीं जाता। इस्लामिक नजरिए से हजरत मुहम्मद आखिरी पैगंबर हैं। अहमदिया इस मजहब के जनक मिर्जा गुलाम अहमद को अपना पैगंबर मानते हैं। शियाओं की तरह अहमदियाओं के नमाज पढ़ने का तरीका भी सुन्नियों से भिन्न

शिया-अहमदिया अब हुए 'गद्दार'

मुहर्रम के अवसर पर इकट्ठी हुई शिया महिलाएं

एक षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान में शिया एवं अहमदिया समुदायों को देश विरोधी प्रचारित किया जा रहा है ताकि उनके खिलाफ आम जनता भड़क जाए। नए दौर के जिहादी मुल्क को बनाने वालों को ही देश का दुश्मन बता रहे हैं। इसे साबित करने को झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं। माहौल बनाया जा रहा कि देश का बहुसंख्यक आम सुन्नी समुदाय भड़क जाए। इस साजिश के तहत शियाओं के बारे में कहा जा रहा कि 'सीरिया के लड़ाकों को मात देने के लिए जिस गुप्त सेना 'जैनबियून ब्रिगेड' का गठन किया गया है, उसे खड़ा करने में पाकिस्तान के शियाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश के हजार से अधिक शिया संगठन इसको बनाने में आगे रहे हैं'। ऐसे भ्रामक प्रचार से पाकिस्तान में शियाओं के प्रति माहौल खराब हुआ है। मुहर्रम के दौरान उन्हें जगह-जगह निशाना बनाया गया। एक दुष्प्रचार यह भी है कि पिछले महीने मुहर्रम के आशूरा जलूस में शियाओं ने इस्लाम विरोधी टिप्पणियां कीं। मर्सिया पढ़ते समय ऐसी बातें कही गईं जो ईशनिंदा की श्रेणी में आती हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए ईशनिंदा कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसे दुष्प्रचार के कारण मुहर्रम के स्मरणोत्सव में शियाओं पर हथगोले फेंके गए। कश्मीर एवं काबुल में शियाओं को आशूरा जुलूस निकालने से रोका गया। शासन-प्रशासन भी शिया एवं अहमदियाओं के विरुद्ध मोर्चा खोलने वाले कट्टरपंथियों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इसका प्रमाण है पत्रकार बेलाल फारुकी की गिरफ्तारी। उन्होंने जब कट्टरपंथियों की कराची रैली और मुहर्रम के मौके पर शियाओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की करतूतों का अपने अखबार में खुलासा किया तो उन्हें देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया।

है। इस वजह से अहमदियाओं को इस्लाम से 'खारिज' कर दिया गया था। हालांकि भारत सहित विश्व के कई अन्य देशों में इस बिना पर उनके साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जाता। सुन्नी उनके मामलों में हस्ताक्षेप नहीं करते, पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहां 1974 में कानून में संशोधन कर उनसे न केवल मुसलमान होने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि उन्हें हिंदू, सिख, ईसाई की तरह अल्पसंख्यकों की श्रेणी में डाल दिया गया। पाकिस्तान में आज स्थिति यह है कि कोई अहमदिया किसी को 'अस्सलाम ओ-अलैकुम' नहीं कह सकता। इमरान खान की तहरीक इंसाफ सरकार में उनके प्रति अत्याचार बढ़े हैं। उनकी सरकार ने अहमदिया सलाहकार को हटा दिया। इस वर्ष मजहबी नजरिए से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठित किया गया, पर अहमदिया उससे भी बाहर रखे गए। पाकिस्तान में अहमदियाओं की आबादी करीब 25 लाख है। ये अधिकतर पंजाब के रबवा जिले में रहते

पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में तीन अहमदिया फांसी के फंदे पर झूल चुके हैं। हाल में उनकी मस्जिदों में नमाज व अजान पर भी रोक लगा दी गई है। कुछ दिन पहले ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार चार अहमदियाओं में से तीन को जमानत पर छोड़ दिया गया पर चौथे की पुलिस हिरासत में गोली मार कर हत्या कर दी गई। पिछले कुछ दिनों में कुल 260 अहमदियाओं की हत्या की जा चुकी है।

हैं। भारत के पंजाब, राजस्थान एवं मुंबई में बड़ी संख्या में अहमदिया हैं। वे खास तरह की टोपी एवं बुर्के के कारण दूर से पहचाने जा सकते हैं। 1974 में कानून में संशोधन कर अहमदियाओं को इस्लाम से 'खारिज' करने के बाद से उनका पाकिस्तान से पलायन जारी है। उनका मजहबी स्थान कादियां भी पंजाब से इंग्लैंड स्थानांतरित कर दिया गया। वैज्ञानिक परवेज हुदभाय कहते हैं, उसी दौरान 1980 में इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन के लिए भौतिकी का नोबेल सम्मान जीतने वाले इकलौते पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल सलाम देश छोड़कर विदेश जा बसे। 2016 में इस्लामाबाद की कायदे-आजम यूनिवर्सिटी ने उन्हें सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम किया था, पर जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठन के विरोध के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो सके। हालांकि बाद में वह न केवल नवाज शरीफ सरकार में वैज्ञानिक सलाहकार बने, बल्कि भौतिकी से विदेश में पीएचडी करने वाले पांच छात्रों को उनके नाम पर स्कॉलरशिप देने का ऐलान भी किया गया। अब्दुल सलाम को पाकिस्तान के अंतरिक्ष एवं परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अहमदिया मजहब के अब्दुल सलाम अपवाद हैं। पाकिस्तान का आम अहमदिया बहुत ज्यादा त्रस्त है। यह कौम व्यापार-कारोबार के लिए पहचानी जाती है। कट्टरपंथियों ने उनसे कारोबारी रिश्ता नहीं रखने का एलान किया है। भारत के पंजाब के कादियां के 121वें जलसे में भाग लेने पाकिस्तान से आए रसूर अहमद व अश्फाक अहमद बताते हैं कि एक बार उनके समुदाय ने झांग जिले में मजहबी गीत नात पढ़ने की प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें उनके समुदाय की एक छात्रा को पांचवां स्थान मिला। उसके बाद कट्टरपंथी उनके पीछे पड़ गए। प्रतियोगिता में पांचवें नंबर पर आने वाली छात्रा को जान से मारने की धमकी दी गई। पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में तीन अहमदिया फांसी के फंदे पर झूल चुके हैं। हाल के दिनों में उनकी मस्जिदों में नमाज व अजान की अदायगी पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस ने कुछ दिनों पहले चार युवाओं को ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनमें से तीन को जमानत पर छोड़ दिया गया पर चौथे की पुलिस हिरासत में गोली मार कर हत्या कर दी गई। पत्रकार महबूब की रिपोर्ट कहती है कि एक बार एक ही झटके में 13 अहमदियाओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। फैसलाबाद में अहमदियाओं की एक मस्जिद जला दी गई। हाल के दिनों में 260 अहमदियाओं को मौत के घाट उतारा गया है। पाकिस्तान के स्वतंत्र लेखक मिर्जा उस्मान अहमद कहते हैं कि अहमदियाओं को लेकर यह भ्रम फैला जा रहा कि वे यहूदी समर्थक एवं इस्लाम के दुश्मन हैं। इस वर्ष 8 मई को न्यूज चैनल अलजजीरा ने पाकिस्तान के अहमदियाओं के साथ भेद-भाव पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रसारित की थी। वेबसाइट पुलित्जर सेंटर से प्रकाशित अयीहाल चौधरी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के सशस्त्र बलों में एक दशक तक सेवाएं देने वाले 38 वर्षीय एयरोनॉटिक इंजीनियर अली अख्तर को पहले पदावनत एवं बाद में इसलिए बर्खास्त कर दिया गया कि वह सुन्नी से अहमदिया पंथ में शामिल हो गया था। अहमदिया समुदाय के निदेशक कमर सुलेमान ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहते हैं ''संविधान के अनुसार अहमदिया मुसलमान नहीं, जब कि वे कुरान-हदीस सभी मानते हैं। उन्हें सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद को पैगंबर मानने की सजा मिल रही है। मुल्क का दुश्मन बताकर उनके बच्चे गायब किए जा रहे हैं।'' 42 वर्षीय शाजिया शमून के तीन बेटों एवं भतीजे को कुछ दिनों पहले ऐसे गायब किया गया कि उनका आज तक पता नहीं चल पाया है। अहमदियाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार से संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारवादी भी चिंतित हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वे पाकिस्तान सरकार से ठोस कदम उठाने की सिफारिश भी कर चुके हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान : सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ रही हैं (फाइल चित्र)

तार-तार होता इस्लामी उम्मा!

इस्लामी जगत में आज दो फाड़ की स्थिति है। नेतृत्व के कई दावेदार हैं। इस भीड़ में शामिल ताकतें दुनिया को अपनी तरह से ढालने की कोशिश कर रही हैं। नतीजतन, पूरा मुस्लिम जगत विरोधाभासी हो गया है

■ अनिल त्रिगुणायत

इस्लामी उम्मा एक बार फिर से मुस्लिमों के पारम्परिक नेताओं और उनकी जगह लेने की कोशिश में लगी नई ताकतों के बीच होड़ में फंस गया है। कट्टरपंथी और राजनीतिक इस्लाम के विकास के साथ भू-राजनीतिक कारणों ने, खासतौर पर मध्य-पूर्व में, राजनीतिक संदर्भों में मजहब के दखल के नए दबाव बिंदु और कड़े मुकाबले की स्थितियां पैदा कर दी हैं। सुन्नी-शिया संदर्भ में सऊदी अरब और ईरान की लंबे समय से चली आ रही मजहबी रस्साकशी अपने आप में अनोखी है। यह इस क्षेत्र में राजनीतिक-मजहबी दबदबा कायम करने के विवाद का प्रमुख कारण है। यमन में 'हाउदी' समर्थक, लेबनान में 'हिजबुल्ला' और गाजा में 'हमास' के अलावा बड़ी संख्या में मिलिशिया और आतंकवादी समूहों की निष्ठा ईरान के प्रति है। इसलिए यमन, सीरिया, लेबनान और इराक सऊदी अरब और ईरान के बीच प्रत्यक्ष और छद्म संघर्ष के मैदान बनते हुए क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं। अनिच्छा और तिरस्कार के बावजूद इस खेल में बड़ी ताकतें भी अलग-अलग समूहों को प्रश्रय दे रही हैं। ये देश हथियारों की बिक्री के लिहाज से बढ़िया ग्राहक बन गए हैं और वहां चल रहा संघर्ष पश्चिम के लिए इसलिए भी सुविधानजक है क्योंकि इससे उनके संरक्षण वाले यह इज्राएल की सुरक्षा मजबूत होती है। पश्चिम यहां रणनीतिक हितों के आधार पर पक्ष भी बदलता रहा है।

देखा जाए तो, बीते सात दशकों से फिलिस्तीन के संदर्भ में इज्राएल और इस्लामी दुनिया के बीच शायद इससे भी ज्यादा कट्टर प्रतिद्वंद्विता लगातार बनी रही है हालांकि, अरब में राजशाही और तानाशाही शासनों के खिलाफ लोकतंत्रवादी आंदोलनों के उभार (अरब स्प्रिंग) के बाद से फिलिस्तीनी राज्य के मुद्दे के हाशिए पर पहुंचने और उस ओर खिंचाव घटने के बाद से, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे प्रमुख अरबी देशों ने एक दशक से चल रही गुपचुप वार्ताओं और अमेरिकी मध्यस्थता के परिणामस्वरूप इज्राएल के साथ संबंधों को सामान्य करने का फैसला किया है। इससे क्षेत्र में प्रभुत्व के जटिल संघर्ष के स्वरूप में बदलाव आएगा। इसी बीच,

अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता से इज्राएल और यूएई के बीच समझौते से पूरी तरह सामान्य संबंधों तक पहुंचना आजादी के लिए संघर्षरत फिलिस्तीन की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। इज्राएल के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते, क्योंकि अभी भी फिलिस्तीनी नागरिक उसके कब्जे में हैं।

- एस.क्यू.आर. इलियास
सदस्य, कार्यकारी समिति मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

अमेरिका-चीन संघर्ष और जेसीपीओए नाभिकीय समझौते से अमेरिका के हटने के अलावा राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा कई देशों के खिलाफ प्रतिबंधों के लगातार इस्तेमाल ने जवाबी तर्कों और शक्ति संघर्ष के विकास के लिए जरूरी और पर्याप्त परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। ऐसे में चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के बीच एक ढीले–ढाले गठजोड़ को उभरते देखा जा सकता है।

ध्वस्त होता 'मुस्लिम ब्रदरहुड'

2017 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र द्वारा कतर की नाकाबंदी के परिणामस्वरूप, तुर्की को दोहा में अपना आधार स्थापित करने का मौका मिल गया था। 'मुस्लिम ब्रदरहुड' का समर्थन करने से ये दोनों देश सऊदी नेतृत्व वाली चौकड़ी के साथ सीधे टकराव की स्थिति में पहुंच गए हैं। तुर्की अपनी सैन्य शक्ति के साथ सीरिया, इराक, लीबिया से पूर्वी भूमध्य सागर तक हस्तक्षेप करते हुए बांहें फड़का रहा है। राष्ट्रपति एर्दोगान न केवल 'ओटोमनी साम्राज्य' का सपना संजोए हैं, बल्कि 'मुस्लिम ब्रदरहुड' के प्रति गहरे अपनत्व के साथ इस्लामी दुनिया का नेतृत्व हासिल करना चाहते हैं।

इस्लामी जगत में नेतृत्व के कई दावेदार हैं। इस भीड़ में शामिल ताकतें दुनिया को अपनी तरह से ढालने की कोशिश कर रही हैं। परिणामस्वरूप पूरा संदर्भ विरोधाभासी हो गया है। इस प्रतियोगिता में मस्जिदें और मजहब दिखावटी नेताओं को वैधता प्रदान करते हैं। सऊदी अरब के शाह दो मस्जिदों के संरक्षक हैं; ईरानी मजहबी नेता के पास शिया समुदाय में अपने प्रभाव का बड़ा दायरा है; और, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय तो खुद को सीधे पैगंबर के वंश से जोड़ते हुए 'सबसे पाक मस्जिदों' में तीसरे नंबर की अल अक्सा मस्जिद के साथ ही यरुशलम में कई चर्चों के संरक्षक हैं। 'मुस्लिम ब्रदरहुड' के संरक्षक और समर्थक एर्दोगन ने हाल ही में एक पुराने चर्च हागिया सोफिया और कुछ अन्य को मस्जिदों में बदलते हुए नए प्रतीकों का सृजन भी किया है।

इन प्रतीकों से वंचित संयुक्त अरब अमीरात ने उच्च नैतिक आधार का आश्रय लेते हुए खुद को मजहबी तथा अन्य प्रकार की 'सहिष्णुता' का संरक्षक बना लिया है। ये सभी देश अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार और रक्षा के लिए सैन्य शक्ति का दिखावा करने में भी संकोच नहीं करेंगे। स्वाभाविक-सी बात है कि इन अलग-अलग धाराओं के प्रवाहों का विलय होकर कोई संगम नहीं बनेगा, बल्कि उनमें आपस में संघर्ष पैदा होता रहेगा, विशेषतः इस क्षेत्र में, जहां नेतृत्व को अक्सर चुनौतियां मिलती रही हैं। राष्ट्रपति एर्दोगन के नेतृत्व में तुर्की मध्य-पूर्व और भूमध्यसागरीय क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप करने में तेज रहा है। राजनीतिक इस्लाम राजशाहियों के लिए एक प्रकार का खतरा बन गया है। भले तुर्की की अपनी समस्याएं हों, लेकिन नाटो का सदस्य देश होने के नाते अन्य यूरोपीय और पश्चिमी शक्तियां उसकी भूमिका और हस्तक्षेप के तौर-तरीकों की कड़ाई से परख कर रही हैं। इस जांच-परख से निबटने के लिए तुर्की ने इन पश्चिमी देशों के आंतरिक मतभेदों के बीच से रास्ता निकालने की कोशिश की है। दरअसल, भू-अर्थशास्त्र और मजहबी दबदबे की तलाश का घालमेल सिर पर चढ़ने वाला नशा है।

पाकिस्तान अब तक सऊदी अरब और खाड़ी के देशों में अपने मददगारों के साथ ही, ईरान और तुर्की के बीच भी इस्लामी कार्ड खेलने में सफल रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान खूंखार अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन समेत आतंकवादी समूहों का ठिकाना रहा है, तो भी उसने तालिबान कार्ड के सहारे खुद को अमेरिका और रूस के लिए भी अपरिहार्य बनाए रखने की कोशिश की है। भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के राज्य-प्रायोजित सीमापार आतंकवाद और पाखंड के बारे में दुनिया दशकों से जानती रही है। लेकिन, लगता है कि पाकिस्तान की झांसेबाजी अब और नहीं चलेगी, क्योंकि अब इस्लामाबाद पूरी तरह से चीन की गोद में बैठ गया है। चीन का प्रभाव और उस पर उसकी निर्भरता इतनी गहरी है कि शायद ही किसी इस्लामिक देश ने सिंक्यांग में उइगर मुस्लिमों की दुर्दशा की खुलकर आलोचना की हो। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्लामी सहयोग संगठन का सदा दुरुपयोग किया है और उस मंच पर हाल तक जम्मू-कश्मीर में मुसलमानों की कथित दुर्दशा की निंदा और आलोचना करता रहा है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, क्योंकि इस्लामी सहयोग संगठन के प्रमुख देशों को पाकिस्तान के नापाक षड्यंत्रों का पता चलने लगा है। भारत को मार्च 2019 में अबू धाबी में इस्लामी सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में 'सम्मानित अतिथि' के रूप में आमंत्रित किया गया था। तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने निमंत्रण को स्वीकार किया था। इस्लामी सहयोग संगठन की 46वीं बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहन का निमंत्रण स्वीकार करते हुए विदेश मंत्रालय ने जो वक्तव्य जारी किया था उसमें संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय संबंधों को स्पष्टता से रेखांकित किया गया था। उसमें कहा

गया था, ''हम इस निमंत्रण को संयुक्त अरब अमीरात के साथ तेजी से बढ़ते अपने नजदीकी द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सच्ची बहुपक्षीय साझेदारी बनाने की प्रबुद्ध नेतृत्व की इच्छा के रूप में देखते हैं। हम इस निमंत्रण को संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में मील के पत्थर के रूप में देखते हैं। हम इस आमंत्रण को भारत में 18.5 करोड़ मुस्लिमों की मौजूदगी और इसके बहुलतावादी लोकाचार में उनके योगदान और इस्लामी दुनिया में भारत के योगदान की स्वागतयोग्य स्वीकृति के रूप में भी देखते हैं।''

भारत के प्रति बदला नजरिया

भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन को पहले ही चेताया था कि उसे भारत में जम्मू-कश्मीर तथा मुसलमानों की दशा समेत भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। पाकिस्तान के इशारे पर 1990 के दशक से इस्लामी सहयोग संगठन साल-दर-साल भारत के खिलाफ अपमानजनक बयान देता रहा था, जिसे भारत लगातार निराधार और निरर्थक वक्तव्य के रूप में सिरे से खारिज करता रहा था। इससे भारत के बारे में इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नजरिए में सिरे से आए बदलाव को देखा जा सकता है। इन देशों ने बातचीत में भले परम्परागत तरीके से पुराने मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन अबू धाबी घोषणापत्र में भारत के खिलाफ जाने वाले किसी भी विवादास्पद मुद्दे का उल्लेख नहीं किया। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि उसने मित्र देश भारत को उसके बड़े वैश्विक राजनीतिक कद के साथ-साथ उसकी दीर्घकालिक और गहरी सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विरासत और उसके महत्वपूर्ण इस्लामी घटकों के मद्देनजर सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। पुलवामा और बालाकोट घटनाक्रमों के साथ ही अनुच्छेद-370 को रद्द किए जाने के संदर्भ में खाड़ी के प्रमुख देशों की प्रतिक्रियाओं से साफ पता चलता है कि उन्होंने इसे स्पष्टतः भारत का आंतरिक मामला माना था।

इन सबसे क्षुब्ध पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व वाले इस्लामी सहयोग संगठन के मुकाबले तुर्की, मलेशिया और कतर के साथ एक वैकल्पिक इस्लामी मंच बनाने की कोशिश की। लेकिन यह प्रयास विफल हो गया है और आर्थिक रूप से परेशान पाकिस्तान अपने पुराने मददगारों, खासकर सऊदी अरब की नाराजगी का सामना कर रहा है जिन्होंने तमाम सहायता, अनुदान और ऋण सुविधाओं को वापस ले लिया है। इससे भारत को इस्लामी सहयोग संगठन देशों के साथ और अधिक घनिष्ठ जुड़ाव विकसित करने का नया आधार मिला है।

पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध लगातार और मजबूत हुए हैं। भारत की ऊर्जा और भौतिक सुरक्षा तथा प्रवासी कल्याण के लिहाज से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। खाड़ी के अधिकांश

बढ़ता भरोसा : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अबु धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जाएद (फाइल चित्र)

देश भारत को दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे सौम्य लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। उन्होंने यह भी महसूस किया है कि उग्र और चरमपंथी समूहों का समर्थन करने से उन्हीं का नुकसान होगा। आर्थिक मंदी, कोरोना महामारी का प्रभाव, बदलता वैश्विक शक्ति संतुलन और समग्र अनिश्चितता का सामना करते अरब जगत के लिए आंतरिक क्षमताओं तथा असीमित अवसरों से सम्पन्न भारत एक विश्वसनीय, रणनीतिक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी का अवसर प्रदान करता है।

भारत ने इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ उनकी वैचारिक या सांप्रदायिक कमजोरियों में उलझे बिना द्विपक्षीय संबंध रखने की नीति का पालन किया है। यह विदेश नीति की प्रमुख सफलता है क्योंकि तेजी से बदलते गठजोड़ों और शीतयुद्ध-2.0 की आशंकाओं के बीच भारत उनके आपसी टकरावों में शामिल होने की जहमत मोल नहीं ले सकता। हो सकता है कि भविष्य में ऐसी स्थितियां हों जब हमें निराशा और अनिच्छा के बावजूद पक्ष चुनने पड़ें। तब तक भारत द्विपक्षीय आदान-प्रदान और बहुपक्षीय जुड़ाव के माध्यम से संबंधों को प्रगाढ़ बनाना जारी रखेगा। यद्यपि, हमें वह सही संतुलन खोजने का काम जारी रखना होगा जिससे हमारे राष्ट्रीय और रणनीतिक हित बेहतर ढंग से पूरे हो सकें। कद और महत्वाकांक्षाएं बढ़ने के साथ जब तक भारत स्पष्ट रूप अभिव्यक्त उद्देश्यपरक मूल्यांकन की नीति का पालन करता रहेगा, उसे इस क्षेत्र में संघर्ष के पीछे मजहबी कारणों की मौजूदगी के बावजूद, शांति के ईमानदार मध्यस्थ होने के साथ ही, लाभदायक रिश्तों के लिए अपेक्षित विश्वसनीयता प्राप्त होती रहेगी।

(लेखक जॉर्डन, लीबिया और माल्टा में भारत के राजदूत रहे हैं)

चीनी नागरिक 'दामाद' बन कर पाकिस्तानी लड़कियों को अपने यहां व्यापार मंडी में बेचते हैं, लेकिन चीन इससे इनकार करता है (फाइल चित्र)

चीनी देह-व्यापार में पाकिस्तानी बेटियां

चीनी नागरिक पहले पाकिस्तानी लड़कियों से निकाह करते हैं, फिर उनका यौन शोषण करने के बाद उन्हें अपने यहां देह-व्यापार में बेच देते हैं। पाकिस्तानी बिचौलियों की मदद से इस काम के लिए उन्हें एक लड़की का सौदा करने पर 4-5 लाख रुपये मिलते हैं। ऐसी अनेक घटनाओं से पर्दा उठाती रपट की पहली किस्त।

■ मलिक असगर हाशमी

चीन के प्रति पाकिस्तान की अंधभक्ति का अंजाम दिखने लगा है। विशेष महत्व मिलने का अनुचित लाभ उठाते हुए चीनी अब 'दामाद' बनकर पहले पाकिस्तानी बहू-बेटियों की इज्जत लूटते हैं, फिर निकाह का ढोंग कर उन्हें चीन की देह मंडी में बेच देते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था 'ह्यूमन राइट्स वॉच' की सोफिया रिचर्डसन की रिपोर्ट 'पाकिस्तान शुड हीड अलार्म बेल्स ओवर ब्राइड ट्रैफिकिंग' में कहा गया है कि चीन के लोग 1978 से यह घृणित काम कर रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में इनका जोर बढ़ा है। ह्यूमन राइट वॉच ने चीनियों के इस कुकृत्य को यौन गुलामी की संज्ञा दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी गिरोह पहले पाकिस्तानी ईसाई लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। बाद में हिंदू, मुसलमान सहित सभी मत-पंथ की लड़कियां चीनी चकलाघरों में पहुंचाई जाने लगीं। इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान सरकार की खूब फजीहत हो रही है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी एफआईए का कहना है कि पाकिस्तानी लड़कियों से 'निकाह' कर उन्हें चीनी वेश्यालय तक पहुंचाने का गोरखधंधा पिछले वर्ष से शुरू हुआ है। इसका पता लगते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि, एफआईए की 2018 की रिपोर्ट को देखें तो तस्करी एवं मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 112 शातिर अपराधियों में एक भी चीनी नहीं है। इनमें एक ईसाई युवक है, शेष सभी मुस्लिम हैं। जाहिर है, चीनियों की इस घिनौनी हरकत पर पाकिस्तान परदा डालता रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर सवाल उठाता रहा है कि यदि एक साल से चीनी गिरोह सक्रिय है तो उनके खिलाफ

कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? यदि गिरोह की करतूतों का अब खुलासा हो रहा है तो आंतरिक सुरक्षा, सीमा नियंत्रण, आपराधिक जांच, आतंकवाद, विदेशी जासूसी, फासीवाद एवं तस्करी पर नजर रखने वाली एफआईए क्या कर रही थी?

दरअसल, पाकिस्तान सरकार ने जान-बूझकर आंखें मूंद रखी थीं, क्योंकि अब तक ईसाई लड़कियां ही चीनियों के निशाने पर थीं। अब गिरोह का दायरा बहुत बढ़ गया है। तमाम अल्पसंख्यक लड़कियों के साथ मुस्लिम बालाएं भी चीन की देह मंडी में पहुंचाई जा रही हैं। गिरोह के खिलाफ अभियान चलाने पर इस मामले में कई चीनी नागरिक और पाकिस्तानी बिचौलिए पकड़े गए। इनके चंगुल से कई लड़कियां भी छुड़ाई गईं। पाकिस्तान के कई न्यूज चैनलों ने भी ऐसे गिरोह का खुलासा किया है। बताया जाता है कि कई चर्चों के पादरी एवं मौलवी भी इसमें संलिप्त हैं। पाकिस्तानी दलालों को पादरियों एवं मौलवियों के जरिये एक लड़की का सौदा कराने पर चार से पांच लाख रुपये मिलते हैं। पाकिस्तानी संघीय जांच एजेंसी ने हाल में इस बारे में एक रिपोर्ट पाकिस्तान में चीन के राजदूत को सौंपी थी, लेकिन चीन ने इसे पाकिस्तानी मीडिया की खुराफात बताकर खारिज कर दिया था। एफआईए ने 20 चीनी एवं पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी से संबंधित जो रिपोर्ट उसे सौंपी थी, उसमें कुछ चीनियों पर अवैध दस्तावेज तैयार करने और चीन में पाकिस्तानी लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराने के आरोप दर्ज थे। यह गिरफ्तारी लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद एवं इस्लामाबाद में दिखाई गई थीं। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने इस रिपोर्ट को नकारते हुए कहा कि जांच करने पर पाकिस्तानी लड़कियों को चीन में बेचने के कोई सबूत नहीं मिले। चीन के लोक सुरक्षा मंत्रालय का कहना है कि यदि पाकिस्तान इस बारे में जांच करना चाहे तो उसका हर तरह से सहयोग किया जाएगा। साथ ही, चीन ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी मीडिया का एक वर्ग भ्रामक खबरें छापकर चीन-पाकिस्तान रिश्तों में दरार पैदा करना चाहता है। यह अलग बात है कि इसको लेकर विवाद बढ़ता देख चीनी दूतावास ने 90 पाकिस्तानी दुल्हनों के वीजा पर रोक लगा दी थी। पाकिस्तान में चीन के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन लिजियान झाओ ने बताया कि दूतावास को 140 चीनी नागरिकों की ओर से पाकिस्तानी दुल्हनों के वीजा के लिए आवेदन मिले थे, जिनमें से 50 को मंजूरी दी गई, जबकि बाकी को रद्द कर दिया गया।

(लेखक पाकिस्तानी मामलों के जानकार हैं)

आदिजाति विकास विभाग, गुजरात सरकार गांधीनगर

गुजरात में उमरगाम से लेकर अम्बाजी तक पूर्व पट्टी के आदिजाति विस्तार में कुल 53 तालुकाओं का समावेश होता है जिसमें अनुसूचित जनजाति की वस्ती 89.17 लाख है जिसके ऊपर गुजरात सरकार ने आदि जाति के सर्वांगी कल्याण कार्यक्रम वनबधु कल्याण के अंतर्गत निम्न लिखित मुद्दों पर कार्य 1,00,954 करोड़ रु. का आवंटन किया गया

सर्वांगी विकास को समर्पित मुख्यमंत्रीश्री के 10 मुद्दों का कार्यक्रम (वनबधु कल्याण येजना):-

- 5 लाख कुटुम्बो के लिए रोजगार लक्षी कार्यक्रम
- शिक्षण की गुणवता और उच्च अभ्यास पर भार
- आदिजाति विस्तार का आर्थिक विकास तीव्रता से हो
- सभी के लिए आरोग्य
- बिजली की सार्वत्रिक उपलब्धता
- सभी के लिए घर
- पीने के लिए पानी
- सिंचाई
- बारमासी रास्ते
- शहरी विकास

गुजरात के बहुलक आदिजाति विस्तार 14 प्रायोजन विस्तार में विस्तारित है

1. पालनपुर-बनासकांठा
2. खेडब्रह्मा-सावरकांठा
3. दाहोद -दाहोद
4. गोधरा -पंचमहल
5. छोटा उदयपुर-छोटा उदयपुर
6. राजपीपला-नर्मदा
7. भरूच-भरूच
8. मांडवी-सुरत
9. सोनगढ़-तापी
10. वांसदा-नवसारी
11. वलसाड-क्लसाड
12. आहवा-डांग
13. मोडासा-अरवल्ली
14. लुणावाडा-महिसागर

शुभेच्छक आदिजाति विकास विभाग

चलो चलें आस्था की डगर

देशाटन, तीर्थाटन जैसे शब्द खूब प्रचलित रहे हैं हमारी सभ्यता, संस्कृति में। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में अपनी धरती के एक से दूसरे कोने तक जाना पुण्य कार्य माना गया है। आदिशंकराचार्य ने चार धाम की स्थापना कर देश को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोया।कोरोना संक्रमण के इस दौर में विश्व पर्यटन दिवस पर, आइए चर्चा करें सांस्कृतिक पर्यटन से जुड़े स्थलों और सरकार के स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशों की

■ डॉ. संदीप कुलश्रेष्ठ

भारत को विश्व में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है जिसकी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। इसकी उदारता तथा समन्वयवादी गुणों ने अन्य संस्कृतियों को आत्मसात तो किया परंतु अपने मूल को भी संरक्षित किया। भारतीय सनातन परंपरा में यात्राओं का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है जिसमें एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा; भगवान श्री राम की श्रीलंका तक वनगमन यात्रा; बुद्ध, महावीर, आदि शंकराचार्य से लेकर गुरुनानक देव सरीखे महापुरुषों ने राष्ट्र को यात्राओं के माध्यम से एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इतिहास साक्षी है कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालयों ने विश्व के प्रत्येक कोने से छात्रों, शोधकर्ताओं व आचार्यों को भारत आने को प्रेरित किया। शंकराचार्य द्वारा चार धाम की स्थापना के पीछे कदाचित राष्ट्रीय एकता व

भारत के जन-जन की आस्था का केन्द्र है वाराणसी का गंगा तट

ओरछा में बेतवा नदी के किनारे बनीं प्राचीन छतरियां, पास ही रामराजा का भव्य मंदिर है

संस्कृतियों के आदान-प्रदान को धर्म के साथ जोड़कर अध्यात्म के एक नए युग की शुरुआत करने का लक्ष्य भी रहा होगा। भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भवः तथा वसुधैव कुटुंबकम् के साथ समस्त ब्रह्मांड के कल्याण में विश्वास रखती है।

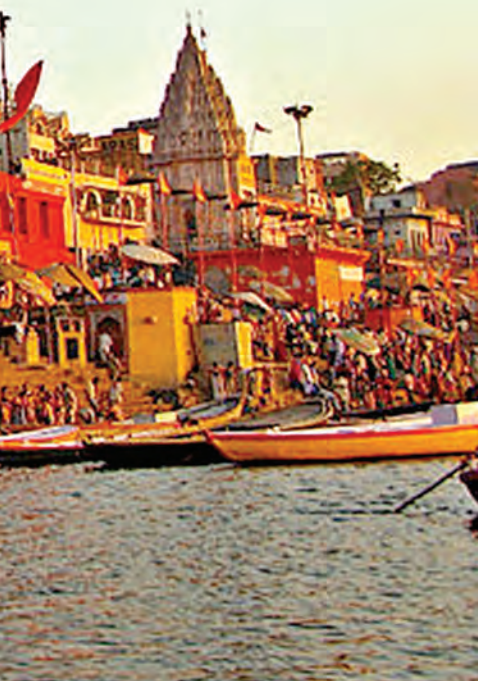

सांस्कृतिक पर्यटन की ऐतिहासिकता

इस परिकल्पना के साथ हमारे यहां सांस्कृतिक विरासत व नैसर्गिक पर्यटन तेजी से उभरेगा। भारत में पर्यटन की पृष्ठभूमि ईसा पूर्व 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, सनातन व वैदिक परंपराओं में उसे तीर्थाटन व देशाटन भी कहा गया है। इसका व्यवस्थित उल्लेख वेदों, उपनिषदों व अन्य धार्मिक ग्रंथों में कई प्रसंगों के माध्यम से मिलता है जिनमें भागवत्पुराण, त्रिपुरा रहस्य और अद्वैत वेदांत आदि प्रमुख हैं। महाभारत, रामचरितमानस आदि ग्रंथों में भी यातायात व संदेश वाहन के विभिन्न तरीकों का प्रामाणिक वर्णन मिलता है जहां तीर्थाटन, वन विहार, नौका विहार, पुष्पक विमान (चार्टर्ड फ्लाइट) आदि शब्द, जो कि पर्यटन एवं यात्रा से जुड़े हैं, का उल्लेख मिलता है। चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग व 51 शक्तिपीठों की यात्रा भारतीय दर्शन में अपनी अहम भूमिका रखती है। कदाचित भविष्यवेत्ता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ाने की बात रखी थी व कहा कि हमें दूसरे राज्यों व दूसरे देशों के लोगों का स्वागत करना चाहिए। भारत में प्रत्येक राज्य व पंथ में अलग-अलग उत्सव आयोजित किए जाते हैं, चाहे वह होली हो, दीवाली, पिहू या पोंगल हो।

आस्था से नाता

विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटक भीड़-भाड़ से दूर ऐसे वैकल्पिक स्थलों की ओर जाना चाहता है जिनमें सांस्कृतिक, प्राकृतिक आकर्षण हो। वह देखना चाहता है हम्पी का विरुपाक्ष मंदिर, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, कुंभकोनम का अरिवत्सवारा, केरल स्थित गुरुवायुर मंदिर और ओरछा का रामराजा मंदिर। सुदूर उत्तर-पूर्वी राज्य अपनी नैसर्गिक सुंदरता के कारण पर्यटकों को और अधिक लुभाएंगे। यहां गुवाहाटी विख्यात स्थित कामाख्या मंदिर, मणिपुर के गोविंद जी मंदिर, अरुणाचल का मलिनिथान मंदिर व त्रिपुरा स्थित त्रिपुरेश्वरी मंदिर की अपनी एक अलग ही छवि व महत्ता है।

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' एक ऐसा

केरल का गुरुवायूर मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता रहा है हर साल

अभियान है जो कोविड-19 से पहले शुरू किया गया था और आज के चुनौतीपूर्ण परिवेश में पूरी तरह खरा उतर रहा है। एक राज्य के पर्यटकों के दूसरे राज्य में जाने से रोजगार व अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो आत्मनिर्भर भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे सामाजिक व सांस्कृतिक सद्भाव तो बढ़ेगा ही, साथ ही 'अनेकता में एकता, भारत की विशेषता' उक्ति भी चरितार्थ होगी।

सेवा क्षेत्र को मिलेगी पहचान

सरकार द्वारा घोषित अतिरिक्त संपाश्रविक मुक्त तरलता समर्थन प्राप्त करने के लिए देश में यात्रा पर्यटन और आतिथ्य व्यवसायों के लाभ के लिए काम करेंगे। बैंकों और एनबीएफसी के माध्यम से एमएसएमई व्यवसाय के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की संपाश्रविक मुक्त स्वचालित ट्रेनों की घोषणा सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने में दीर्घकालीन रूप से सहायक साबित होगी। वर्तमान में जहां कोविड-19 के कारण एकाकीपन, अवसाद, पारिवारिक व मानसिक तनाव तथा अन्य पारिवारिक समस्याएं अपने चरम पर हैं, उसे दूर करने में पर्यटन यंत्र का कार्य करेगा। वास्तव में पर्यटन का मुख्य उद्देश्य ही आनंद व चित्त को प्रसन्न रखना है। आज के समय में भौतिक प्रसन्नता व संपन्नता के स्थान पर मानसिक व भावनात्मक प्रसन्नता व संपन्नता होना अत्यंत आवश्यक है। लॉकडाउन में घर में रहते हुए भारतीयों ने इस बात को अच्छी तरह महसूस किया है। अमेरिका, इटली जैसे भौतिक रूप से संपन्न राष्ट्र इस बात को महसूस करने पर मजबूर हैं। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति मानव को आत्मिक शांति प्रदान करती है और यही कारण है कि देश में आने वाले विदेशी वृंदावन, मथुरा, बनारस और अयोध्या की गलियों में शान्ति को खोजते हैं, तो ऋषिकेश में योग और केरल में आयुर्वेदिक पर्यटन से लाभान्वित होने के इच्छुक रहते हैं।

ग्रामीण पर्यटन का अवदान

27 सितंबर, 2020 का दिन विश्व पर्यटन दिवस है। भारत में 65 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इस क्षेत्र के पास शहरी क्षेत्र की 35 प्रतिशत आबादी को देने के लिए बहुत कुछ है जिसमें कृषि, प्रकृति, खाद्य एवं भोजन, संस्कृति एवं साहसिक पर्यटन प्रमुख हैं। ग्रामीण समुदाय की विशिष्ट परंपराओं, रीति-रिवाजों को सहेज व संरक्षित कर आज के समयानुसार

नदियों से जुड़े तीर्थ

हिन्दुस्थान एक समय इतना बड़ा और एकजुट देश नहीं था। बहुत राजा थे यहां। बहुत झंडे थे उनके। हरेक का अपना-अपना सिक्का चलता था। फिर भी अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक यह भरतखंड ही कहलाता था। पूरे हिस्से में एक ही तरह की अर्थव्यवस्था चलती थी। तीर्थ हम सबको बांधे हुए थे। राज्य अलग-अलग थे मगर तीर्थ सबके लिए एक थे। आम मान्यता थी कि हर आदमी को ये तीर्थ करने ही हैं। इतने धाम घूमना ही है। वे सबके लिए एक थे और सबके लिए छूट थी। तीर्थों के बल पर हम सब कहीं न कहीं एक होते रहे हैं। तीर्थ किसको कहते हैं? तीर्थ वह क्षेत्र माना जाता है जहां कोई भी नदी उत्तरवाहिनी हो जाती है। हमारी सारी नदियां पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण बहती हैं। जहां भी कोई नदी उत्तरवाहिनी होती है वही क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है। गंगा काशी में उत्तरवाहिनी है, वह तीर्थ क्षेत्र है। और कहीं वह उत्तरवाहिनी नहीं है। गंगा का पूरा किनारा तीर्थ क्षेत्र नहीं माना जाता। गोदावरी का पूरा किनारा तीर्थ क्षेत्र नहीं माना जाता। जहां संगम होते हैं वे भी तीर्थ माने जाते हैं। हम गंगा गोदावरी को मिलाने की बात करते हैं, इससे हमारा सारा तीर्थ ही खत्म हो जाएगा। हजारों सालों से हम मिलकर रहे तो इन्हीं तीर्थों की वजह से। नहीं तो यहां काशी जाने की किसको पड़ी है? या किसी को काशी से रामेश्वरम जाने की क्या पड़ी होती? जब लोग रामेश्वरम से काशी जाते हैं तो यहां की रेत लेकर जाते हैं और जब काशी से लौटते हैं, तो गंगा जल लेकर रामेश्वरम में अर्पित करना होता है। हम तीर्थों के बल पर एक रहे हैं। देश और राष्ट्र सब अलग-अलग रहे मगर तीर्थों के कारण हम एक रहे। तीर्थों की वजह से अर्थव्यवस्था एक रही। पुराणों में नदियां से जुड़े तीर्थों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

रविन्द्र शर्मा गुरुजी

विकसित करने के साथ महिलाओं व युवाओं को रोजगार प्रदान कर आर्थिक विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकता है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण पर्यटन का विकास देश को एक नई राह प्रदान कर सकता है, जैसे काश्तकारी, शिल्पकारी, पच्चीकारी, बुनाई-कढ़ाई, मिट्टी व लकड़ी के खिलौने, बर्तन आदि का क्रय पर्यटकों की यात्रा को और भी यादगार बना सकता है। पर्यटक जानना चाहता है ग्रामीण गीत, संगीत, नृत्य, पाक कला, खेल व मनोरंजन को। इस लिए वह राजस्थान के जैसलमेर एवं हिमाचल के सुदूर क्षेत्रों की सैर करना चाहता है। आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीणों को इन योजनाओं का सीधा लाभ मिले और उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। आवश्यक हो तो ग्राम पंचायतों को भी योजना निर्माण में शामिल किया जाए। गुजरात का होडका, सिक्किम का लोचन, मेघालय का मावलांग, असम का माजुली एवं राजस्थान में समौद ग्रामीण पर्यटन के सजीव उदाहरण हैं जिनकी सैर करने के बाद पर्यटक आनंदित एवं भाव विभोर हो जाता है।

संक्रमण काल है यह

विगत कुछ माह में कोरोना वायरस के कारण हुए वैश्विक परिवर्तन से पर्यटन जगत भी अछूता नहीं रहा है। पर्यटन हितधारकों ने कभी इस अभूतपूर्व स्थिति के बारे में सोचा तक नहीं था। विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा जारी चौंकाने वाले आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि 180 मिलियन अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आवागमन पर कोविड-19 का दुष्प्रभाव पड़ा है, पर्यटन उद्योग को 195 बिलियन डॉलर के निर्यात राजस्व की हानि का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लगभग 120 मिलियन प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। संभवत ऐसी विपत्ति का सामना पर्यटन जगत ने पहली बार किया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में तो यह स्थिति और भी भयावह है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार पर्यटन का भारत के घरेलू सकल उत्पाद में योगदान 9 प्रतिशत से अधिक था लेकिन आज निराशा का वातावरण बना है।

पर्यटन समुदाय को संभवतः विश्व का सबसे बड़ा समुदाय माना जाता है जिसमें छोटे दुकानदार, शिल्पकार, कलाकार, टूरिस्ट गाइड, ऑटो रिक्शा वाले से लेकर बड़े उद्यम, जैसे नागरिक विमानन, होटल उद्योग, क्रूज कंपनियां आदि आते हैं। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, रोजगार, विदेशी मुद्रा विनिमय व सांस्कृतिक-सामाजिक सहिष्णुता हेतु पर्यटन एक महत्वपूर्ण घटक की भूमिका का निर्वाह करता है। पर्यटन के गुणात्मक प्रभाव के कारण सरकारें भी इसकी महत्ता को नजरअंदाज नहीं कर पातीं हैं।

भारत में यह अजीब विडंबना है कि इस पर्यटन रूपी पिरामिड का निचला हिस्सा लघु उद्यमियों के द्वारा प्रमुखता से मजबूती प्राप्त करता है। भारत में पर्यटन

के असंगठित क्षेत्र के 75 प्रतिशत से अधिक निचले पायदान पर कार्यरत लोगों की मासिक आय 15000 रु. से भी कम है। कोरोना काल में इसका भविष्य भी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे विषम समय में इसकी उत्तरजीविता व पुनरुत्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आवश्यकता इस बात की है कि इन सभी पर्यटन हितधारकों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा और उनमें परस्पर विश्वास और सद्भावना का माहौल बनाना होगा। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं जिनमें पर्यटन मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह व श्रम मंत्रालय प्रमुख हैं। विशेष रूप से पर्यटन मंत्रालय ने ऑनलाइन माध्यम से हितधारकों के लिए ठोस कदम उठाए हैं; नागरिक विमानन मंत्रालय ने बबल फ्लाइट्स व वंदे भारत मिशन के माध्यम से कुछ देशों से संपर्क बनाया हुआ है। पर ज्यादातर राष्ट्रों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं अभी पर्यटकों के लिए बंद हैं।

2020-21 में कई नवीन परिदृश्य उभर कर सामने आएंगे, जिनमें सर्व प्रमुख घरेलू पर्यटन है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधित आवागमन के कारण अब घरेलू पर्यटन अपनी महती भूमिका निभाएगा, इसलिए राज्य सरकारें अपने पर्यटन विभाग को इस हेतु चुस्त-दुरुस्त करने में लगी हैं। यह अजीब संयोग है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कदाचित अपनी दूरदृष्टि के कारण भारी कठिनाइयों को चिन्हित कर लिया था और गत वर्ष ही मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के नागरिकों से आग्रह किया था कि वे अपनी छुट्टियां देश के अंदर ही व्यतीत कर घरेलू पर्यटन को बढ़ायें। वे देश के 7 सर्वश्रेष्ठ स्थानों को चयनित कर अपने अनुभव व फोटो साझा करें। और सुखद संयोग देखिए आज तो विश्व पर्यटन संगठन इसी बात को दोहरा रहा है।

नए काल के नए चलन

पर्यटन व्यवसायियों को पर्यटकों की चिति को समझना होगा और अपनी सेवाओं और उत्पादों को नए कलेवर में ढालकर

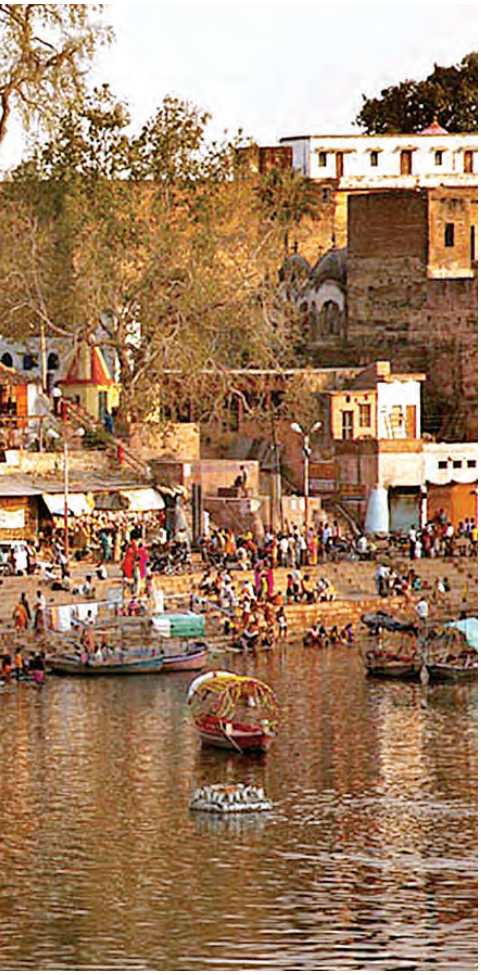

मंदाकिनी नदी के किनारे रमणीक चित्रकूट धाम

भगवान श्रीराम के वनवास से जुड़े प्रमुख स्थल

श्रृंगवेरपुर	लखनऊ रोड पर, प्रयागराज के पास
तमसा नदी	वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित
प्रयागराज	उत्तर प्रदेश (भारद्वाज मुनि से वातार्लाप)
महर्षि वाल्मीकि आश्रम	मध्य प्रदेश में स्थित
चित्रकूट	सतना, मध्य प्रदेश में
पंचवटी	नासिक, महाराष्ट्र में
दंडकारण्य	पंचवटी के पास
शबरी	छत्तीसगढ़ में
किष्किंधा	तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक राज्य में
पंपापुर	किष्किंधा के पास
रामेश्वरम	तमिलनाडु में
श्रीरामसेतु	रामेश्वरम और श्रीलंका के मध्य

पर्यटकों को संतुष्ट करने के प्रयास करने होंगे। विश्व पर्यटन संगठन ने कोरोना काल में विश्वास को पर्यटन की नई मुद्रा बताया है अतः व्यवसायों को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। लिहाजा पर्यटकों को ऐसी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाएं जिनसे प्रदाताओं व पर्यटकों के मध्य विश्वास कायम हो सके व पर्यटक घर से बाहर निकलकर यात्रा करने हेतु बिना डरे आतुर हो सके। आज का पर्यटक अपने शहर के आसपास भीड़ से दूर अपने परिवार के साथ अपने वाहन से जाने की चाहत रखता है व सप्ताहांत पर्यटन को अपनाना चाहता है। होटल में सुरक्षा व स्वास्थ्य के कारण से वह 'होमस्टे' को भी प्राथमिकता देने लगा है। खाद्य एवं पेय पदार्थों के सेवन में भी वह प्रतिरोधक क्षमता वर्धक को प्राथमिकता दे रहा है।

कोविड-19 ने पर्यटन में नए नियमों, प्रोटोकॉल व मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) को भी जन्म दिया है। पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया मार्केटिंग मल्टी स्किलिंग, अपस्किलिंग, रिस्किलिंग जैसी जरूरतों को आत्मसात करना होगा, पर्यटकों में विश्वास जगाना होगा तभी वे व्यवसायी के बताए पर्यटन स्थल होटल व परिवहन के साधनों का उपयोग करेंगे और टूर पैकेज क्रय करेंगे। व्यवसाया को इस हेतु पर्यटकों की सुरक्षा व स्वच्छता के प्रमाण भी दर्शाने होंगे जिनमें सैनिटाइजर, मास्किंग, फेस शील्ड का प्रयोग कर सामाजिक दूरी के नियमों का परिपालन आवश्यक है। पर्यटकों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हुए पैकेज में तनाव प्रबंधन आत्मविश्वास निर्माण, योग एवं ध्यान, स्वानुशासन आदि को भी शामिल करना होगा। पर्यटन सेवा प्रदाताओं को पर्यटक को बदली हुई मानसिकता के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। भारतीय संस्कृति व दर्शन इस वैश्विक चुनौती का सामना अपनी सुदृढ़ नींव के साथ करते हुए पर्यटन जगत को एक नई दिशा व दशा देने में सक्षम है।

(लेखक भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान के निदेशक रहे हैं)

'कल्पतरु' की छांव में पल रही जिंदगी

बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए सेवा भारती 'कल्पतरु स्वावलंबन योजना' चला रही है। इससे अब तक 250 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है

■ अरुण कुमार सिंह

वर्तमान महामारी का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर हुआ है, जो प्रतिदिन कमाते-खाते हैं। दिहाड़ी मजदूर हों या सड़क के किनारे कुछ बेचकर गुजारा करने वाले, इन लोगों का काम-धंधा बंद हो गया। ऐसे लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए गैर-सरकारी संस्था सेवा भारती ने 'कल्पतरु स्वावलंबन योजना' की शुरुआत की है। यह योजना उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में चल रही है। इसके अंतर्गत बेरोजगारों को ठेला गाड़ी और जरूरत के अनुसार कुछ पूंजी भी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 250 से अधिक बेरोजगारों ने मदद लेकर अपना काम शुरू किया है। ऐसे ही एक युवा हैं संजय मुंडा। ये सेवा भारती से सहायता लेकर रांची के कांके में इन दिनों चाट बेचने का काम कर रहे हैं। संजय कहते हैं, ''लॉकडाउन से पहले भाड़े पर ठेला गाड़ी लेकर चाट बेचने का काम करते थे। लॉकडाउन के दौरान हालत बहुत ही खराब हो गई। तीन महीने तक कोई काम नहीं करने से जेब में एक पैसा भी नहीं रहा। जब लॉकडाउन में कुछ ढील मिली तो काम करने का मन बनाया, लेकिन पूंजी के बिना काम शुरू नहीं कर पाया। इसी बीच किसी से जानकारी मिली कि सेवा भारती हम जैसे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में मदद कर रही है। एक दिन मैं भी सेवा भारती के कार्यालय में गया और वहां के पदाधिकारियों से बात की। इसके कुछ दिन बाद ही मुझे ठेला गाड़ी मिल गई। अब चाट बेचने का काम करता हूं। रोजाना करीब 400 रु. की कमाई हो जाती है। हालांकि यह कम है, पर परिवार का गुजारा हो जाता है।''

ऐसे ही कुर्रा उरांव भी सेवा भारती की सहायता से इन दिनों कुछ कमा पा रहे हैं। ये रांची जिले के रहने वाले हैं और कई वर्ष से रांची में रहकर निजी गाड़ी चलाते थे। लॉकडाउन लगते ही इनका काम बंद हो गया। तीन महीने तक इन्हें भी कोई काम नहीं मिला। उरांव कहते हैं, ''कुछ दिन पहले एक जानकार ने सेवा भारती के बारे में बताया और उन्होंने ही मुझे उसका पता भी दिया। एक हफ्ते के अंदर सेवा भारती से ठेला गाड़ी मिली। अब रांची के फिरायालाल चौक पर चाउमीन बेचकर परिवार पाल रहा हूं।''

रांची में सेवा भारती से मिले ठेले के जरिए चाट की दुकान चलाती एक महिला।

सेवा भारती के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने बताया, ''एक ठेले की कीमत 13,000 रु. पड़ती है। जिनको भी ठेला दिया जाता है उससे कहा जाता है कि जो भी काम करो, संभव हो तो हर सप्ताह सेवा भारती को 250 रु. वापस करो। लोग वापस भी कर रहे हैं। इसलिए सेवा भारती और जरूरतमंदों को मदद कर पा रही है।'' राष्ट्रीय सेवा भारती के संयोजक श्री गुरशरण प्रसाद कहते हैं, ''कल्पतरु योजना लोगों के सहयोग से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य है बेरोजगारों को रोजगार दिलाना।''

उम्मीद है कि 'कल्पतरु स्वावलंबन योजना' का विस्तार पूरे देश में होगा और हर हाथ को कुछ न कुछ काम मिलेगा। ■

लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय सेना की मजबूती से चीन की बेचैनी बढ़ी

चीन की आक्रामकता और बेचैनी क्यों?

भारत का लद्दाख क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करना चीन को हजम नहीं हो रहा, वह जिस क्षेत्र पर अपना हक मान कर वह बरसों से गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठा था, अब उसे वहां से चुनौती मिल रही

■ कर्नल शिवदान सिंह

दो सौ साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त,1947 को भारत आजाद हुआ, परंतु अंग्रेज जाते-जाते देश को उत्तर-पूर्व में अरुणाचल से लेकर पंजाब में अमृतसर तक अशांत तथा अनिश्चित सीमाएं दे गए। इस पूरे 200 साल की अवधि में अंग्रेज चीन के साथ सीमाओं का निर्धारण नहीं कर पाए। नतीजा, आजादी के कुछ समय बाद जब भारतवर्ष पूरी तरह से संभल भी नहीं पाया था कि चीन ने 1959 में चुपचाप भारत के अक्साई चिन के 48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कब्जा लिया।

आजादी से कुछ समय पहले अंग्रेजों ने मैकमोहन रेखा के जरिए भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण किया था, लेकिन चीन ने उसे कभी माना ही नहीं। अक्साई चिन पर चीन इसलिए कब्जा कर सका, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में लगने वाली सीमाएं ऊंचे-ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। उस समय भारत में न तो संचार व्यवस्था और न ही सड़कों की सुविधा थी। इसलिए भारतीय सुरक्षा बल प्रभावशाली तरीके से इन क्षेत्र की निगरानी नहीं कर सके। चीन ने इसी का फायदा उठाकर भारत के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसी तरह, वह अपनी विस्तारवादी नीति के तहत समूचे तिब्बत को हड़प गया। यही नहीं, नेपाल, भूटान, बर्मा और भारत, जहां भी उसे अवसर मिला, उसने अपना कब्जा जमाया। उसकी हड़प नीति के कारण पूरा दक्षिण एशिया अशांत है। आजादी के 75 साल बाद भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। उसने अपनी सारी सीमाओं तक सड़कें बना ली हैं। यहां तक कि उसने असंभव कहे जाने वाले पूर्वी लद्दाख के काराकोरम दर्रा तक लेह-श्योक-दौलत बेग ओल्डी तक 13,000 से 16,000 फुट की ऊंचाई तक 255 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क का निर्माण 2001 में शुरू हुआ था और 2020 में पूरा हो चुका है। यह सड़क हर मौसम में खुली रहेगी और इसके जरिए भारतीय सेना किसी भी समय लद्दाख के आखिरी छोर तक आसानी से पहुंच सकती है, जो चीन की सीमा से मिलता है। भारतीय सेना मई से इस क्षेत्र में इसी का अभ्यास कर रही है। लेकिन चीन इस सड़क को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है, क्योंकि भारत की यह सड़क पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाले उसके प्रसिद्ध कराकोरम हाईवे के निकट तक जाती है। इसके अलावा, इस सड़क के बन जाने के बाद भारत का दौलत बेग ओल्डी हवाईअड्डा, जो 16000 फुट की ऊंचाई पर है, पूरी तरह से हरकत में आ गया है। अब यहां से हर प्रकार के लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। चीन की मुश्किल यह है कि वह जिस क्षेत्र को भारत के लिए असंभव मानकर खुद को इसका मालिक समझ बैठा था, उस पर भारत प्रभावशाली तरीके से स्थापित हो गया है और भारत का यही बदलता हुआ स्वरूप उसे रास नहीं आ रहा

नमो विजन के अनुरूप निखर रही दिव्य केदारपुरी

आपदा के बाद केदारनाथ यात्रा से जुड़ते चले गए नए कीर्तिमान, सुविधाओं का विकास

जून 2013 की आपदा के बाद बीते सात वर्षों में केदारपुरी अब नए कलेवर में निखरकर सामने आई है तो इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विजन है। केदारपुरी का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस परियोजना पर सीधी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भी समय-समय पर इसकी समीक्षा करते हैं।

आपदा के बाद शुरुआती दो वर्षों में जरूर यात्रियों की आमद सीमित रही, लेकिन फिर यात्रा ने नए-पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। बीते वर्ष पहली बार दस लाख से अधिक यात्री धाम में दर्शनों को पहुंचे, जो कि यात्रा के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत धाम में पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। इनमें कई पूरे भी हो चुके हैं।

16 जून 2013 की आपदा ने केदारपुरी में जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर लगता ही नहीं था कि निकट भविष्य में यात्रा शुरू भी हो पाएगी। लेकिन, बीते सात वर्षों में जैसे-जैसे केदारपुरी संवरती गई, यात्रा भी नए-नए कीर्तिमान गढ़ती चली गई। आपदा के बाद धाम में जिस तरह बुनियादी सुविधाएं विकसित हुई हैं, वह धाम के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इसके पीछे एक वजह प्रधानमंत्री का स्वयं पुनर्निर्माण कार्यों की मॉनीटरिंग करना भी है। आपदा में केदारनाथ पैदल मार्ग ही नहीं, गौरीकुंड हाइवे भी रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक कई स्थानों पर पूरी तरह बह गया था। अब ऑलवेदर रोड के तहत इस हाइवे को बनाया जा रहा है। इसके लिए ठटिंग का कार्य पूरा हो चुका है। धाम में यात्रियों के ठहरने को पर्याप्त व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं और सात हजार यात्री यहां ठहर सकते हैं। तीर्थ पुरोहितों के लिए भी 210 भवनों का निर्माण कराया गया है। आपदा के बाद भीमबली से केदारनाथ तक दस किमी लंबा नया पैदल मार्ग तैयार किया गया। साथ ही छोटी लिनचोली, लिनचोली, रुद्रा प्वांइट समेत कई छोटे बाजार भी विकसित किए गए। इन स्थानों पर यात्रियों के रहने की सभी व्यवस्थाएं हैं।

इन पर कार्य प्रारम्भ

- आदि शंकराचार्य की समाधि का निर्माण
- छूटे तीर्थ पुरोहितों के लिए घरों का निर्माण
- गरुड़चट्टी से भीमबली तक पैदल मार्ग का निर्माण
- केदारनाथ मंदिर के पीछे ब्रह्मवाटिका का निर्माण

प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हुए निर्माण कार्य

- मंदाकिनी नदी पर घाट व चबूतरे का निर्माण
- केदारनाथ मंदिर परिसर में चौड़ीकरण कार्य और मंदिर के सामने 200 मी. लंबे रास्ते का निर्माण
- तीर्थ पुरोहितों के घरों का निर्माण
- 400 मी. लंबे आस्था पथ का निर्माण
- गरुड़चट्टी को केदारनाथ धाम से जोड़ा
- यात्रियों के ठहरने को कॉटेज का निर्माण
- केदारनाथ में अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त अस्पताल

केदारनाथ मंदिर

प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट की दिख रही झलक, बदल गई तस्वीर

प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट की झलक केदारपुरी में दिखने लगी है। देश-दुनिया में आने वाले यात्रियों को इस बार केदारपुरी नए रूप-रंग में नजर आ रही है। मंदिर परिसर में जहां एक साथ तीन हजार यात्री खड़े हो सकते हैं, वहीं यात्री 200 मीटर दूर मंदाकिनी व सरस्वती नदी के संगम से भी केदारनाथ मंदिर के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। केदारपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत कार्य हो रहे हैं। मंदिर परिसर पहले की तुलना में तीन गुना बड़ा हो गया है। जबकि, मंदिर के सामने 275 मीटर लंबा व 50 फीट चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते में भी यात्रियों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। मंदाकिनी व सरस्वती नदी के संगम पर यात्रियों के लिए वेजिंग रूम बनाया गया है। इसके अलावा घाट बनने से वहां स्नान करना काफी सुविधाजनक एवं सुरक्षित हो गया है।

प्रधानमंत्री ने ली वीडियो कॉन्फ्रेंस में केदारनाथ के कार्यों की जानकारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से श्री केदारनाथ में चल रहे कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने ड्रोन के माध्यम से श्री केदारनाथ में चल रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन भी किया। उन्होंने केदारनाथ मंदिर परिसर, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट एवं आस्था पथ, भैरव मंदिर के रास्ते पर बने पुल, केदारनाथ में बन रही गुफाओं, मन्दाकिनी नदी पर बन रहे पुल, मंदाकिनी एवं सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों का अवलोकन किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि रामवाड़ा से केदारनाथ तक छोटे-छोटे पेच को श्री केदारनाथ की ऐतिहासिकता से जोड़ा जाय, ताकि श्रद्धालुओं को केदारनाथ के ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के बारे में भी रोचक जानकारियां मिल सके । इस क्षेत्र में आध्यात्म से संबंधित भी अनेक कार्य किये जा सकते हैं। इस ओर ध्यान दिया जाय। इससे श्रद्धालुओं को श्री केदारनाथ के दर्शन के साथ ही यहां से जुड़ी धार्मिक एवं पारंपरिक महत्व के बारे में भी जानकारी मिलेगी। केदारनाथ के आस-पास जो गुफाएं बनाई जा रही हैं, उनका सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाए ताकि इनका स्वरूप आकर्षक हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी केदारनाथ में निर्माण कार्य तेजी से किये जा सकते हैं। शीर्ष प्राथमिकता के कार्य चिन्हित कर पहले उन्हे पूर्ण कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि भगवान केदारनाथ एवं बदरीनाथ में विभिन्न कार्यों के लिए राज्य सरकार को केन्द्र से हर सम्भव मदद दी जायेगी। भगवान बदरीनाथ धाम के लिए भी डेवलपमेंट प्लान बनाया जाय। अगले 100 साल तक की परिकल्पना के हिसाब से डेवलपमेंट प्लान बनाया जाय। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्री केदारनाथ में यात्रा की स्थिति के बारे में जानकारी ली।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि केदारनाथ धाम, पूरे विश्व की आस्था को केंद्र है। यहां प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बदरीनाथ चार धाम यात्रा प्रदेशवासियों के लिए लाईफ लाईन की तरह है। हजारों स्थानीय लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर है। होटल, रेस्टोरेंट, बस व टैक्सी, आदि के रूप में पर्यटन से जुड़े व्यवसाय काफी हद तक केदारनाथ सहित चारधाम यात्रा पर निर्भर हैं। इससे हजारों लोगों को काम मिलता है।

राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों की आजीविका के लिए नई पहल की है। देवभोग प्रसाद योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इसमें स्थानीय उत्पादों का प्रयोग कर प्रसाद तैयार करवाया जाता है। अकेले केदारनाथ में 1 करोड़ का प्रसाद महिलाओं द्वारा बेचा गया है। प्रदेश के 625 बड़े मंदिरों में इस योजना को लागू किया जा रहा है। फलस्वरूप महिलाओं के साथ-साथ किसानों को भी अच्छी आमदनी हो रही है।

केदारनाथ में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए राज्य को लगभग 200 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के लिए सीमित संख्या में भगवान केदारनाथ एवं बदरीनाथ जी के दर्शन के लिए अनुमति दी गई है। मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी के पालन करते हुए एक दिन में अधिकतम 800 लोग दर्शन कर सकते हैं। आदिगुरू शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण का कार्य 31 दिसम्बर 2020 तक पूरा हो जायेगा। सरस्वती घाट का कार्य पूर्णता की ओर है। भैरव मन्दिर के रास्ते पर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, यह कार्य निर्धारित समयावधि से पहले ही पूरा किया गया है। तीर्थ पुरोहितों को रहने के लिए 05 ब्लॉको में घर बनाऐ जा रहे हैं, जिसमें से 02 ब्लाको में बनाये जा चुके हैं, शेष ब्लाको में सितम्बर तक कार्य पूरा हो जायेगा। केदारनाथ में आध्यात्म की दृष्टि से तीन गुफाए बनाई जा रही हैं, जिनका निर्माण कार्य सितम्बर 2020 तक पूर्ण हो जायेगा। मन्दाकिनी नदी पर बन रहे पुल का कार्य 31 मार्च 2021 तक पूर्ण किया जायेगा। श्री केदारनाथ में ओपन म्यूजियम बनाने की योजना भी बनाई जा रही है।

आजीविका से जुड़ा केदारनाथ धाम

प्रधानमंत्री के समक्ष बद्रीनाथ का मास्टर प्लान प्रस्तुत

130 करोड़ से होंगे द्वितीय चरण के कार्य

केदारनाथ में तीन चरणों में होने वाले पुनर्निर्माण कार्यों पर खर्च होने हैं 450 करोड़

केदारनाथ धाम में प्रथम चरण के पुनर्निर्माण कार्य 80 फीसद पूरे हो

केदारनाथ यात्रा इको फ्रेंडली बनाने का प्रयास

केदारनाथ यात्रा को इको फ्रेंडली बनाने के लिए बहुत सी पहल की गई हैं। पॉलिथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। एक ईको डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई है। यात्रा मार्ग पर 250 स्वच्छता मित्र लगाए गए हैं। कूड़े को एक

ध्यान गुफा बनी आकर्षण का केन्द्र

जिस ध्यान गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 घंटे एकांत वास किया वह श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गई। उस गुफा में रहने हेतु बुकिंग के लिए श्रद्धालुओं में होड़ सी लग गई। पिछले साल सरकार ने पुनर्निर्माण के तहत भैरवनाथ मंदिर के में चर्चा में आई। स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ धाम में तीन और गुफाओं का निर्माण कराया जा रहा है। यह तीनों गुफाएं केदारनाथ की पहाड़ियों पर बनाई जानी हैं। केदारनाथ धाम में समुद्र तल 12500 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई ध्यान गुफा देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी चर्चा का विषय बनी। गढ़वाल मंडल विकास निगम की

शुरू करने की कवायद चल रही है। प्रशासन की ओर से भूमि का सर्वे कर लिया गया है और अब मास्टर प्लान के तहत सरकारी व गैर सरकारी भवनों का अधिग्रहण किया जाना है। इन औपचारिकताओं के पूरे होते ही द्वितीय चरण के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। इन पर 130 करोड़ की धनराशि खर्च होनी है। तीसरे चरण के लिए 195 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं। तीन चरणों में होने वाले कार्यों पर कुल 450 करोड़ की धनराशि खर्च होने का अनुमान है।

वर्ष 2013 की आपदा में तबाह हुई केदारपुरी को दोबारा से मास्टर प्लान के तहत बसाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2017 को तीन चरणों में होने वाले पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया था। प्रथम चरण में केदारनाथ मंदिर परिसर का चौड़ीकरण, मंदिर के सामने 200 मीटर लंबे पैदल मार्ग व चबूतरे का निर्माण, मंदाकिनी नदी पर 400 मीटर लंबे आस्था पथ, आदि शंकराचार्य की समाधि, गरुड़चट्टी-केदारनाथ पैदल, तीर्थपुरोहितों के घर, मंदाकिनी व सरस्वती पर घाट का निर्माण और बाढ़ सुरक्षा कार्य होने थे। इनमें 80 फीसद कार्य पूरे हो चुके हैं और अब द्वितीय चरण के कार्य शुरू करने को औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

केदारपुरी में श्रद्धालुओं के रहने के लिए बनाए गए कॉटेज।

द्वितीय चरण में होने वाले कार्य

- चिकित्सालय का निर्माण
- मंदाकिनी व सरस्वती नदी पर प्लाजा का निर्माण
- मंदिर समिति के भवनों का निर्माण
- मंदिर के ठीक सामने प्लाजा विस्तारीकरण
- संगम घाट पर नवनिर्माण
- दो वाटर एटीएम की स्थापना
- आस्था पथ में रेन शटर और यात्रियों के लिए बैठक का निर्माण
- पुलिस स्टेशन व बैरक का निर्माण
- पुलिस गेस्टहाउस का निर्माण

पुनर्निर्माण में चिनूक की महत्वपूर्ण भूमिका

अमेरिकी तकनीक से बना भारतीय वायु सेना का सबसे बड़ा मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक समुद्रतल से 11657 फीट ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों में अहम भूमिका निभाएगा। वर्ष 2015 में वायु सेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर एमआइ-26 ने भी आठ दिनों तक गौचर से चार डंफर व दो जेसीबी समेत कई भारी मशीनें व अन्य निर्माण सामग्री केदारनाथ पहुंचाई थी। इसके बाद पुनर्निर्माण कार्यों में काफी तेजी आ गई थी।

वर्ष 2013 की आपदा के बाद से केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों में वायु सेना की अहम भूमिका रही है। वर्ष 2015 में रूसी तकनीक से बने वायु सेना के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर एमआई-26 की मदद से केदारनाथ में कई महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण कार्यों को अंजाम दिया गया था। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा करने के लिए वायु सेना का सहारा लिया जा रहा है। इसके तहत हाल ही में वायु सेना में शामिल हुआ अमेरिकी हेलीकॉप्टर चिनूक भी केदारनाथ के लिए उड़ान भरेगा। इस हेलीकॉप्टर से दस टन भारी मशीनें केदारनाथ पहुंचाई जा सकती हैं। प्रदेश सरकार ने भी केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। वर्ष 2015 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (निम) ने यहां एमआइ-26 उतारने के लिए सौ गुणा 50 मीटर का हेलीपैड बनाया था। लेकिन, बाद में प्रदेश सरकार ने इसके आधे हिस्से पर यात्रियों के लिए 45 कॉटेज बनवा दिए। इनमें 500 यात्री ठहर सकते हैं। अब चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड पर बने ये कॉटेज हटाए जा रहे हैं।

चिनूक हेलीकॉप्टर की विशेषताएं

- जरूरत पड़ने पर 11 टन तक भारी सामान ले जाने में भी सक्षम।
- भारी सामान ऊंचे एवं दुर्गम इलाकों तक पहुंचाने में सक्षम।
- किसी भी समय और किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है।
- दो रोटर इंजन लगे होने के कारण काफी सुरक्षित है यह हेलीकॉप्टर।

देश-दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही केदारपुरी

केदारनाथ धाम 12 ज्योर्तिलिंगों में शामिल है, जो हिन्दुओं की आस्था का केंद्र है। श्री केदारनाथ धाम हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग जिले में पर्वतराज हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों में विराजमान श्री केदारनाथ धाम आकर दैवीय अनुभूति की जा सकती है। मंदाकिनी नदी का उद्भव यही से होता है। चारधाम यात्रा बिना केदारनाथ दर्शन के अधूरी है। वर्ष 2013 में आयी आपदा के बाद केदारनाथ का पुनर्निर्माण आरंभ हुआ। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के उपरांत केदारनाथ का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री केदारनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर बेहद गंभीर हैं। वह चाहते हैं कि इसका स्वरूप भव्य व दिव्य हो। पुनर्निर्माण कार्यों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार किया जा रहा है। पुनर्निर्माण कार्यों में धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप का ध्यान रखा जाएगा।

इसलिए प्रधानमंत्री स्वयं निर्माण कार्यों की मानिटरिंग करने लगे। 2020 में केदारपुरी निखरते हुए अपने भव्य स्वरूप में आ रही है। देश-दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केदारनाथ स्थित ध्यान गुफा में साधना के बाद 'सुरक्षित उत्तराखंड-सुरक्षित यात्रा' का संदेश दिया है। केदारनाथ आस्था व कुदरत का अनूठा संगम है। इसलिए दुनिया में कहीं भी विदेश यात्रा करें लेकिन केदारनाथ अवश्य आएं।

संचार संपर्क, पैदल यात्रा हुई अधिक सुविधाजनक

सात साल पहले आई जल प्रलय से अब केदारघाटी पूरी तरह उबर चुकी है। केदारनाथ त्रासदी से सबक लेते हुए व्यवस्थाएं मुकम्मल करने की दिशा में सरकारें संजीदा हुईं, मगर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ये बात अलग है कि इस मर्तबा परिस्थितियां बदली हैं, मगर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का जिम्मा अब सरकार ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के जरिये अपने हाथ में ले लिया है। अब उसके सामने केदारनाथ समेत पूरे क्षेत्र में बेहतर संचार कनेक्टिविटी, पैदल मार्ग पर यात्री सुविधाएं, यात्रियों की नियंत्रित संख्या, पंजीकरण, वैकल्पिक मार्ग जैसे मामलों में कसौटी पर खरा उतरने की चुनौती है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि जून 2013 में कुदरत ने केदारनाथ समेत समूची केदारघाटी में किस तरह अपना रौद्र रूप दिखाया था। लगातार प्रयास हुए तो इस त्रासदी से केदारघाटी उबर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में निरंतर रुचि ले रहे हैं। साफ है कि केदारनाथ त्रासदी से सिस्टम ने सबक लिया है। केदारनाथ की सुरक्षा के लिए मंदिर के पीछे त्रिस्तरीय सुरक्षा दीवार के निर्माण के साथ ही केदारपुरी में कई काम हुए हैं और वर्तमान में तमाम कार्य चल रहे हैं। केदारनाथ में व्यवस्थाएं अवश्य जुटी हैं, लेकिन अभी काफी काम होने बाकी हैं। अब तो सरकार ने केदारनाथ समेत चारधाम और उनके नजदीकी मंदिरों के प्रबंधन को चारधाम देवस्थानम बोर्ड के जरिये व्यवस्थाएं अपने हाथ में ले ली हैं। लिहाजा, उसे ही यात्रा से जुड़ी चुनौतियों से पार पाने के लिए कदम उठाने हैं।

परिस्थितियां सामान्य होने पर जब यात्रा प्रारंभ होगी तो इसमें चुनौतियां कम नहीं होंगी। सबसे पहले तो केदारनाथ क्षेत्र में बेहतर संचार सुविधा कराने की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के प्रयास जरूरी हैं। वर्तमान में केदारनाथ में सात हजार यात्रियों के ठहरने का इंतजाम है, जबकि सीजन में इसके चार गुना तक यात्री रोजाना वहां पहुंचते हैं। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक 16 किमी के पैदल सफर के दरम्यान यात्रा मार्ग पर यात्री सुविधाएं भी उसी हिसाब से जुटानी आवश्यक हैं। यही नहीं, पूर्व में ये बात हुई थी कि केदारनाथ जाने वाले प्रत्येक यात्री का वायोमीट्रिक पंजीकरण होगा। अब देवस्थानम बोर्ड को इस मोर्चे पर कौशल दिखाना होगा। यात्रियों के पंजीकरण के मद्देनजर ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जिससे एक-एक यात्री का ब्योरा उपलब्ध रहे और किसी को कोई दिक्कत भी न होने पाए। इसके अलावा किसी भी अपरिहार्य स्थिति के दृष्टिगत वैकल्पिक मार्गों को सुदृढ़ किए जाने पर भी काम किया जा रहा है।

पैदल यात्रा मार्ग केदारपुरी

केदारनाथ में वर्ष 2013 में आई आपदा के बाद सारे रास्ते ध्वस्त हो चुके थे। लेकिन तेजी से हुए पुनर्निर्माण से पैदल रास्ते पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और सुविधाजनक हो गए है। यही कारण है कि करीब चार साल बाद श्रद्धालुओं द्वारा केदारनाथ यात्रा में पैदल मार्ग को तवज्जो दी जा रही है। मौजूदा समय में गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्वास्थ्य विभाग ने एमआरपी (मेडिकल रिलीफ प्वाइंट) के साथ एक-एक वॉर्म रूम स्थापित किए हैं। करीब 17 किमी पैदल मार्ग पर 9 एमआरपी बनाई जा रही है। केदारनाथ में भी दो वॉर्म रूम स्थापित होंगे। इस प्रकार यात्रा में कुल 11 वॉर्म रूम स्थापित होंगे। इस सुविधा से हाइपोथर्मिया (तेजी से शरीर का तापमान घटना, सांस लेने में दिक्कत) से पीड़ित मरीज के उपचार में मदद मिलेगी। पैदल मार्ग में हर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर दुकानें मिल रही हैं। जहां चाय-बिस्कुट, पानी आदि खाने-पीने की चीजें उपलब्ध रास्ते में बीच में कई जगह प्रतीक्षालय, बैठने का स्थान भी बनाए गए हैं, जहां लोग अपनी थकान दूर कर सकते हैं। केदारनाथ बेस कैंप में 12 बैड का स्वामी विवेकानंद धमार्थ चिकित्सालय में यात्रियों को निशुल्क चिकित्सा मुहैया करायी जाएगी।

ADVT

2017 में चीन ने डोकलाम विवाद को अंजाम दिया था।

जम्मू-कश्मीर का दरवाजा समूचे देश के लिए खोल देने के बाद पाकिस्तान की छटपटाहट बढ़ गई है। वह कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए निराशा में उसने अपने सबसे बड़े संरक्षक तथा मित्र चीन से मदद की गुहार लगाई है। चीन भी पाकिस्तान की मदद के लिए मजबूर है, क्योंकि उसने पाकिस्तान में साझे आर्थिक गलियारे के लिए बहुत बड़ा निवेश कर रखा है।

है। इसलिए वह बार-बार पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है। वह परोक्ष रूप से भारत पर दबाव डालकर उसे लद्दाख क्षेत्र से दूर रखना चाहता है।

चीन की बेचैनी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है-जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 तथा 35ए का समाप्त होना, जिसके कारण अब इस राज्य का चौतरफा विकास होगा। राज्य में निवेश होगा और आम कश्मीरी की स्थिति सुधरेगी और वह अलगाववादियों से छुटकारा पा लेगा। भारत के इस कदम से पाकिस्तान के सपने पर वज्रपात हुआ है। जो लंबे समय से कश्मीर को हड़पने का मंसूबा पाले बैठा था। पाकिस्तानी सेना अपने देशवासियों को कश्मीर पर कब्जे के सब्जबाग दिखा रही थी, पर अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। इसमें आग में पेट्रोल डालने का काम भारत सरकार के उस निश्चय ने किया है, जिसके द्वारा अब वह पाक अधिक्रांत कश्मीर को भी कश्मीर में मिलाने की योजना बना रही है। कश्मीर में भारतीय कानून लागू होने के कारण पाकिस्तान समर्थित अलगाववादियों की हरकतों पर भी पूरी तरह लगाम कस गई है। इस कारण अब कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के इशारों पर धरने-प्रदर्शन इत्यादि बंद हो गए हैं। ये अलगाववादी जम्मू-कश्मीर को जान-बूझकर पिछड़ा रखना चाहते थे, ताकि वहां की जनता को यह कह कर बहका सकें कि भारत सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार से जो धन मिलता था, अलगाववादी उसकी बंदरबांट कर रहे थे। इसके बावजूद सत्तारूढ़ दल उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता थी। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रह चुके जगमोहन ने अपनी किताब में वहां हो रहे भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं कि राज्य में सरकारी नौकरियां अपने चहेतों को दी जाती थीं। अलगाववादी यहां चुपके-चुपके आतंक का माहौल पैदा करके लोगों पर पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए दबाव डालते थे। यही कारण था कि हर शुक्रवार को नमाज के बाद यहां पथराव और प्रदर्शन आम बात थी। कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित कर उन्हें घाटी से खदेड़ दिया गया। इस तरह उन्होंने भारत समर्थक हर उस व्यक्ति को घाटी से बाहर निकाल दिया ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज न उठा सके और वे देश विरोधी गतिविधियां बिना रोक-टोक जारी रख सकें। अब जम्मू-कश्मीर का दरवाजा समूचे देश के लिए खोल देने के बाद पाकिस्तान की छटपटाहट बढ़ गई है। वह कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए निराशा की स्थिति में उसने अपने सबसे बड़े संरक्षक तथा मित्र चीन से मदद की गुहार लगाई है। इस समय चीन भी पाकिस्तान की मदद को मजबूर है, क्योंकि उसने पाकिस्तान में साझा आर्थिक गलियारे के लिए बहुत बड़ा निवेश कर रखा है। यह योजना 80 बिलियन पाउंड की है, जिसका बहुत धन अब तक वह खर्च कर चुका है। पाकिस्तान और चीन की यह साझा परियोजना अगस्त 2015 में शुरू हुई थी। इसके तहत चीन अपने शिंजियांग प्रांत को काराकोरम सड़क मार्ग के जरिए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस सड़क के आसपास वह पाकिस्तान में जगह-जगह औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करके वहां अपने उद्योगों का विस्तार करना चाहता है। इसके लिए वह पाकिस्तान में आधारभूत ढांचे के विकास जैसे-सड़क तथा बिजली इत्यादि पर भी अच्छा खासा खर्च कर रहा है। चूंकि परियोजना के लिए उसने पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया है, इसलिए उसे हर समय यह डर सताता है कि कहीं आगे चल कर वह अपना इरादा न बदल दे। यही वजह है कि वह हर हाल में पाकिस्तानी सरकार व उसकी सेना को खुश रखना चाहता है। इसी कारण वह बार-बार भारत के साथ सैनिक टकराव के मौके ढूंढ़ता रहता है, जैसा कि उसने 2017 में सिक्किम के डोकलाम में किया था और उसी की पुनरावृत्ति पूर्वी लद्दाख में कर रहा है।

इसके अलावा, चीन की आक्रामकता का तीसरा सबसे बड़ा कारण है दक्षिणी चीन सागर में चीन के प्रभुत्व को भारत द्वारा चुनौती दिया जाना। भारत ने इस क्षेत्र के प्रमुख देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस तथा अमेरिका के साथ एक गठजोड़ बनाया है। इसी के तहत भारतीय और अमेरिकी युद्धपोत इस क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं। संभव है कि भविष्य में कभी भी चीन का यह आयात-निर्यात मार्ग बंद हो सकता है। चीन इसी रास्ते से अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है तथा उसका 60 प्रतिशत निर्यात इसी मार्ग से होता है। यदि इस रास्ते में उसके सामने कोई

बाधा आएगी तो उसका पूरा आर्थिक विकास बाधित हो जाएगा। इसी कारण उसने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित किया है ताकि समुद्री मार्ग से उसका संपर्क बना रहे। लेकिन अब काराकोरम हाईवे के आसपास भारतीय सेना ने अपना प्रभाव बढ़ाया है तो उसके मन में ग्वादर बंदरगाह को लेकर भी संशय पैदा हो गई है। यही तीन कारण हैं, जिससे चीन बौखलाया हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण काराकोरम हाईवे को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र से पीछे धकेलना चाहता है, जिससे वह इस इलाके में बिना रोक-टोक अपनी गतिविधियां चलाता रहे। लेकिन वह भूल कर रहा है कि यह 1962 का भारत नहीं है। उस समय भारत को आजाद हुए दो दशक भी नहीं हुए थे और लंबे समय तक गुलाम रहने के कारण विकास के मामले में देश फिसड्डी था। चीन ने इसी का फायदा उठाकर चुपचाप अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया। चूंकि उस समय भारत में संचार व्यवस्था नहीं थी, इसलिए भारत को इस घुसपैठ का पता तीन साल बाद 1962 में लगा। दुर्भाग्य से इस युद्ध में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन अब यह चीन को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। अपनी उसी शक्ति का प्रदर्शन भारतीय सेना मई से अब तक पैंगोंग झील के आसपास प्रमुख पहाड़ियों पर कब्जा करके कर रही है। भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के आसपास ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, रेजांगला आदि ऊंची चोटियों पर कब्जा करके चीनी घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगा दी है। 28-29 अगस्त की रातजब चीनी सैनिक चोरी-छिपे दोबारा 14 जून की तरह घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, तब भारतीय सैनिकों ने उन्हें समय रहते वापस लौटने पर मजबूर कर दिया।

भारतीय सेना ने लद्दाख क्षेत्र में पर्याप्त सैनिकों की नियुक्ति, तोपखाना तथा टैंकों की तैनाती कर अपनी रक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर लिया है। चीन भी इसे अच्छी तरह समझ रहा है, इसलिए वह कभी भी भारत के साथ युद्ध करने के बारे में नहीं सोचेगा। वह केवल छोटी-मोटी झड़पों के जरिए अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करेगा ताकि उसका मित्र पाकिस्तान खुश हो जाए, जैसा कि आजकल दिख भी रहा है। चीन यह भी भली-भांति जानता है कि अगर उसने भारत के साथ युद्ध छेड़ा तो भारत उसका आर्थिक ढांचा तथा दुनियाभर में फैले उसके व्यापार को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इसलिए वह भारत के खिलाफ ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे उसे नुकसान हो। हालांकि युद्ध किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। आपसी समझ-बूझ और बातचीत से इसे टाला जा सकता है। भारत-चीन विवाद में यही प्रयास किया जा रहा है। ■

महिला एवं बाल विकास विभाग
ICDS
POSHAN Abhiyaan
आइए सुपोषित गुजरात का
निर्माण करें
हर घर में पोषण त्यौहार
पोषण माह
(1 से 30 सितंबर 2020)
शिशु के समग्र विकास के लिए महत्त्वपूर्ण प्रथम 1000 दिवसों का ध्यान रखें
सगर्भावस्था (270 दिवस)
• समय पर आंगनवाड़ी में प्रारंभिक पंजीकरण
• संतुलित आहार का ध्यान रखें और आराम करें
• लौहतत्त्व/आयर्न और कैल्शियम की गोलियों का नियमित सेवन
जन्म से 6 माह के बालक (180 दिवस)
• पहले एक घंटे में केवल स्तनपान
• 6 माह तक सिर्फ स्तनपान
• गलथुथि, शहर एवं पानी तक भी नहीं
सात से 24 माह के बालक (550 दिवस)
• 6 माह पूर्ण होने के तुरंत बाद पौष्टिक एवं सुपाच्य ऊपरी आहार की शुरुआत
• आयुनुसार बालक के आहार में वृद्धि करें
• 2 वर्ष तक स्तनपान अवश्य जारी रखें
अधिक जानकारी के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें।
सुपोषित गुजरात के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध
-श्री नीतिनभाई पटेल, उप मुख्यमंत्री, गुजरात राज्य
महिला और बाल विकास विभाग, गुजरात सरकार
WCD Gujarat

ईसाई बाने में रोहिंग्या घुसपैठिए

रोहिंग्या और अफगानिस्तान के मुसलमान भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए तेजी से ईसाई बन रहे हैं ताकि नागरिकता संशोधन कानून का फायदा उठा सकें। ईसाई मत अपनाने वाले रोहिंग्या खुद को बांग्लादेश का ईसाई बता रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को इस बारे में आगाह किया है। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 1,50,000-1,60,000 अफगान मुस्लिम और देशभर में 40,000 रोहिंग्या घुसपैठिए हैं

■ एस. वर्मा

भारत सदियों से दुनियाभर में आध्यात्मिक खोज, ज्ञान और शांति चाहने वालों का पसंदीदा स्थान रहा है और हमेशा से ही बड़ी संख्या में ऐसे जिज्ञासुओं का यहां स्वागत किया जाता रहा है। लेकिन भारत पर इस्लामिक आक्रमण के बाद से स्थितियां बदलने लगीं। बड़ी संख्या में आए दुर्दांत आक्रान्ताओं ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संपदा को नष्ट करने का प्रयास किया। इसी क्रम में बड़े पैमाने पर विदेशों से मजहब विशेष के लोग टिड्डी दल की तरह भारत पर टूट पड़े। इसी के साथ बड़े पैमाने पर बलात कन्वर्जन के जरिये जनसांख्यिकी बदलने और राजनीतिक लाभ हासिल करने के प्रयास भी हुए, जिसमें काफी हद तक उन्हें सफलता भी मिली। इस कारण मुगलों ने लंबे समय तक भारत पर

पश्चिमी दिल्ली में रहने वाले म्यांमार के लगभग 5,000 चिन शरणार्थियों में से करीब 90 प्रतिशत ईसाई बन चुके हैं

शासन किया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद व्यापार करने भारत आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस राजनीतिक निर्वात को भरने का काम शुरू किया। नई औपनिवेशिक शक्ति के रूप में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद शोषण के तरीकों में कुछ आमूलचूल बदलाव आए। अंग्रेजों के भारत पर शासन की शुरुआत के साथ ही नई तरह की घुसपैठ भी शुरू हुई, जिससे भारत में धार्मिक उत्पीड़न और कन्वर्जन का नया दौर शुरू हुआ, जिसके केंद्र में चर्च था। भारत को ईसाई बना लेने की महती आकांक्षाओं के साथ दुनियाभर के मिशनरीज ने भारत पर धावा बोला। हालांकि 15 अगस्त, 1947 को हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद तो हुए, पर धार्मिक उत्पीड़न और कन्वर्जन की प्रक्रियाएं आजादी के बाद भी नए रूप में जारी हैं।

मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और मुसलमानों को नए देश के रूप में पाकिस्तान मिला। वहीं, भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को न केवल समान अधिकार मिले, बल्कि कई मामलों में तो विशेषाधिकार भी दिए गए। वहीं, पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के हिस्से में नारकीय जीवन ही आया। बाद में यही स्थिति बांग्लादेश की भी रही। इसलिए धार्मिक अल्पसंख्यक मदद के लिए भारत की ओर देखते थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें इन मुद्दों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाती रहीं और इस बड़ी आबादी को उसके हाल पर छोड़ दिया। वर्तमान भाजपा नीत राजग सरकार ने इन देशों में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) बनाया, जिसमें उन्हें भारत की नागरिकता देने संबंधी रक्षा उपाय किए गए। लेकिन भारत में एक विशिष्ट मानसिकता और विचारधारा वाले वर्ग ने इसका विरोध किया और इसे भेदभावपरक तथा भारत के पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध बताया। दूसरी ओर, पंथनिरपेक्षता का ढोल पीटने वाले लोग, जिन्होंने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए हमेशा धर्म का सहारा लिया, एक बार फिर धर्म की आड़ में अपने कुत्सित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं।

कन्वर्ट होते रोहिंग्या!

सीएए में चूंकि ईसाइयों को भी छूट दी गई है, इसलिए अफगानी और रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को ईसाई मत में कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि वे भारतीय नागरिकता हासिल कर सकें। केंद्रीय सतर्कता एजेंसियों ने सरकार को इस नए षड्यंत्र के प्रति आगाह किया है। समाचारपत्र इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अफगान मुसलमानों के ईसाई मत में परिवर्तित होने के लगभग 25 मामले सुरक्षा एजेंसियों की निगाह में आए हैं। दक्षिण दिल्ली में एक अफगान चर्च के प्रमुख और एक परिवर्तित ईसाई आदिब अहमद मैक्सवेल के हवाले से समाचारपत्र ने लिखा है, 'सीएए के लागू होने के बाद वैसे अफगान मुसलमानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जो ईसाई मत अपनाना चाहते हैं।' आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 1,50,000-1,60,000 अफगान मुस्लिम रहते हैं। अधिकारियों का मानना है कि यूएनएचसीआर ने जिन अफगान और रोहिंग्या घुसपैठियों को शरणार्थी का दर्जा देने से इनकार कर दिया है या जो सीएए लागू होने की तारीख से पहले भारत आए थे, वैसे मुसलमान भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कन्वर्जन का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार, भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं, जिनकी सबसे बड़ी संख्या जम्मू-कश्मीर में है। इनमें बड़ी संख्या में रोहिंग्या 2012 से पहले भारत में रह रहे हैं। अब इन्होंने ईसाई मत को अपना लिया है और ये बांग्लादेश का निवासी होने का दावा कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत के हैं। इनके बारे में दुनियाभर में यह प्रचारित किया गया कि 2011 के अंत में म्यांमार में सशस्त्र बलों के उत्पीड़न के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं ने भारत का रुख किया। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए रोहिंग्याओं की समस्या को धार्मिक उत्पीड़न के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

10 जनवरी, 2020 को लागू सीएए का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पांथिक अल्पसंख्यकों जैसे–हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता देना है, जो इन इस्लामी देशों में उत्पीड़न के

कारण पलायन के लिए विवश हुए हैं। इनके अलावा, किसी भी शरणार्थी को शरण देने के लिए भारत को किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत ने न तो शरणार्थियों को लेकर 1951 में हुए समझौते पर और न ही 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। हमें भी रोहिंग्या मुसलमानों को प्रताड़ित समुदाय नहीं मान कर उन्हें इस रूप में देखना होगा कि वे म्यांमार की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने के उद्देश्य से गठित कई विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और वहां की बौद्ध आबादी के खिलाफ मजहबी उन्माद से ग्रस्त होकर सशस्त्र हिंसा फैलाने जैसी अनेक गतिविधियों में भी शामिल हैं। इसके प्रमाण समय-समय पर उपलब्ध कराए गए हैं। रोहिंग्या स्पष्ट रूप से भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और इनमें से भी एक बड़ा वर्ग अपने लिए शक्ति संग्रह कर म्यांमार और भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए आतुर हैं। इसी कारण ये आवश्यक संसाधन हासिल करने के उद्देश्य से बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ कर सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। यही कारण है कि नागरिकता (संशोधन) कानून के तहत नागरिकता पाने के लिए बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान अब ईसाई बन रहे हैं। इस तरह के कन्वर्जन की कुछ घटनाएं 2017 में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में सामने आई थीं। वास्तव में दिल्ली ऐसे घुसपैठियों का घर बन चुकी है। यूएनएसीआर के आंकड़ों के मुताबिक, भारत इस समय म्यांमार के लगभग 5,000 चिन शरणार्थियों को भी शरण प्रदान किए हुए है। इनमें करीब 90 प्रतिशत चिन शरणार्थी ईसाई बन चुके हैं और पश्चिमी दिल्ली में रह रहे हैं।

हमें रोहिंग्या मुसलमानों को प्रताड़ित समुदाय न मान कर उन्हें इस रूप में देखना होगा कि वे म्यांमार की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने के उद्देश्य से गठित कई विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। वे वहां की बौद्ध आबादी के खिलाफ मजहबी उन्माद से ग्रस्त होकर सशस्त्र हिंसा फैलाने जैसी अनेक गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। इसके प्रमाण समय-समय पर उपलब्ध कराए गए हैं। रोहिंग्या स्पष्ट रूप से भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं

1988 में जब म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ तो हजारों की संख्या में चिन शरणार्थी भागकर सीमावर्ती भारतीय राज्य मिजोरम में आ गए। फिर वहां से दिल्ली में आकर बस गए। जब चिन शरणार्थियों में कई जनजातियां शामिल हैं, जिनमें जोमी, टेडिम, फलाम, चो, हखा, मारा आदि प्रमुख हैं। ये सभी पश्चिम दिल्ली के गांवों जैसे- हस्तसाल, विकास नगर, सीतापुरी और बिंदापुर में रहते हैं।

कानून में खामियों का फायदा उठा रहे

सीएए कानून उन लोगों पर लागू होता है, जो धर्म-मत-पंथ के आधार पर पड़ोसी देशों में प्रताड़ित किए जाते हैं और इसी वजह से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। इस कानून का उद्देश्य ऐसे लोगों को अवैध प्रवास की कार्रवाई से बचाना भी है। सीएए में नागरिकता के लिए कट-ऑफ तारीख 31 दिसंबर, 2014 रखी गई है, यानी नागरिकता के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति इस तारीख से या इससे पहले से भारत में रह रहा है। मौजूदा कानून के तहत भारतीय नागरिकता वैसे लोगों को प्रदान की जाती है, जो भारत में पैदा हुए या कम से कम 11 वर्षों से यहां रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले मुसलमान, जो 'मजहबी उत्पीड़न' के आधार पर यहां शरण चाहते हैं, शायद ही पीड़ित या प्रताड़ित हैं, पर दिखाते ऐसे हैं कि वास्तव में उनसे अधिक पीड़ित और प्रताड़ित कोई है ही नहीं। अब जबकि यह स्पष्ट हो गया है कि भारत की नागरिकता का हकदार कौन है, ये लोग कानून में किए गए प्रावधानों का फायदा उठाने के लिए ईसाई मत अपना रहे हैं ताकि भारत में रह सकें। इसके अलावा, इस कानून में म्यांमार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। लिहाजा, रोहिंग्या खुद को बांग्लादेश का ईसाई बता कर मजहबी अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ पर नजरें गड़ाए बैठे हैं और कुचक्र रच रहे हैं।

चूंकि रोहिंग्या अवैध प्रवासी हैं, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें स्वीकार करने और उन्हें नागरिकता देने से मना कर दिया है। इस कारण देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों को इस कानून में असहिष्णुता और मजहबी कट्टरपंथ दिखाई देता है। आज यह वर्ग इन तथाकथित 'प्रताड़ित शरणार्थियों' के एक मत के निर्लज्ज दुरुपयोग पर मौन धारण किए हुए है। इस तरह की घटनाएं सीएए कानून के सैद्धांतिक पक्ष को रेखांकित करती हैं कि इस्लामी देशों से मुस्लिम आबादी के पलायन को मजहबी उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जो समुदाय चंद सुविधाओं के उपभोग के लिए आसानी से अपना मजहब छोड़कर दूसरे मत को अपना ले, वह लंबे समय से मजहबी रूप से उत्पीड़न को कैसे सह सकता है? इन तथाकथित उदारवादी और कुतर्की सूक्ष्म वर्ग को इस पर भी विचार करना चाहिए। आज भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा का है और इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे तत्व जो इसके लिए खतरा बने हुए हों और संभावित चुनौती प्रस्तुत करने में सक्षम हों, उन्हें चिह्नित कर जड़ से उनका उन्मूलन किया जाए। ■

फरवरी 1922, चौरीचौरा : उपद्रवियों की भीड़ द्वारा फूंका गया पुलिस वाहन

खिलाफत के खोल में हिंसा

खिलाफत आंदोलन का अगस्त 1920 से मार्च 1922 तक का दूसरा चरण जोर-जबरदस्ती और नरसंहार का चरण था। हिंसक मुस्लिमों की भीड़ ने जगह-जगह उपद्रव किए। चौरीचौरा थाने में 21 पुलिस वालों को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया

■ डॉ. श्रीरंग गोडबोले

खिलाफत और असहयोग आंदोलन आपस में जुड़े हुए थे, यह एक गलतफहमी है। असहयोग आन्दोलन भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, इस चर्चित विषय पर डॉ. आंबेडकर का विश्लेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं,''श्री गांधी खिलाफत के लिए न केवल मुसलमानों से सहमत थे बल्कि इस काम में उनके मार्गदर्शक और मित्र भी बन गए। इसमें श्री गांधी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उससे उस आन्दोलन और असहयोग आन्दोलन में जो सबंध था वह क्षीण हो गया, क्योंकि अधिकतर लोग यह विश्वास करते थे कि कांग्रेस ने ही असहयोग आन्दोलन शुरू किया है और वह इसलिए कि यह स्वराज पाने का एक साधन है।

यह विचार सब जगह घर कर गया था क्योंकि अधिकांश लोग यही देखकर संतुष्ट हो गए थे कि असहयोग आन्दोलन और 7-8 सितम्बर, 1920 को कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में संबंध था, परन्तु जिसने भी सितंबर 1920 के बाद की स्थिति का अवलोकन किया है, वह जानता है कि यह विचार सही नहीं है। सच्चाई यह है कि असहयोग आन्दोलन का उद्गम खिलाफत आन्दोलन से हुआ था, न कि स्वराज के लिए कांग्रेस के आंदोलन के रूप

में और कि इसे खिलाफतवादियों ने तुर्की की मदद के लिए शुरू किया था, कांग्रेस ने केवल खिलाफतवादियों की मदद के लिए इसे अपनाया था। इसका मूल उद्देश्य स्वराज नहीं, बल्कि खिलाफत था और स्वराज का गौण उद्देश्य बनाकर उससे जोड़ दिया गया था, ताकि हिन्दू भी उसमें भाग लें और यह बात नीचे दिए गए तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है।

खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 27 अक्तूबर, 1919 को मानी जा सकती है, क्योंकि इसी दिन देशभर में खिलाफत सम्मेलन हुए। इन सम्मेलनों में मुसलमानों ने इस संभावना पर विचार किया कि क्या असहयोग करके अंग्रेज सरकार को खिलाफत की गलती दूर करने के लिए विवश किया जा सकता है। 10 मार्च, 1920 को कलकत्ता में खिलाफत सम्मलेन हुआ और उसमें यह फैसला कर लिया गया कि आन्दोलन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए असहयोग सर्वोत्तम हथियार हो सकता है। 9 जून, 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत सम्मेलन हुआ और वहां सर्वसम्मति से इस बात को दोहराया गया कि असहयोग का सहारा लिया जाए। इस काम के लिए एक कार्यकारी समिति गठित की गई जो विस्तृत

खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 27 अक्तूबर, 1919 को मानी जा सकती है, क्योंकि इसी दिन देशभर में खिलाफत सम्मेलन हुए। इन सम्मेलनों में मुसलमानों ने इस संभावना पर विचार किया कि क्या असहयोग करके अंग्रेज सरकार को खिलाफत की गलती दूर करने के लिए विवश किया जा सकता है

कार्यक्रम तैयार करके उसे लागू करे।

22 जून, 1920 को मुस्लिमों ने वायसराय को सन्देश भेजा जिसमें कहा गया था कि यदि पहली अगस्त 1920 से पूर्व तुर्क लोगों की शिकायतें दूर न की गईं तो वे असहयोग आन्दोलन शुरू कर देंगे। 30 जून, 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई जहां यह तय किया गया कि वायसराय को एक महीने का नोटिस देकर असहयोग आन्दोलन शुरू कर दिया जाए। 1 जुलाई, 1920 को यह नोटिस दिया गया और 1 अगस्त, 1920 से असहयोग आन्दोलन शुरू हो गया। इस संक्षिप्त विवरण से पता चलता है कि असहयोग आन्दोलन खिलाफत कमेटी के खिलाफत सम्मलेन में पहले ही शुरू हो चुका था; और यह स्वराज के लिए नहीं, बल्कि खिलाफत आन्दोलन को बढ़ाने में मुसलमानों की सहायता करने के लिए था। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया गया, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है।'' (डॉ.आंबेडकर, संपूर्ण वाड्मय, खंड 15, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, डॉ. बी. आर. आंबेडकर, डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 2013 पृ.137-139)

असहयोग की खिलाफतवादी योजना

28-29 फरवरी, 1920 को मौलाना आजाद ने कलकत्ता में खिलाफत कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शरीयत के अनुसार किसी भी मुस्लिम का इस्लाम के गैर-मुस्लिम शत्रुओं के साथ मवाला (सहयोग) एक पाप है। हालांकि उन्होंने बड़ी चतुराई से इस श्रेणी से हिंदुओं को बाहर रखा था। उन्होंने असहयोग को इस्लामी 'तर्क-ए-मवालत' (सामाजिक बहिष्कार) के रूप में परिभाषित किया और इसे मुसलमानों के लिए अनुशंसित किया क्योंकि उनके लिए यही एकमात्र उपाय बचा था। (खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया,1919-1924, मुहम्मद नईम कुरैशी, लंदन विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया गया शोध प्रबंध, 1973, पृ.8) 11 मई, 1920 को जिन शांति-शर्तों की घोषणा की गई उन्हें तुर्की की स्वतंत्रता को नष्ट करने और उसके साम्राज्य को छीनने वाला बताया गया। खिलाफतवादियों ने कांग्रेस के हिंदू नेताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए, गांधी जी के परामर्श से सेंट्रल खिलाफत कमेटी की एक विशेष बैठक की। यह जून, 1920 के पहले सप्ताह में इलाहाबाद में आयोजित की गई जिसमें हिंदू-मुस्लिम नेताओं ने सहभागिता की। (उल्लेखनीय है यह वही बैठक है जिसका उल्लेख ऊपर आंबेडकर ने किया है) बैठक में, असहयोग की परिकल्पना चार चरणों में की गई: 1. उपाधियों और मानद पदों का त्याग, 2. सरकार की सिविल सेवाओं में पदों का त्याग, इससे पुलिस को बाहर रखा जाना, 3. पुलिस और सेना में सेवा का इस्तीफा, और 4. करों के भुगतान से इनकार।

तेज हुए खिलाफत के नारे

गांधीजी ने दिसंबर 1919 में खिलाफत मुद्दे पर सरकार द्वारा घोषित शांति समारोह के बहिष्कार की वकालत की। वह पंजाब के मुद्दे (जलियांवाला बाग हत्याकांड और मार्शल लॉ) को बहिष्कार के कारणों में जोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। खिलाफत कॉन्फ्रेंस की हिंदू-मुस्लिम संयुक्त बैठक (24 नवंबर, 1919) को संबोधित करते हुए गांधीजी ने कहा, 'व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों की जो भी पीड़ा हो, हम एक स्थानीय मुद्दे पर खुद को इस समारोह से अलग नहीं कर सकते हैं जो कि संपूर्ण साम्राज्य से जुड़ा हुआ है...और इसके लिए खिलाफत ही वह मुद्दा है जिस पर हम शांति समारोह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं।' हालांकि, खिलाफतवादियों ने पंजाब मुद्दे का फायदा उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसने व्यापक जन असंतोष को उभारा था। गांधीजी ने भी अब खिलाफत के साथ पंजाब के मुद्दे को एक चारे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि हिंदुओं को असहयोग आंदोलन के प्रति आकर्षित किया जा सके। (कुरैशी, उक्त, पृ.112-13) पारंपरिक और संवैधानिक रास्तों से कांग्रेस का हटना

एक बड़ा मुद्दा माना गया जिसके लिए कलकत्ता में 4-9 सितंबर, 1920 को कांग्रेस का एक विशेष सम्मेलन बुलाया गया। (द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पट्टाभि सीतारमैया, सीडब्ल्यूसी, मद्रास, 1935 , पृ. 336)

हिंदू नेतृत्व का विरोध

असहयोग आंदोलन के प्रति कई हिंदू नेताओं के धुर विरोध ने खिलाफतवादियों को चिंतित कर दिया। मुस्लिम नेता एक भारतीय राष्ट्र के निर्माण हेतु हिंदुओं के साथ अपने मतभेद समाप्त करने के इच्छुक नहीं थे। (हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, आर.सी. मजूमदार, खंड 3, पृष्ठ 64) गांधी एक खिलाफतवादी के रूप खिलाफत फंड के व्यय पर देश का दौरा कर रहे थे। इसका अन्य हिंदू नेताओं ने विरोध किया क्योंकि उन्हें लगता था कि यह सेन्ट्रल खिलाफत कमेटी द्वारा संचालित आंदोलन था। उदारवादियों ने इसे अपनी अवधारणा में 'विचित्र और पूरी तरह से अव्यावहारिक' पाया। श्रीमती एनी बेसेंट (1847-1933), जो भारत में थियोसोफी एवं होम रूल लीग की अगुआ थीं, ने इसे 'राष्ट्रीय आत्महत्या' बताया। सर पी.एस. सिवास्वामी अय्यर (1864-1946), जो मद्रास प्रेसीडेंसी के एडवोकेट-जनरल रहे, ने इसे 'देश के लिए आपदा से भरा' अभियान माना। वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री (1869-1946) ने इसे अतार्किक और हानिकारक बताया, साथ ही अप्रैल 1920 में भविष्यवाणी भी की कि शीघ्र ही आंदोलन हिंसक हो जाएगा। मद्रास प्रेसीडेंसी के ही एडवोकेट जनरल रहे श्रीनिवास अयंगर (1874-1941)) ने इस आन्दोलन के तीसरे और चौथे चरण को 'निश्चित रूप से अवैध और असंवैधानिक' करार दिया। ऐसे ही विचार पंडित मदन मोहन मालवीय ने व्यक्त किये। कांग्रेस के संस्थापक सदस्य सुरेंद्रनाथ बनर्जी (1848-1925) ने भी इस संबंध में अपना सार्वजनिक अस्वीकार जारी किया। (कुरैशी, उक्त, पृ.154-155)

कांग्रेस के 'अतिवादी' इस विषय पर एकमत नहीं थे। हालांकि यह सार्वजनिक रूप से माना जा रहा था कि तिलक खिलाफत आंदोलन के साथ नहीं थे। परन्तु तिलक द्वारा 1920 में कांग्रेस के भीतर स्थापित डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी के मेनिफेस्टो के अनुसार 'यह पार्टी खिलाफत से जुड़ी समस्या के मुस्लिम मान्यताओं और कुरान के सिद्धांतों के अनुरूप समाधान के लिए मुस्लिमों के दावे का समर्थन करती थी। (पट्टाभि सीतारमैया, उक्त, पृ. 327) मोतीलाल नेहरू हिंसा फैलने से चिंतित थे। सी. आर. दास, बी.सी. पाल, जी.एस. खापर्डे, एन.सी. केलकर, विट्ठलभाई पटेल जैसे अन्य नेता भी इससे सशंकित थे। (कुरैशी, उक्त, पृ. 154-156) गांधीजी और खिलाफतवादियों, दोनों के लिए कलकत्ता (सितंबर 1920) में कांग्रेस का विशेष सत्र महत्वपूर्ण था।

स्वराज से पहले खिलाफत

हिंदुओं को अपनी ताकत दिखाने के लिए खिलाफतवादियों ने कांग्रेस से असहयोग पर चर्चा करने से पहले अपना सम्मेलन (5 सितंबर, 1919) आयोजित किया। खिलाफत कॉन्फ्रेंस ने सर्वसम्मति से पुष्टि की कि असहयोग एक अत्यंत बाध्यकारी मजहबी दायित्व था। शौकत अली और अन्य खिलाफतवादियों के अत्यधिक दबाव के कारण मुस्लिम लीग ने भी सेन्ट्रल खिलाफत कमेटी का अनुसरण करने का निर्णय लिया। हालांकि जिन्ना ने इसके विरुद्ध चेतावनी दी थी। 'श्री गांधी का तात्कालिक उद्देश्य कांग्रेस के विशेष सत्र को उनके पंथ में परिवर्तित करना था...लेकिन श्री गांधी ने इस हेतु सूक्ष्मता के साथ तैयारियां की थीं। बॉम्बे और मद्रास से खिलाफत स्पेशल ट्रेनों से कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भरकर लाया गया जिन्हें पक्ष में वोट देने के लिए शपथ दिलाई गई थी। राष्ट्रवादियों ने शिकायत की कि खिलाफतवादियों ने सभागार को बंद कर दिया था और बहुमत के साथ छेड़छाड़ की थी।' (स्पीचिस एंड राइटिंग्स ऑफ एम.के. गांधी, इंट्रोडक्शन बाय सी. एफ. एंड्रयूज, मद्रास, 1922, पृ.46-48) असहयोग समिति में असहयोग के प्रस्ताव पर तीन दिन तक बहस चली जिसे बहुत कम बहुमत से स्वीकार किया गया था; 132 के मुकाबले 144 वोट से। मुस्लिम प्रभुत्व ने असहयोग के पक्ष में पलड़ा झुका दिया था। (कुरैशी,उक्त, पृ.158)

असहयोग के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, गांधीजी ने कहा, ''भारत के मुसलमान सम्माननीय व्यक्ति और अपने पैगंबर के

LOANS
'सरल' ऋण
हिसाबों की झंझट से मुक्ति
सिर्फ १०.५०% से
होम लोन
आपके अपने घर का सपना करें साकार
कम किस्त और लंबी अवधि का ऋण
सिर्फ ८.२५% से
तत्काल सोना ऋण
प्रोसेसिंग चार्ज और बीमा चार्ज से मुक्ति
सिर्फ १०.००% से
मोबाईल बैंकिंग
बैंकिंग किजीए टेक्नोलोजी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से
ASBA, BHIM, भारत बिल पेमेन्ट
ATM : डेबिट कम शोपींग कार्ड
केश क्रेडिट
हिसाबों की झंझट से मुक्ति
सिर्फ ९.२५% से
औद्योगिक ऋण
उद्योग के निर्माण के लिए, विस्तरण और आधुनिकीकरण के लिए
निर्माण ९.५०% से
महिला आवेदक को ब्याजदर में १% की विशेष छूट
शीघ्र ही हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें अथवा
मोबाइल ९४२८२ ८६२६८ में मिस्ड कॉल करें और बैंक की योजना की जानकारी प्राप्त करें
राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि.
(मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बैंक)
विनोद शर्मा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जीवणभाई पटेल
उपाध्यक्ष
नलिन वसा
अध्यक्ष
मुख्य तथा पंजीकृत कार्यालय : ''अरविंदभाई मणीआर नागरिक सेवालय'', १५० फीट रींग रोड, रैया सर्कल के पास, राजकोट-५. फोन : ०२८१-३५५५ ५५५ Email : secretary@rnsbindia.com Website : www.rnsbindia.com
छोटे लोगों की बड़ी बैंक

विश्वास के अनुयायियों के रूप में नहीं रह सकते हैं, यदि वे किसी भी कीमत पर इसका सम्मान सुरक्षित नहीं रख पाते हैं तो। पंजाब के साथ क्रूरतापूर्ण और बर्बर व्यवहार किया गया है। और इन दो गलतियों को दूर करने के लिए ही मैंने इस देश के सामने असहयोग की योजना दी है।'' पंजाब का मुद्दा स्पष्ट रूप से एक बाद में आया हुआ विचार था। यह याद किया जा सकता है कि रॉलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भी, गांधीजी ने दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में 'असहयोग के एक हल्के रूप' का भी विरोध किया था। उन्होंने पंजाब के मुद्दे पर सरकार के शांति समारोह संबंधी आदेश का बहिष्कार करने पर विचार करने से भी इनकार कर दिया था। अब एक वर्ष के भीतर, वह जोर-शोर से असहयोग की वकालत कर रहे थे, जबकि साथ ही साथ इसमें पंजाब का मुद्दा भी शामिल था। (मजूमदार, उक्त, पृ.9) असहयोग के संकल्प पर मुस्लिम वोट की संख्या पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वोटों के लिए बड़ी संख्या में कलकत्ता के टैक्सी ड्राइवरों को चोरीछुपे लाया गया। उस सत्र में

सेंट्रल खिलाफत कमेटी ने अपनी प्रचार समिति द्वारा प्रशिक्षित वेतनभोगी व्याख्याताओं, गुप्त कार्यकर्ताओं और दूतों को नियुक्त किया। मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने बड़े शहरों में ड्रिल परेड की। खाकी कपड़ों में चाकू - भाले से लैस कार्यकर्ताओं ने खिलाफत के समर्थन में राजनीतिक बैठकें कीं, इसने हिंसा का समर्थन करने वाले आन्दोलन का रूप धारण कर लिया

5,000 से अधिक प्रतिनिधि थे, हालांकि जिनमें से आधे ने मतदान नहीं किया था। असहयोग पर प्रस्ताव, 804 वोट के विरुद्ध 1,826 वोट से पारित हो गया। (खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया : 1919-1924, ए.सी. नीमायर, मार्टिनस निजॉफ, 1972, पृ.109)

अप्रैल, 1920 में सेंट्रल खिलाफत कमेटी द्वारा लाये गए असहयोग प्रस्तावों की तुलना (जो कि गांधीजी द्वारा तैयार किए गए थे) यदि सितंबर,1920 में कांग्रेस के विशेष सत्र द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव से करें, तो पता चलता है कि खिलाफतवादी, कांग्रेस से कहीं आगे जाने के लिए तैयार थे। और लगभग एक साल बाद, जब असहयोग आंदोलन मुसलमानों की शिकायतों का निवारण करने में विफल रहा, गांधीजी ने लिखा, 'अपने धैर्यपूर्ण गुस्से के कारण मुसलमानों ने कांग्रेस और खिलाफत संगठनों से अधिक जोरदार और तत्काल कदम उठाने की मांग करनी शुरू कर दी। मुसलमानों के लिए स्वराज का अर्थ है, और होना भी चाहिए, खिलाफत के सवाल को सफलतापूर्वक हल करने में हिंदुस्थान की योग्यता। इसलिए यदि स्वराज प्राप्ति का मतलब ऐसे कार्यक्रम में अनिश्चित विलम्ब होना है, जिसमें उन्हें यूरोपीय समुद्रों में नपुंसकों की तरह तुर्की का विनाश देखना पड़े, तो मुसलमान प्रतीक्षा करना अस्वीकार करते हैं। इस दृष्टिकोण से सहानुभूति न रखना असंभव है। यदि मुझे कोई प्रभावकारी तरीका समझ में आता तो मैं अविलम्ब प्रसन्नतापूर्वक उसका अनुमोदन कर देता। यदि स्वराज की गतिविधियों को मुल्तवी करने से हम खिलाफत के उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सके तो मैं खुशी से ऐसा करने को तैयार हूं। इस कारण करोड़ों मुसलमानों को जो पीड़ा हो रही है, उसे शांत करने के लिए यदि मुझे असहयोग के बाहर भी कोई मार्ग सूझेंगे तो मैं बड़ी खुशी से उन्हें अपना लूंगा।'' (मजूमदार, उक्त, पृ.96)

कट्टर इस्लामी शिकंजा

सेंट्रल खिलाफत कमेटी ने अपनी प्रचार समिति द्वारा प्रशिक्षित वेतनभोगी व्याख्याताओं को नियुक्त किया, साथ ही, प्रचार-प्रसार करने के लिए गुप्त कार्यकर्ताओं और दूतों को नियुक्त किया। हर शाम, मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने बड़े शहरों की गलियों में ड्रिल और परेड की। खाकी कपड़ों में चाकू और भाले से लैस खिलाफत कार्यकर्ताओं ने खिलाफत की मांगों के समर्थन में राजनीतिक बैठकें कीं और असहयोग ने हिंसा का समर्थन करने वाले आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। 'इस्लाम खतरे में' या 'क्रिश्चियन ताकतों का छल' जैसे अपने पुराने विषय का उपयोग कर, पैम्फलेट्स, कविताओं और वाद-विवाद के द्वारा लोगों की भावनाओं को भड़काया गया। धनराशि की मांग के लिए प्रत्यक्ष अपील के अलावा, सेंट्रल खिलाफत कमेटी ने 'कागजी मुद्रा' जारी की, जो एक रुपये की रसीदों के रूप में थीं, जो आकार-प्रकार में एक-एक रुपये के नोट से मिलती-जुलती थी, लेकिन इसमें उर्दू में कुरान के उद्धरण छपे थे।

उलेमा ने पंथनिरपेक्षता के खिलाफ असहयोग का इस्तेमाल करने की भी इच्छा व्यक्त की; जिसमें विधायी निकायों को उलेमाओं की समिति द्वारा, 'विधर्मी' न्यायालयों को शरिया अदालतों और सरकारी स्कूलों को दारुल उलूम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। जमीयत-उल-उलमा-ए-हिंद ने कुरान और पैगंबर के कथनों पर आधारित एक मुत्तफिक (सामूहिक) फतवा जारी किया जो असहयोग आंदोलन की मांगों का मद-दर-मद समर्थन करता था। (कुरैशी, उक्त , पृ.160-177; यह भी देखें, खिलाफत मूवमेंटः रिलीजियस सिम्बोलिज्म एंड पोलिटिकल मोबिलाइजेशन इन इंडिया, गेल मिनॉल्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1982, पृ. 146) मार्च 1921 को जमीयत-उल-उलेमा ने बरेली में यह निर्धारित किया कि असहयोग के विरोधियों को मजहबी न्यायाधिकरणों के माध्यम से दंडित किया जाए। (कुरैशी, उक्त, पृ. 191) खिलाफतवादियों ने कांग्रेस की विशाल मशीनरी और उसके सभी फंडों पर कब्जा कर लिया, जिसमें तिलक स्वराज फंड भी शामिल था, जिसमें कुल मिलाकर एक करोड़ पांच लाख रुपए थे। (कुरैशी, उक्त, 178;

मिनॉल्ट, उक्त , पृष्ठ 126, 132) खिलाफत फंड के ब्योरों और ऑडिट की मांग मार्च 1920 से बढ़ रही थी, लेकिन जुलाई 1920 तक कुछ भी नहीं हुआ। कई लोग यूरोप में खिलाफत प्रतिनिधिमंडल के भव्य खर्च से हैरान थे। (मिनॉल्ट, उक्त, पृ.137)

अमीर को आमंत्रण

1921 की गर्मियों में खिलाफत के कुछ नेताओं के भाषणों का स्वर पहले की तुलना में अधिक हिंसक हो गया। मुत्तफिक फतवे की प्रतियां, जिसमें सेना की सेवा को हराम घोषित किया गया था, फरवरी से मई 1921 तक गुप्त रूप से वितरित की गई थीं। इस प्रतिबंधित फतवे को भारतीय सेना की कई इकाइयों के बीच पर्चे के रूप में वितरित किया गया। सैनिकों को रिश्वत देने के लिए खिलाफत फंड में से बड़ी धनराशि का उपयोग किया जा रहा था। (कुरैशी, उक्त, पृ.205) 1920-21 में अफगानिस्तान के अमीर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने की साजिश रची गई थी। 18 अप्रैल,1921 को मुहम्मद अली ने मद्रास में 'भारत पर अफगान आक्रमण की स्थिति में भारतीय मुसलमानों के कर्तव्यों' के विषय पर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमीर ने भारत को अधीन बनाने के लिए आक्रमण किया तो मुस्लिमों को इस हमले का विरोध करना चाहिए। लेकिन अगर उसका उद्देश्य इस्लाम और खलीफा के उत्पीड़कों को हराने के लिए था, तो यह भारतीय मुस्लिमों का कर्तव्य होगा कि वे भारत सरकार से सभी सहयोग वापस ले लें, यहां तक कि अफगानों के साथ मिलकर इस्लाम की लड़ाई लड़ें। इस विचार के कारण हिंदुओं में बेचैनी बढ़ गई। गांधीजी ने यंग इंडिया में लिखा,''मैं एक तरह से अफगानिस्तान के अमीर की मदद जरूर करूंगा, अगर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, मैं खुलकर अपने देशवासियों से कहूंगा; कि एक ऐसी सरकार की सहायता करना अपराध होगा, जिसने सत्ता में बने रहने हेतु राष्ट्र का विश्वास खो दिया है।'' (नीमायर, उक्त, पृ. 129-130)

उ.प्र. के गवर्नर बटलर ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को दिए एक नोट (12 जनवरी 1922) में यह निष्कर्ष निकाला था कि 'इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लमान उपद्रवी तत्व हत्या और किसी भी तरह की हिंसा के लिए तत्पर हैं।' कई स्थानों पर अवज्ञा की भावना भीड़ और पुलिस के बीच मुठभेड़ में परिवर्तित हो गई, विशेष रूप से उ.प्र. और बंगाल में। (कुरैशी, उक्त, पृ.221)। मुस्लिम रक्त-पिपासा के बारे में बटलर के शब्द भविष्यवाणी साबित हुए!

चौरीचौरा नरसंहार

4 फरवरी, 1922 को गोरखपुर जिले के चौरीचौरा थाने पर 3000-5000 प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने चढ़ाई कर दी। इस मुठभेड़ में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया जिसके जवाब में पुलिस ने पहले हवा में और फिर भीड़ पर गोलियां चलाईं। जब भीड़ को पता चला कि पुलिस के पास गोला-बारूद की कमी है, तो उसने पुलिस को भागने पर मजबूर कर दिया। इनमें से कुछ बाहर खेतों में भाग गए जबकि कुछ ने थाने की इमारत में शरण ली। भीड़ ने थाना भवन में आग लगा दी, जिसमें सभी 21 पुलिस वाले और चौकीदार मारे गए। सब-इंस्पेक्टर के एक नौकर, जो एक छोटा लड़का था, की भी हत्या कर दी गई। ज्यादातर पुलिसकर्मियों को लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से पीट-पीटकर मार डाला गया और कई शवों पर भालों के निशान भी थे। गांधीजी ने सार्वजनिक रूप से इस हिंसा पर पश्चाताप किया और अपने आंदोलन को अचानक बंद कर दिया। (कुरैशी, उक्त, पृ. 223) सबाल्टर्न इतिहास की आड़ में, चौरीचौरा की घटना को किसानों के प्रकोप के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए शाहिद अमीन द्वारा लिखित इवेंट, मेटाफोर, मेमोरीः चौरी चौरा, 1922-1992 (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1995) का अध्ययन करने की आवश्यकता है। चौरी चौरा आगजनी करने वालों की मजहबी प्रेरणाएं बढ़ा-चढ़ा कर दिखाई गई हैं। लेकिन इसी किताब से उद्धृत तथ्य तो झूठ नहीं बोल सकते। 1921-22 की सर्दियों में, खिलाफत और कांग्रेस स्वयंसेवी संगठनों को एक समग्र नेशनल वॉलंटियर कोर में मिला दिया गया था। 1921 के मध्य में, चौरीचौरा थाने के एक मील पश्चिम में एक गांव छोटकी डुमरी में ऐसे वॉलंटियरों की एक ग्राम इकाई (मंडल) स्थापित की गई थी। चौरा के एक व्यक्ति लाल मोहम्मद साई ने गोरखपुर जिला कांग्रेस और खिलाफत समितियों के एक पदाधिकारी को इस ग्राम की इकाई की स्थापना के लिए आमंत्रित किया था। खिलाफत के प्रमुख मौलवी सुभानुल्लाह ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। (अमीन, उक्त, पृ.14-16)

वह शनिवार का दिन था जब खाल और चमड़े के लिए विशेष हाट भोपा में लगा हुआ था, जो रेल गोदाम के नजदीक था। भोपा में आस-पास के गांवों के अधिकांश मुस्लिम किसान इस चमड़े की हाट में आते थे। भोपा के मुस्लिम प्रभुत्व को एक मस्जिद द्वारा समझा जा सकता था, जो बाजार के सामने ही थी। अधिकांश हिंदू शनिवार को भोपा से दूर रहते थे, खालों की बदबू इस व्यापार से जुड़े किसी प्रतिबद्ध व्यापारी को छोड़कर, अन्य किसी को यहां से दूर रखने के लिए पर्याप्त थी। (अमीन, उक्त, पृ. 24-25) मेवा लाल (जिसने अपने पिता से यह वृत्तान्त सुना था) ने बताया, ''वहां कहा जा रहा था, तुम क्या मारोगे, हम मारेंगे'। उसके अनुसार 'थाना जलाने में मदनपुर के पठानों का हाथ था, वे सब व्यापारी थे। (अमीन, उक्त, पृ.231) हमलावरों की मजहबी संरचना और प्रेरणाओं को वफादारी से छुपा कर रखा गया है। इन भयावह वर्षों में जोर-जबरदस्ती और नरसंहार का प्रतिनिधित्व करने वाली दो घटनाएं सामने आई। अफगानिस्तान के लिए एक हिजरत (सामूहिक मुस्लिम उत्प्रवास) के रूप में दबाव था; तो नरसंहार ने बर्बर मोपला जिहाद का रूप ले लिया।

(लेखक ने इस्लाम, ईसाई मत, समकालीन बौद्ध-मुस्लिम संबंध, शुद्धि आंदोलन और पांथिक जनसांख्यिकी पर पुस्तकें लिखी हैं)

दीनों पर दया करने वाले दीनदयाल

समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी एक दिन सुखी और संपन्न जीवन बिताए, इसकी कल्पना दीनदयाल जी ने की थी। यह अच्छी बात है कि आज उनकी इस कल्पना को पूरा करने के लिए कई सरकारें काम कर रही हैं।

■ प्रो. रसाल सिंह

सहृदयता, बुद्धिमता, सक्रियता एवं अध्यवसायी वृत्ति वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक व्यक्ति नहीं, अपितु एक विचार और जीवनशैली हैं। राष्ट्र एवं समाज के प्रति आजीवन समर्पित रहने वाले पंडित जी ने अपने मौलिक चिंतन से राष्ट्र-जीवन को प्रेरित और प्रभावित किया। वे 'राष्ट्रधर्म प्रकाशन' के संस्थापक एवं 'राष्ट्रधर्म', 'पाञ्चजन्य', 'दैनिक स्वदेश' व 'तरुण भारत' जैसी राष्ट्रवादी पत्र-पत्रिकाओं के प्रेरणास्रोत भी थे। भारतीय समाज-जीवन को सुखी, संपन्न एवं मंगलकारी बनाने के निमित्त उन्होंने 'एकात्म मानवदर्शन' व 'अन्त्योदय' की अद्भुत संकल्पना प्रस्तुत की। उनके चिंतन के मूल में लोकमंगल एवं राष्ट्र-कल्याण का भाव समाहित है। उन्होंने राष्ट्र को धर्म, अध्यात्म एवं संस्कृति का सनातन पुंज बताते हुए राजनीति की नई व्याख्या की। वे गांधी, तिलक एवं सुभाष की परंपरा के वाहक थे। वह दलगत एवं सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर वास्तव में एक ऐसे राजनीतिक

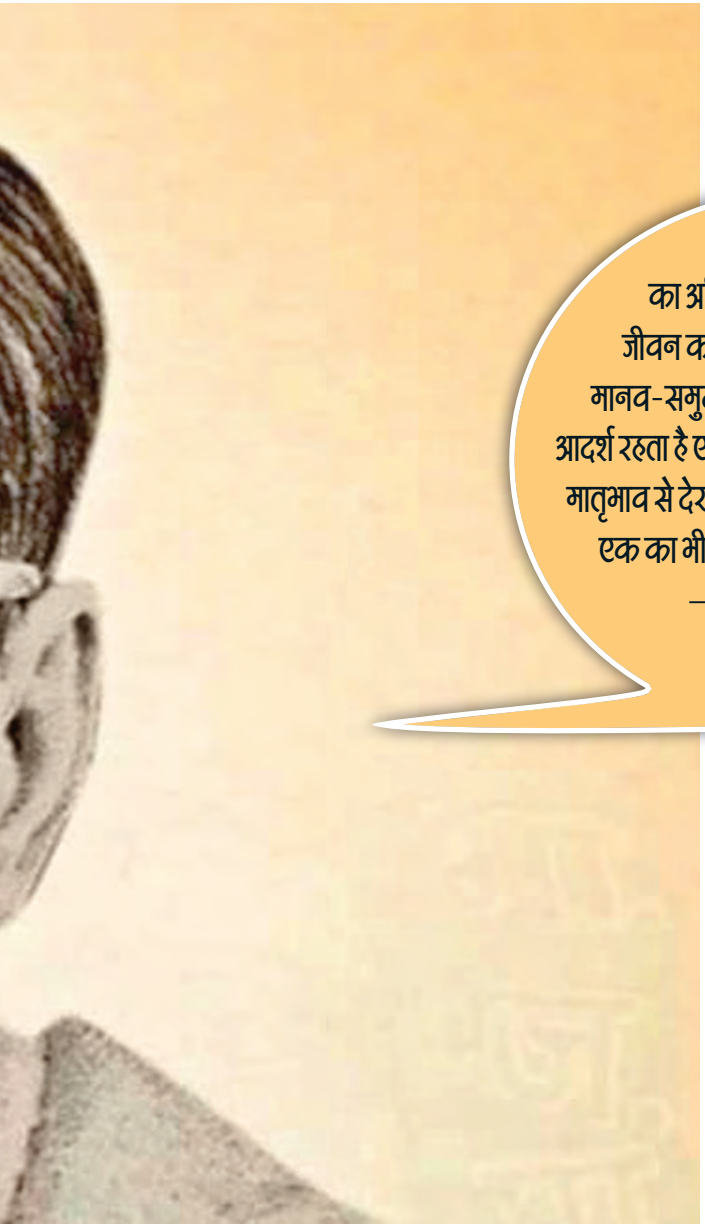

> राष्ट्र
> का अस्तित्व उसके नागरिकों के
> जीवन का ध्येयभूत आधार है। जब एक
> मानव-समुदाय के समक्ष एक व्रत, विचार या
> आदर्श रहता है एवं वह समुदाय किसी भूमि विशेष को
> मातृभाव से देखता है तो राष्ट्र कहलाता है। इनमें से
> एक का भी अभाव रहा तो राष्ट्र नहीं बनेगा।
> –पं.दीनदयाल उपाध्याय

दर्शन को विकसित करना चाहते थे जो भारत की प्रकृति एवं परंपरा के अनुकूल हो एवं राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने में समर्थ हो। अपनी व्याख्या को उन्होंने 'एकात्म मानववाद' का नाम दिया। एक ओर उन्होंने जहां समाजवाद, मार्क्सवाद एवं पूंजीवाद सरीखी अभारतीय विचारधाराओं को भारतीय चिंतन-परंपरा, भारतीय दृष्टिकोण एवं भारतीय जीवन-शैली के सर्वथा प्रतिकूल माना, उन्हें अस्वीकार किया, वहीं, दूसरी ओर भारतीय मानस के अनुकूल 'एकात्म मानवदर्शन' व 'अन्त्योदय' की संकल्पना प्रस्तुत कर भारत को भारत की दृष्टि से देखने-समझने का एक सार्थक सूत्र भी दिया।

'वसुधैव कुटुम्बकम्' की मान्यता से अनुप्राणित उनका चिंतन 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' भाव-साधना का सिद्धांत है। उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की प्रस्तावना करते हुए बताया कि ये अन्यान्योश्रित हैं। वे उत्पादन में वृद्धि, उपभोग में संयम और वितरण में समानता के पक्षधर थे। व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि की एकात्मता और शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के उन्नयन की चिंता उनका मूल ध्येय है। अभारतीय विचारधाराओं में मानव-मात्र को टुकड़ों में बांट कर देखने की पद्धति अपनाई गई है। अतः वहां सम्यक मूल्यांकन का कोई अवकाश नहीं होता। दीनदयाल जी का स्पष्ट मत है कि एकांगी होकर मनुष्य को केवल 'आर्थिक प्राणी' के रूप में देखने की परंपरा नितांत अभारतीय है। इससे मानव-सभ्यता के विकास के उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो किसी राष्ट्र को 'परम वैभव' तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होते हैं। उनकी दृष्टि में मनुष्य को सर्वप्रथम 'मनुष्य' ही माना जाना चाहिए। उसकी समस्त आवश्यकताओं, उसके जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक आयामों को ध्यान में रखकर चिंतन करते हुए संतुलित-विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए।

दीनदयाल जी भारत की 'चिति' और 'विराट' को अपने चिंतन-मनन के केंद्र में रखते हैं।

उनकी स्पष्ट धारणा है कि हमें अपनी प्राचीन संस्कृति का विचार अवश्य करना चाहिए। किंतु हम इस बात के प्रति भी सचेत रहें कि हम पुरातत्ववेत्ता नहीं हैं। हमारा ध्येय अपनी संस्कृति का संरक्षण करना ही नहीं, अपितु उसे गति देकर सजीव व सक्षम बनाए रखना भी होना चाहिए। हमें अपनी रूढ़ियां समाप्त करनी चाहिए। अपनी कमियों की परख कर उनमें सुधार करना चाहिए। सामाजिक जीवन में मौजूद भेदभाव, छुआछूत एवं अस्पृश्यता जैसी विभेदकारी धारणाओं को तोड़ना चाहिए। हमें प्रत्येक मनुष्य से सबसे पहले मनुष्य के रूप में जुड़ना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक एकता एवं राष्ट्र की एकता के लिए उपरोक्त विभेदकारी विचार सर्वथा घातक है।

दीनदयाल जी की दृष्टि में धर्म, अर्थ एवं काम की पूर्ति व इनके सामंजस्य से मोक्ष की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इनमें से किसी एक के प्रति भी विशेष आग्रह

या असंतुलन व्यक्ति के जीवन को समस्याग्रस्त बना सकता है। दीनदयाल जी अपने पूरे चिंतन में बारम्बार इस विचार पर बल देते हैं, ''मानव केवल एक व्यक्ति मात्र नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा का समुच्चय है। व्यक्ति केवल एकवचन 'मैं' तक सीमित नहीं, उसका बहुवचन 'हम' से भी अभिन्न संबंध रखता है। अतः हमें समाज व समष्टि का विचार करना होगा।''

वास्तव में, दीनदयाल जी व्यष्टि एवं समष्टि या कहें कि व्यक्ति एवं समाज को एक-दूसरे की सापेक्षता में देखने के आग्रही हैं। यह विचार पश्चिम के दार्शनिक-विचारों से भिन्न है। उनकी दृष्टि में, ''मानव न केवल व्यक्ति है, मानव न केवल समाज है, वरन् मानव व्यक्ति एवं समाज की एकात्मता में से पैदा होता है। व्यक्ति एवं समाज को बांट दें तो मानव मर जाता है। अस्तित्व में ही नहीं आता। व्यष्टि एवं समष्टि एकात्म इकाई है। इस एकात्म इकाई का नाम मानव है। इसलिए मानव को सुखी करना है तो व्यक्तिवादी होकर नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्तिवादी समाज की उपेक्षा करता है। समाजवादी होकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि समाजवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुचल देता है।'' स्पष्ट है कि व्यष्टि से समष्टि एवं परमेष्टि तक पहुंचने की मनुष्य की यात्रा अलग-अलग खण्डों में विभाजित नहीं है। उसे अलग-अलग घेरे हुए नहीं है। यह एक-दूसरे से पूर्णतः असंबद्ध नहीं है। वह एक ही केंद्र से निसृत समग्र जीवन में सातत्य के साथ प्रवाहमान कहीं पर भी खंडित न होने वाला आवृत है। 'एकात्म मानवदर्शन' व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि व परमेष्टि तक की इसी यात्रा, इसी संबद्धता, मानव-जीवन की इसी समग्रता, इसी सातत्य व प्रवाह एवं इसी आवृत को समझने का सहज-सूत्र है।

समाज 'स्वयंभू' है। जिस प्रकार व्यक्ति पैदा होता है, उसी प्रकार समाज भी पैदा होता है। व्यक्ति मिलकर कभी समाज को नहीं बनाते। .....वास्तव में समाज तो एक ऐसी सत्ता है, जिसकी अपनी आत्मा है, जिसका अपना एक जीवन है, इसलिए यह भी उसी प्रकार से जीवमान सत्ता है, जैसे मनुष्य जीवमान सत्ता है।

'एकात्म मानवदर्शन' की संकल्पनाकार दीनदयाल जी के चिंतन का फलक बहुत व्यापक एवं सुगठित है। वे एक साथ व्यक्ति, समाज, राजनीति, धर्म, राष्ट्र आदि न जाने कितने विषयों पर विचार करते हैं। किंतु प्रत्येक जगह उनके विचारों में एक सह-संबंध, पारस्परिकता एवं नयापन परिलक्षित होता है। समाज के विषय में वे लिखते हैं, ''समाज 'स्वयंभू' है। जिस प्रकार व्यक्ति पैदा होता है, उसी प्रकार समाज भी पैदा होता है। व्यक्ति मिलकर कभी समाज को नहीं बनाते। .....वास्तव में समाज तो एक ऐसी सत्ता है, जिसकी अपनी आत्मा है, जिसका अपना एक जीवन है, इसलिए यह भी उसी प्रकार से जीवमान सत्ता है, जैसे मनुष्य जीवमान सत्ता।'' वास्तव में, यह समाज की भौतिक व्याख्या नहीं, अपितु तात्विक व्याख्या है। इसलिए यहां समाज को पश्चिम के 'द्वंद्वात्मक भौतिकवाद' के सूत्र के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। 'राष्ट्र' पर चिंतन करते हुए पंडित जी ने लिखा है, ''राष्ट्र का अस्तित्व उसके नागरिकों के जीवन का ध्येयभूत आधार है। जब एक मानव-समुदाय के समक्ष एक व्रत, विचार या आदर्श रहता है एवं वह समुदाय किसी भूमि विशेष को मातृभाव से देखता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। इनमें से एक का भी अभाव रहा तो राष्ट्र नहीं बनेगा।''

स्पष्ट है कि भारतीय चिंतन परंपरा में 'राष्ट्र' केवल भौतिक सीमाओं पर आधारित भौगोलिक इकाई या भौतिक सरणी नहीं है। इसका संबंध समानधर्मी, समानदर्शी एवं समानुभूति पर आधारित सामूहिक समभाव से है। यही कारण है कि पंडित जी 'राष्ट्र' की ऐसी परिकल्पना कर 'भू-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' को महत्त्व देते हैं। 'भू-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की विचार-सरणी को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति समानव्रती, सामान दर्शन व सामान मूल्यों को मानने वाला होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक प्रत्येक भारतीय एक-दूसरे से 'एकात्म-भाव' से जुड़ा हुआ है। भले ही उसकी भाषा अलग हो, संस्कृति अलग हो, रहन-सहन अलग हो, पंथ-संप्रदाय अलग हो, किंतु वह संपूर्ण भारतभूमि के कण-कण को पवित्र मनाता है। सबके हित की कामना करता है।

इतना ही नहीं, समान व्रत, समान दर्शन, समान मूल्यों को मानने वाले व्यक्ति संसार में जहां भी उपस्थित हैं, वे सभी इस भारत-भूमि, इस राष्ट्र के समभाव एवं संकल्पना में समाहित हैं। इस प्रकार दीनदयाल जी की 'राष्ट्र' की संकल्पना व 'भू-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की विचार-प्रणाली भी संपूर्णता एवं सामूहिकता की भावना से अनुप्राणित है। यह दृष्टि पश्चिम की 'नेशन' एवं 'नेशनलिज्म' अर्थात 'राष्ट्र' एवं 'राष्ट्रवाद' की दृष्टि से सर्वथा भिन्न है। वे 'एकात्म मानव-दर्शन' के तहत 'राष्ट्र' की भी तात्विक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार, ''राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है। उसका एक शास्त्रीय नाम है। इसे 'चिति' कहा गया है।'' इस प्रकार दीनदयाल जी 'राष्ट्र' की संकल्पना में व्यक्ति को एक साधन के रूप में देखते हैं। व्यक्ति स्वयं के अतिरिक्त अपने राष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। स्पष्ट है कि दीनदयाल जी द्वारा प्रस्तावित 'एकात्म मानव-दर्शन' एक वायवीय विचार नहीं है, बल्कि एक कालजयी सिद्धांत है।

(लेखक जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में 'छात्र कल्याण' के अधिष्ठाता हैं)

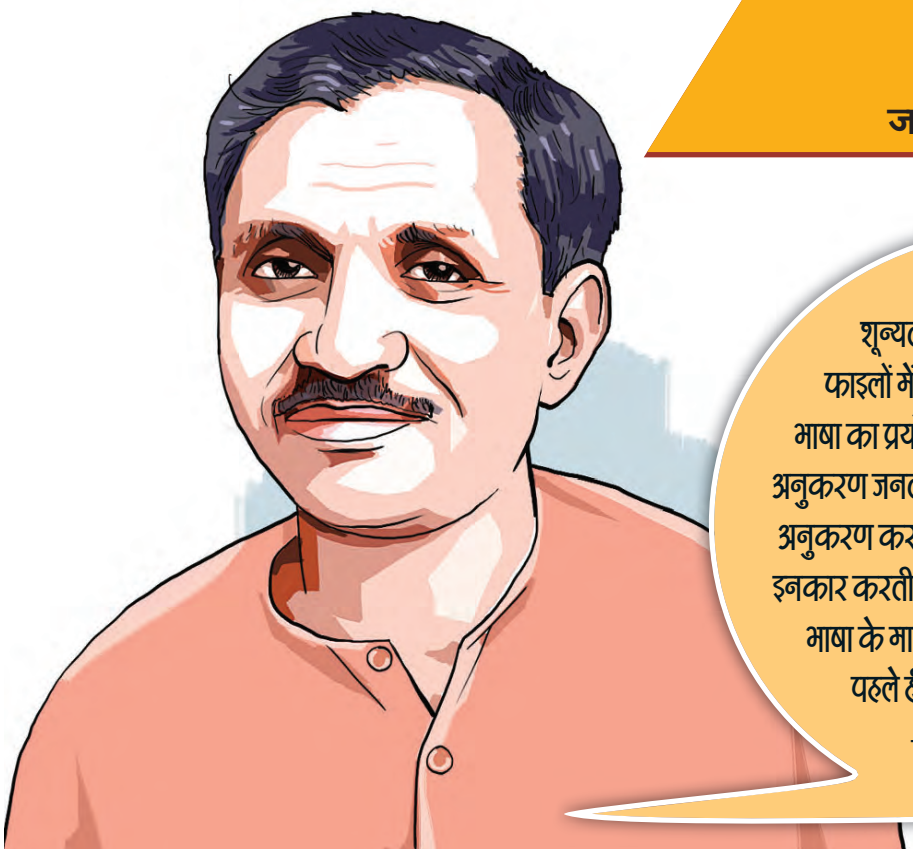

भाषा
शून्यता में नहीं पनपती। सरकारी फाइलों में विकसित नहीं होती। हमें अपनी भाषा का प्रयोग स्वयं करना होगा। सरकार का अनुकरण जनता नहीं करती, सरकार को जनता का अनुकरण करना होगा। यदि सरकार ऐसा करने से इनकार करती है तो वह अपनी जड़ें खो देती है। अगर भाषा के मामले में सरकार की चलती तो बहुत पहले ही फारसी देश की भाषा होती।
-दीनदयाल उपाध्याय

भारतीय भाषाओं के प्रबल पक्षधर

पं. दीनदयाल उपाध्याय मानते थे कि जब तक भारत के लोग अपनी भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उनका विकास नहीं होगा और प्रभाव नहीं बढ़ेगा। वे यह भी कहते थे कि सरकारी संरक्षण में कोई भाषा विकास नहीं कर सकती। वे सभी भारतीय भाषाओं के विकास के प्रबल पक्षधर थे

■ प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी

भारतीय राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। वे कई वर्ष तक जनसंघ के महामंत्री और अध्यक्ष भी रहे। उपाध्याय जी राजनेता ही नहीं, एक महान चिंतक, विचारक और संगठनकर्ता एवं पत्रकार और लेखक भी थे। यह कहना असमीचीन न होगा कि वे राजनेता कम, मनीषी अधिक थे। वे पूर्णतया भारतीयता और भारतीय संस्कृति के उपासक थे। वस्तुतः वे राष्ट्र जीवन-दर्शन के निर्माता ही थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल प्रस्तुत करते हुए एकात्म मानववाद की अवधारणा प्रस्तुत की। आर्थिक रचनाकार के रूप में उनका मत था कि सामान्य मानव अर्थात् जन-सामान्य का सुख और समृद्धि ही आर्थिक विकास के मुख्य उद्देश्य होने चाहिए।

भाषा नीति और शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में दीनदयाल जी के विचार बहुत ही गंभीर, चिंतनपरक, सुघड़ और लोकोपयोगी हैं। उन्होंने बहुभाषी भारत की भाषायी स्थिति को समझते हुए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जो आज भी प्रासंगिक और सार्थक हैं। वे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रबल समर्थक थे और अंग्रेजी के पक्ष में कतई नहीं थे। 1961 में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें भारतीय संस्कृति के पुरोधा और राजनेता श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने अंग्रेजी को भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रेरणास्रोत और उपकरण माना था। दीनदयाल जी ने ऑर्गनाइजर (23 अक्तूबर,1961) को दिए एक साक्षात्कार में उनके इस मत का जोरदार शब्दों में खंडन करते हुए कहा था, ''अंग्रेजी को भारत की राष्ट्रीय चेतना का प्रेरणास्रोत और उपकरण मानना हमारी राष्ट्रीयता के

सच्चे और सकारात्मक दर्शन की उपेक्षा करना है। ऐसा लगता है कि मैकाले की भविष्यवाणी सही निकल रही है कि भारत के अंग्रेजीदां लोग नाम के ही भारतीय हैं। ये लोग न तो भारत की आत्मा को पहचान पाएंगे और न ही सकारात्मक आदर्शों को पाने के लिए जन-समाज को प्रेरित कर पाएंगे।'' एक अन्य साक्षात्कार में (ऑर्गनाइजर, 26 अप्रैल, 1965) वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, ''एकता जनता की इच्छा-शक्ति पर आधारित होती है। अगर जनता मिल-जुलकर एक-साथ रहे, अपने राष्ट्र के प्रति उसकी आस्था और दृढ़ संकल्प हो तो जनता की संकल्प-शक्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार को भी हर हालत में एकता को बनाए रखना है।'' ब्रिटिश शासन में भारत की एकता में अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा के योगदान को अस्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था, ''ब्रिटिश शासन में यह एकता केवल कृत्रिम और नकारात्मक थी। सकारात्मक और रचनात्मक एकता केवल हमारी अपनी भाषाओं से ही संभव हो सकती है।''

उपाध्याय जी ने अपने एक वक्तव्य में अंग्रेजी का विरोध करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था, ''अंग्रेजी की लड़ाई केवल हिंदी के लिए नहीं है, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के हित के लिए भी है। अंग्रेजी को हटाने से केवल हिन्दी का भला नहीं होगा, बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं का भी हित होगा। अंग्रेजी के रहने से न तो कोई भारतीय भाषा पनप पाएगी और न ही विकसित हो पाएगी।'' उनकी यह भी मान्यता थी कि तमिल, बांग्ला तथा अन्य भारतीय भाषाओं को हिन्दी ने पीछे नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी ने ही किया है। उनका यह भी मत है, ''भारत में जब तक अंग्रेजी का वर्चस्व रहेगा तब तक हम मुक्त भाव से अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए विदेशी भाषा के चंगुल से अपने आप को मुक्त करना होगा। अंग्रेजी की नकल से विश्व का ज्ञान तो प्राप्त नहीं होगा, वरन् अपनी भाषाओं से अपना अमूल्य ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।''

उपाध्याय जी संस्कृत भाषा के घोर समर्थक थे। संस्कृत को सुष्ठु, उत्कृष्ट और समृद्ध भाषा मानते हुए उन्होंने कहा, ''संस्कृत मात्र अर्थ ही नहीं, अर्थच्छटाओं को भी व्यक्त करने में पूर्णतया सक्षम और समर्थ है जो अन्य भाषाओं में नहीं है। इसलिए तकनीकी शब्दों के निर्माण में संस्कृत की ही सहायता लेना उचित होगा।'' उन्होंने यहां तक कहा कि संस्कृत न केवल भारत तथा पूर्वी एवं दक्षिण एशिया के लिए उपयोगी और समर्थ है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शब्दावली के निर्माण की क्षमता भी इसमें निहित है। संस्कृत की उपयोगिता की चर्चा करते हुए वे कहते हैं, ''साहित्यिक, तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों में संस्कृत जितनी सक्षम है, उतनी उर्दू, हिंदुस्तानी और हिंगलिश नहीं हैं। उर्दू, हिंगलिश आदि भाषाओं का प्रयोग बोलचाल की भाषा के रूप में तो किया जा सकता है, लेकिन उच्चतर स्तर पर नहीं।'' उनका स्पष्ट मत था कि सभी क्षेत्रीय अर्थात् भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाओं का काम कर सकती हैं, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत ही है।

हिंदी को भारत की संपर्क भाषा मानते हुए वे कहते हैं, ''भारत संघ की राजभाषा की भूमिका निभाने में हिन्दी पूर्णतया समर्थ है और क्षेत्रीय भाषाएं अपने-अपने प्रदेश की राजभाषा का काम कर सकती हैं। इससे देश को एक प्रकार का द्विभाषी होना होगा। संघ सरकार के जो कार्यालय राज्यों में स्थित हैं, उन्हें हिंदी और क्षेत्रीय भाषा दोनों का प्रयोग करना होगा।''

कुछ लोग और समुदायों द्वारा हिंदी का विरोध करने पर जब उनसे इस संबंध में प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने बताया (ऑर्गनाइजर, गणतंत्र दिवस विशेषांक, 1965) कि यह एक प्रकार का 'पुनरावृत्त घृणा' फैलाने का भाव है। ऐसे लोगों को समझाना और आश्वस्त करना कठिन हो जाता है। ऐसे लोगों को उन्होंने दो वर्गों में विभाजित किया। पहले वर्ग के लोग एक राष्ट्र, एक संस्कृति, और एक भाषा की अवधारणा के विरोधी होते हैं। इसलिए उनका प्रश्न हमेशा यही रहता है कि हिंदी ही अकेले क्यों? वस्तुतः वे भारत का एक और विभाजन चाहते हैं और इसलिए वे हिंदी को भारतीयों पर साम्राज्यवादी शासन का उपकरण मानते हैं। यह उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। आप उन्हें तब तक आश्वस्त नहीं कर सकते जब तक उन्हें अलगाववादी महत्वाकांक्षा के व्यर्थ और दुर्बल पक्षों के बारे में आश्वस्त नहीं कर लेते। इसलिए हमें इस बारे में संकल्प लेना होगा और प्रयास करना होगा ताकि वे सही दिशा की ओर उन्मुख हो सकें। समझौते के लिए यदि उनकी शर्तें मान ली जाएं तो उन्हें बल मिलेगा, क्योंकि हरेक को प्रसन्न करने की नीति से काम नहीं चलेगा, बल्कि उससे उनकी भूख और बढ़ेगी। अतः उनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा और उनके इरादों को कुचलना होगा।

पंडित जी ने विरोध करने वाले दूसरे वर्ग की बात करते हुए कहा कि ये लोग पूर्णतया राष्ट्रवादी हैं। वे संस्कृत भाषा की वकालत

करते हैं। उनका यह मत सही भी हो सकता है, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि हिंदी का विरोध करने और उसके प्रयोग में बाधा डालने से संस्कृत का भला नहीं होगा। यदि अंग्रेजी को जारी रखा गया और उसका वर्चस्व बना रहा तो संस्कृत बहुत पीछे रह जाएगी।

राष्ट्र का निर्माण जनता ही करती है। इसलिए वही भाषा अपनाई जाए जो सरकार में निर्णायक भूमिका निभा सके और वह हो सकती है जनता की ही भाषा। उनका मत है कि भाषा शून्यता में नहीं पनपती। सरकारी फाइलों में विकसित नहीं होती। हमें अपनी भाषा का प्रयोग स्वयं करना होगा। सरकार का अनुकरण जनता नहीं करती, सरकार को जनता का अनुकरण करना होगा। यदि सरकार ऐसा करने से इनकार करती है तो वह अपनी जड़ें खो देती है। अगर भाषा के मामले में सरकार की चलती तो बहुत पहले फारसी देश की भाषा होती। मुस्लिम शासकों का संदर्भ देते हुए वे कहते हैं कि दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने शताब्दियों तक अपना राजकाज फारसी भाषा में किया लेकिन जनता अपनी भाषाओं में ही अपना काम करती रही।

अंत में मुगल शासकों को जनता की भाषा खड़ी बोली को अपनाना पड़ा। बाद में अदालतों में हिंदी की एक विशिष्ट शैली उर्दू का विकास भी हुआ, लेकिन सरकारी और अदालती भाषा उर्दू को जनभाषा का दर्जा नहीं मिल सका। सूरदास और तुलसीदास ने जनता की भाषा ब्रज और अवधी को प्राथमिकता देकर काव्य-रचना की। उर्दू की साहित्यिक महत्ता का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं, ''साहित्य में उर्दू का विशेष योगदान होने के बावजूद यह राष्ट्रीय पुनर्जागरण की माध्यम भाषा नहीं बन पाई। जनभाषा हिंदी ही राष्ट्रीय पुनर्जागरण का नैसर्गिक चुनाव थी। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भाषा बन गई, स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गई और साथ ही स्वतंत्रता-सेनानियों के रचनात्मक कार्यक्रमों की अभिव्यक्ति बन गई।''

उपाध्याय जी ब्रिटिश साम्राज्य पूर्व के इतिहास पर अपनी दृष्टि डालते हुए कहते हैं, ''हिंदी न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हो रहे संघर्ष तक ही सीमित थी, बल्कि उससे पहले मुगल शासकों के विरुद्ध भी अपनी भूमिका निभा रही थी। शिवाजी के दरबार में भूषण जैसे कवियों ने हिंदी में वीर रस की कविताओं से इसमें योगदान किया।''

स्वतंत्रता के बाद हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई, उसे पंडित जी जनता की सरकार मानते हैं। अगर जनता अपनी भाषा की उपेक्षा करती है तो कोई भी सरकार उस भाषा की न तो रक्षा कर पाएगी और न ही उसे प्रोत्साहन देगी। वे इस बात की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि जिस भाषा का विकास सरकार के संरक्षण में होता है, वह भाषा जनता की भाषा का गौरव खो बैठती है। इसलिए पंडित जी उस भाषा में जनता का प्रतिबिंब देखते हैं जो अपने-आप में जीवंत होती है और उसका साहित्य समृद्ध होता

> **हिन्दी न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हो रहे संघर्ष तक ही सीमित थी, बल्कि उससे पहले मुगल शासकों के विरुद्ध भी अपनी भूमिका निभा रही थी। शिवाजी के दरबार में भूषण जैसे कवियों ने वीर रस की कविताओं से हिन्दी भाषा में योगदान दिया था।**
>
> **– पं. दीनदयाल उपाध्यायाय**

है। हिंदी साहित्य के रीति काल में उनकी यह मान्यता संपुष्ट हो जाती है कि इस काल में ब्रज भाषा सामंतों और राजाओं के संरक्षण में ही विकसित हुई थी और उसके साहित्य में जन भावना दिखाई नहीं देती।

विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र में अंग्रेजी भाषा को सम्मिलित करने को लेकर में उपाध्याय जी सहमत नहीं थे। त्रिभाषा सूत्र लागू करने पर उनका मत था कि इस त्रिभाषा सूत्र में अगर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा लागू होगी तो उससे संस्कृत को बाहर कर दिया जाएगा, जो क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी हानिकारक होगा। यदि हिंदी को लिया जाता है तो अंग्रेजी का वर्चस्व नहीं हो पाएगा और उसका स्तर भी ऊंचा नहीं हो पाएगा। अंग्रेजी को एक विषय के रूप में पढ़ाने के बारे में उनका कथन है कि क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं को साझे रूप में रखना भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए उचित नहीं है। तत्कालीन सरकार की ढीली-ढाली और विवादास्पद भाषा-नीति से पता चलता है कि सरकार का हिंदी के प्रति उदासीन रवैया स्पष्ट झलकता है और इसी कारण हिंदी को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसलिए हिंदी को अब सक्रियता की भाषा बनाना है और विदेशी भाषा अंग्रेजी को बनाए रखने की सरकार की जो नीति है, वह एक षड्यंत्र है जिसका विरोध जनता को लोकतांत्रिक तरीके से करना होगा।

इस प्रकार उपाध्याय जी के भाषा संबंधी विचार गंभीर, सुलझे हुए और विद्वतापूर्ण हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस विषय पर गहन चिंतन कर अपने विचार व्यक्त किए हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा की दृष्टि से भारत की प्रगति हो सकती है और वह भी केवल अपनी भाषाओं में हो सकती है। वे संस्कृत, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रबल समर्थक रहे हैं। वे अपनी भाषाओं के विकास और संवर्धन में ही राष्ट्र का विकास और संवर्धन मानते थे। उनकी यही आकांक्षा थी कि हिंदी और भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय संघर्ष और राष्ट्रीय उपलब्धि की प्रतीक बनी रहें। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी संघर्ष और विरोध की भाषा रही है। अब यह विकास, संवर्धन और गत्यात्मकता की भाषा रहे।

(लेखक भाषा विज्ञान के प्राध्यापक रहे हैं)

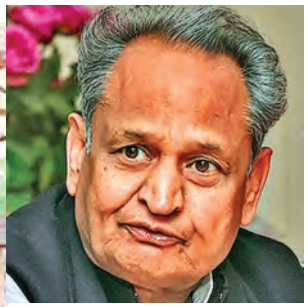

राजस्थान की एक गोशाला। राज्य में गोशालाओं को अनुदान नहीं मिलने से गोवंश संकट में हैं। (प्रकोष्ठ में) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

मुसलमानों को पुचकारा, हिंदुओं को दुत्कारा

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मदरसा बोर्ड को वैधानिक दर्जा दे दिया, वहीं गोशालाओं को मिलने वाले अनुदान में कटौती कर बता दिया कि उसके लिए वोट बैंक की राजनीति ही सब कुछ है

■ राघवेंद्र सिंह

राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार जम कर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। पिछले दिनों इस सरकार ने मदरसा बोर्ड को अनेक अधिकार दे दिए हैं, वहीं गोशालाओं का मिलने वाले अनुदान को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे हिंदुओं में उबाल है, तो मुसलमान बड़े खुश हैं। हिंदू ठगा महसूस कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'वैदिक शिक्षा बोर्ड' के गठन की घोषणा की थी। उनकी इस घोषणा का कई हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों ने स्वागत किया था, लेकिन आज वे संगठन ठगा महसूस कर रहे हैं। वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन तो हुआ नहीं, हां पिछले दिनों गहलोत ने मदरसा बोर्ड को वैधानिक मान्यता दे दी। यह सब उस वक्त किया जा रहा है जब भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 लाकर देश में शैक्षिक सुधारों की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने मदरसों के संचालन के लिए राजकीय बोर्ड का गठन कर नई शिक्षा नीति को मदरसों में लागू नहीं करने को अघोषित चुनौती दे दी है।

इस संबंध में गत 24 अगस्त को विधानसभा के विशेष सत्र में एक विधेयक पारित किया गया। इसके उद्देश्य व कारणों में लिखा गया है, ''निर्धन मुस्लिम परिवारों के बच्चों को अरबी, इस्लामी, आधुनिक और वैज्ञानिक अध्ययनों के साथ ही मजहबी शिक्षा देने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में मदरसे संचालित हैं। ऐसे में इनकी स्वायत्तता के लिए स्वतंत्र बोर्ड की आवश्यकता प्रतीत होती है।'' अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सालेह मोहम्मद के नेतृत्व में मदरसा बोर्ड गठन का विधेयक पारित होने के बाद मुस्लिमों में कांग्रेस सरकार के प्रति अपार प्रेम उमड़ता दिख रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति ले आई है तो फिर मजहबी शिक्षा के लिए मदरसा बोर्ड के गठन का औचित्य क्या है? इससे स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए ही मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है, जबकि प्रदेश में वैदिक शिक्षा के लिए संचालित गुरुकुल व वेदशालाओं के उत्थान के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। ऐसे में राजस्थान सरकार की तुष्टीकरण राजनीति सभी को समान शिक्षा के अधिकार पर भारी पड़ रही है। सरकार सर्वसमाज के कल्याण के बड़े-बड़े दावे तो करती है लेकिन मजहबी शिक्षा के लिए मदरसा बोर्ड बनाकर उसने अपना वास्तविक

चेहरा दिखा दिया है।

जानकारी के अनुसार पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में संचालित 3,240 मदरसों को दी जाने वाली करीब 9 करोड़ रु. की सहायता रोक दी गई थी। ऐसे में वित्तीय सहायता नहीं मिलने से बंद होने के कगार पर पहुंचे मदरसों को प्रदेश सरकार ने राज्य निधि से 188 लाख रुपए दिए थे। यहां के मदरसों में करीब 2,00000 छात्र हैं, जबकि यहां 6,500 मदरसा पैरा शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश में पिछले 17 साल से मदरसा बोर्ड महज एक प्रशासनिक आदेश से चल रहा था। 17 साल बाद मदरसा बोर्ड के प्रस्ताव को अब वैधानिक मंजूरी देकर मदरसा बोर्ड एक्ट राजस्थान विधानसभा में पारित कर दिया गया है।

मदरसा बोर्ड के गठन का विरोध करते हुए पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, ''दो महीने पहले हमने राज्य सरकार से मांग की थी कि तब्लीगी जमात और मदरसों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इनकी शिक्षा और पाठ्यक्रम की पद्धति देश के खिलाफ है, लेकिन इसके विपरीत सरकार ने मदरसों को स्वायत्तशासी बना दिया। मदरसों को वे अधिकार दे दिए गए जो शिक्षा विभाग के विद्यालयों को हैं। मदरसा बोर्ड को संपूर्ण स्वायत्तशासी बना देना यानी कक्षा का वर्गीकरण, पाठ्यक्रम और शिक्षक आदि मदरसा बोर्ड खुद तय करेगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता।''

कम किया गोशालाओं का अनुदान

गत दिनों राजस्थान सरकार ने गोसंरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2016 एवं राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1988 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 3-ख को संशोधित कर स्टांप डयूटी से वसूल की जाने वाली राशि का उपयोग आपदा निधि में करने का प्रावधान कर दिया है। इससे राज्य की गोशालाओं को मिलने वाला अनुदान कम होगा तथा गोशालाओं का संचालन मुश्किल में पड़ जाएगा। इसके विरोध में गोवंश संरक्षण संघर्ष समिति ने संत समाज व गोसेवकों के साथ आंदोलन शुरू कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में सरकार द्वारा पंजीकृत करीब 1980 गोशालाओं को 2014 तक रोजाना चारा खर्च दिया जा रहा था। राज्य सरकार तीन साल से कम आयु के गोवंश के लिए 16 रुपए और बड़े गोवंश के लिए 32 रुपए का अनुदान देती थी। इन गोशालाओं में पोषित होने वाले करीब 6,00000 गोवंश के हितों को ध्यान में रखते हुए 2015 में भाजपा सरकार ने गोशाला गोपालन निदेशालय का गठन किया तथा गोशालाओं को मिलने वाले प्रति पशु अनुदान को बढ़ाया। सरकार ने प्रति गोवंश के हिसाब से अनुदान बढ़ाकर छोटे गोवंश के लिए 35 रुपए तथा बड़े गोवंश का अनुदान 32 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया था। गोशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2016 में स्टांप डयूटी पर 2 फीसदी सेस लगाने के लिए गोसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम विधानसभा में पारित किया था। अब गहलोत सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है। इसके विरोध में गोशाला संचालक आवाज उठाने लगे हैं। गो ग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित दाधीच ने बताया कि सभी के संगठित प्रयास से राज्य स्तर पर विश्व हिन्दू परिषद के नेतृत्व में संघर्ष समिति का गठन किया गया है। समिति ने निर्णय लिया है कि राजस्थान की 4,000 ग्राम पंचायतों में संचालित गोशालाओं के साथ उन ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्रामसेवकों से पत्र लिखवाए जाएंगे।

वहीं गोवंश संरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश मंत्री सुरेश उपाध्याय ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की पंजीकृत गोशालाओं को 180 दिन की सहायता ही मिल पाई है, करीब 1520 गोशालाएं अभी भी सहायता से वंचित हैं। इस संशोधन के पश्चात् वर्तमान में जिन गोशालाओं को सहायता मिल रही है, उनको भी सहायता नहीं मिल सकेगी। ऐसे में सरकार संशोधन को तुरंत प्रभाव से निरस्त करे एवं 200 गोवंश की बाध्यता समाप्त कर राज्य में पंजीकृत सभी छोटी-बड़ी गोशालाओं को अनुदान राशि जारी करे। इसके साथ ही प्रति गोवंश दी जा रही राशि में वृद्धि कर एक वितीय वर्ष में 365 दिन की सहायता दी जाए।

राजस्थान सरकार की तुष्टीकरण राजनीति सभी को समान शिक्षा के अधिकार पर भारी पड़ रही है। सरकार सर्वसमाज के कल्याण के बड़े-बड़े दावे तो करती है लेकिन मजहबी शिक्षा के लिए मदरसा बोर्ड बनाकर कांग्रेस सरकार ने अपना वास्तविक चेहरा दिखाया है।

राजस्थान गोसेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष महंत दिनेशगिरि महाराज ने कहा कि शास्त्रों में गोसेवा के पैसे को किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग करना गोद्रोह माना गया है। ऐसा ही कार्य राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर रही है, जिसके परिणाम उसे भुगतने होंगे। संशोधित विधेयक के विरोध में प्रदेश भर के गोसेवक एक मंच पर आ गए हैं तथा 21 सितंबर को सभी विधानसभा क्षेत्रों में ज्ञापन व धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई जाएगी।

वहीं भरतपुर स्थित जड़खोह धाम गोशाला से जुड़े संत गोपेशदास महाराज का कहना है, ''हिंदू धर्म में गोसेवा को प्रभु की सेवा के समान माना गया है, लेकिन सरकार द्वारा दिए जाने वाले 180 दिन के अनुदान को बढ़ाने की बजाय पूर्व प्रदत्त अनुदान में कटौती करना पाप करने जैसा है। इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा, भगवान राजस्थान सरकार को सदबुद्धि प्रदान करे।''

अब यह देखना है कि गहलोत सरकार को सद्बुद्धि मिलती है या फिर तुष्टीकरण करने वाला कोई कदम उठाती है। ■

बाहरी मदद से बढ़े चीनी कम्युनिस्ट

अब भले ही चीन के कम्युनिस्ट नेता अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें यहां तक पहुंचाने में अमेरिका और रूस जैसे देशों का ही योगदान है

■ प्रो. कुसुमलता केड़िया

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का संपूर्ण चीन पर कब्जा होने में चीन की आंतरिक शक्तियों के स्थान पर बाहरी शक्तियों की ही मुख्य भूमिका है, क्योंकि कम्युनिस्ट स्वयं ही बाहरी शक्तियों के 'एजेंट' हैं। 17वीं शताब्दी में मिंग शासकों ने जहां खेती और व्यापार के विकास पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं यूरोपीय समूहों ने चारों तरफ फैल कर मिंग शासन के प्रशासकों को भ्रष्ट करने के कई हथकंडे अपनाए और इस कारण प्रशासन खोखला होता चला गया। अफीम की खेती पर बहुत अधिक जोर देने के कारण कई जगह फसलों में गिरावट आई और अकाल की स्थितियां भी आईं। जगह-जगह विद्रोह होने लगे जिसका लाभ यूरोपीय समूहों ने उठाया। मानचूओं ने स्थिति का लाभ उठाकर चीन के कई स्थानों पर कब्जा कर लिया। इस बीच यूरोपीय समूह अपना प्रभाव फैलाते रहे। 18वीं शताब्दी में चीन में 3 प्रमुख सम्राट हुए - कांगसी, योंग झोन और किन लोंग। परंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यूरोपीय व्यापारी चीन में छा गए और चीनी मिट्टी के बर्तनों तथा सूती वस्त्रों की बिक्री यूरोप के बाजारों में बढ़ी। रेशमी वस्त्रों की भी मांग होने लगी।

अलग-अलग हिस्सों में डचों, अंग्रेजों और पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक अड्डे बनाए और वे चीनियों के साथ घुल-मिल गए तथा उनमें फूट को बढ़ावा देते रहे। म्यांमार के जरिए ब्रिटिश समूह म्यांमार से सटे इलाके में तेजी से फैले और चीन तथा ब्रिटेन की मैत्री बढ़ने लगी। मानचूओं के विरुद्ध चीनियों के भीतर ईसाई मिशनरियों ने विद्रोह फैलाया और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित विचार चीन में व्यापक हो गए। इस बीच अफीम युद्ध भी शुरू हुआ अर्थात् अफीम की खेती और व्यापार में एकाधिकार को लेकर इंग्लैण्ड, पुर्तगाल और हालैण्ड आपस में भिड़ गए। जैसा कि जान की ने अपनी पुस्तक 'चाईना : ए हिस्ट्री' के अध्याय 15 में लिखा है, ''ईसाई मिशनरियों की प्रेरणा और किसानों के विद्रोह के मिश्रण से चीन में भयंकर विद्रोह फैल गया। शासन के द्वारा विद्रोहियों को कुचला जाने लगा, कई करोड़ लोग मार डाले गए। हक्का समुदाय के लोग विद्रोहियों में सबसे आगे थे। हक्काओं के बीच ईसाइयों ने गहरी पैठ बनाई और जगह-जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियों तथा मठों को नष्ट करने लगे। इसका नेतृत्व पादरी हांग ने किया।''

इन्हीं विद्रोहियों में से आगे चलकर पहले राष्ट्रवादी और फिर कम्युनिस्ट नेता उभरे। मानचू शासकों को बाहरी आक्रमणकारी शासक बताया जाने लगा जिससे चीन को मुक्त करने का अभियान चला, परंतु इस अभियान को चला रहे लोग स्वयं यूरोपीय ईसाइयत के 'एजेंट' ही थे। इन्होंने बड़े पैमाने पर गुरिल्ला लड़ाकुओं को एकत्रित किया और लड़ाकों की एक नई वेषभूषा तथा रहन-सहन की शैली विकसित की और ईसाइयों के नेता हांग ने खुद को चीन का दैवीय शासक घोषित कर दिया। पहला 'लांग मार्च' हांग ने ही आयोजत किया जो 2 साल तक चला। इसमें विभिन्न ईसाई संस्थाओं ने बहुत धन दिया। फ्रेंच, अमेरिकी तथा ब्रिटिश ईसाई संस्थाओं ने इस अभियान को चलाने में भरपूर मदद की। विद्रोहियों के विरुद्ध चीनी राजा किंग ने ब्रिटेन की नौसेना और सेना की सहायता

कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन को संबोधित करते शी जिनपिंग (फाइल चित्र)

जापान ने रूस को 1905 में हराया था इसलिए रूस जापान से बदला लेना चाहता था और साथ ही चीन को जापान के प्रभाव से मुक्त रखना चाहता था। जापान के विरुद्ध रूस और अमेरिका दोनों अपने-अपने ढंग से चीन की मदद कर रहे थे। अमेरिका ने वहां राष्ट्रवादी समूहों को बढ़ावा दिया और च्यांग काई शेक का साथ दिया, जबकि रूस ने कम्युनिस्ट पार्टी को बढ़ावा दिया और बहुत बड़ी धनराशि पार्टी के विस्तार के लिए दी

मांगी जिसके बदले में ब्रिटेन ने चीन में चुंगी दरों को हटाए जाने और अफीम के व्यापार में एकाधिकार की मांग की। लुटेरों और डकैतों से सुरक्षा के नाम पर ब्रिटेन ने चीन में भी वैसी ही सेना अपने लिए बना ली जैसी भारत में भारतीय सैनिकों को भर्ती कर बना ली थी। इस सेना की मदद से इंग्लैण्ड और फ्रांस ने चीन के अनेक हिस्सों पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी शर्तों पर व्यापार करने लगे।

इसी बीच जापान ने चीन पर आक्रमण किया और उसके बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। रूस भी मौके का फायदा उठाकर चीन में हस्तक्षेप करने लगा। रूस ने मानचू शासकों से संधि कर ली और उत्तरी चीन में अपना प्रभाव फैलाने लगा।

20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय प्रभावों से चीन के भीतर चार प्रमुख नए समूह खड़े हुए-रिपब्लिकन, नेशनलिस्ट, कम्युनिस्ट और चीनी संस्कृति के पक्षधर। इनमें से प्रत्येक का नेता ईसाई मिशनरियों के प्रभाव वाला है। चीनी संस्कृति की बात करने वाले यूंग विंग अमेरिका जाकर पढ़ाई की थी और उसने यूरोप की तर्ज पर चीनी संस्कृति का उद्धार करने की बात कही थी। सन यात सेन ईसाई हो गए थे और उन्होंने रिपब्लिकन और नेशनलिस्ट आंदोलनों को प्रेरणा दी। च्यांग काई शेक भी यूरोपीय ईसाई राष्ट्रों से प्रभावित नेता बनकर उभरे और अनेक कम्युनिस्ट नेता भी पादरियों की सहायता से उभरे। 20वीं शताब्दी में संपूर्ण चीन में हजारों छोटी-छोटी जागीरें थीं, ऐसा जान की ने अपनी उक्त पुस्तक के अध्याय 16 में बताया है।

1931 में जापानियों ने मनचूरिया पर कब्जा कर लिया और चीन के भी एक हिस्से पर कब्जा करने में सफल हो गए। दूसरे महायुद्ध में जर्मनी और जापान साथ थे तथा इंग्लैण्ड, फ्रांस और अमेरिका से उनका युद्ध हो रहा था जिसमें बाद में रूस भी इंग्लैण्ड के साथ आ गया। इसलिए जापान को रोकने के लिए रूस और अमेरिका दोनों ने चीन को भरपूर सहायता उपलब्ध कराई। जापान ने रूस को 1905 में हराया था इसलिए रूस जापान से बदला लेना चाहता था और साथ ही चीन को जापान के प्रभाव से मुक्त रखना चाहता था। इस प्रकार जापान के विरुद्ध रूस और अमेरिका दोनों अपने-अपने ढंग से चीन को मदद कर रहे थे। अमेरिका ने वहां राष्ट्रवादी समूहों को बढ़ावा दिया और च्यांग काई शेक का साथ दिया, जबकि रूस ने कम्युनिस्ट पार्टी को बढ़ावा दिया और बहुत बड़ी धनराशि पार्टी के विस्तार के लिए दी। इस धन को स्वीकार करने पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में आरंभ में कुछ हिचक थी परंतु माओ खुलकर इसके समर्थन में आए और इसलिए वे रूस के चहेते बन गए। रूस ने अन्य अनेक प्रभावशाली कम्युनिस्ट नेताओं को हाशिए पर डलवा दिया और माओ त्से तुंग को ही नेता स्वीकार करने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर दबाव डाला। इस प्रकार माओ त्से तुंग के नेतृत्व का उदय हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका च्यांग काई शेक का साथ देता तो रहा, परंतु साथ ही युद्ध छिड़ने पर वह रूस को भी सहन करता रहा और इस प्रकार 1911 में पहले राष्ट्रवादियों ने मानचू शासन हटाकर चीनी गणराज्य की स्थापना की घोषणा की। जिन्हें रूस की सहायता से हराकर कम्युनिस्टों ने 1949 में चीनी गणराज्य की स्थापना की घोषणा की। महायुद्ध में साथ देने के लिए अमेरिका भी चीन के प्रति अनुकूल रहा और उधर स्तालिन ने खुलकर नीतिगत तथा धन की भरपूर मदद देकर चीनियों को सत्ता पर कब्जा करने की प्रेरणा और सहायता दी।

इस प्रकार चीन में जनवादी गणराज्य तो स्थापित हुआ ही, इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा अमेरिका के शत्रु देशों मंगोलिया और मंचूरिया के भी बड़े हिस्से को नए चीनी गणराज्य में शामिल करने में सहायता दी। इस तरह महायुद्ध के कारण और उसमें विजेता पक्ष का साथ देने के कारण चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को पहली बार एक बहुत बड़े इलाके का शासक बनने का सौभाग्य मिला।

(लेखिका अंतरराष्ट्रीय राजनय की विशेषज्ञ हैं)

हमारे भारत देश में तिब्बती शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या है। चीन की विस्तारवादी नीति के परिणामस्वरूप एक अहिंसक धार्मिक देश तिब्बत पराधीन हो गया। 1959 में इसका चरमोत्कर्ष देखने को मिला जब तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष परम पावन दलाई लामा को अपने लाखों अनुयायियों के साथ अपना देश छोड़ भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत में रह रहा तिब्बती समुदाय तिब्बत में रह रहे चीनी सत्ता से संघर्षरत तिब्बतियों की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। 19वीं सदी के अन्त तक तिब्बत स्वतंत्र था। तिब्बत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय अधिकारों के प्रश्न पर छाई वैश्विक चुप्पी को तोड़ने और उन्हें स्वाधीनता दिलाने की जद्दोजहद करता है सुप्रसिद्ध लेखिका नीरजा माधव द्वारा लिखा भारत में हिन्दी का पहला उपन्यास–गेशे जम्पा। प्रस्तुत है इस उपन्यास की दसवीं कड़ी

■ नीरजा माधव

गेशे जम्पा

द्रवित भाव से पिताजी ने उनका सिर सहलाया और बोले थे- नहीं बेटा, सब कैसे जा सकेंगे? फिर तुम तो वहां बेहतर जीवन के लिए जा रहे हो। जब योग्य बन जाओगे तो हम वापस बुला लेंगे। फिर आप भी क्यों नहीं चल रहे हैं साथ? जम्पा मचल उठे। मां घर पर अकेली कैसे रहेगी? हूं...? पिताजी ने बहलाने का प्रयास किया। तो लौट चलो। मां को भी ले लेते हैं। अभी थोड़ी ही दूर तो आए हैं। वे पुनः मचल उठे। नहीं बेटा, कितनी दूर तो आ गए हम नङ्गर-चे से। उतना लंबा-चौड़ा युम डोग्-छो पार किया। मीलों मैदान फिर खारु-ला की चढ़ाई और उतराई और अब ग्यांची पहुंचने वाले हैं हम। ना बाबा ना, मेरी तो हिम्मत नहीं लौटने की। पिताजी ने उन्हें मनाया था।

कहीं हमारे न रहने पर वे सिपाही आ गए तो मां क्या करेगी? उसको बांधकर ले जाएंगे। जम्पा रुआंसे हो उठे थे। नहीं, मां दरवाजा नहीं खोलेगी। पिताजी ने तर्क दिया। इतनी जल्दी वे सब नहीं आएंगे। पिताजी ने आगे कहा, जानते हो जम्पा! जाड़े में यह नदी बर्फ बन जाती है और इस पार से उस पार लोग पैदल ही जाते हैं।

पहाड़ी पर चढ़ते ही एकाएक तेज आंधी आई थी जिसने उन लोगों को एक प्राकृतिक गुफा में बैठने के लिए विवश कर दिया था। कुछ ही देर में एक तेज बारिश का झोंका आकर चला गया था। कुछ देर के लिए जम्पा प्रकृति के मनोहर दृश्य में अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। सामने नदी के आर-पार सुंदर इंद्रधनुष उग आया था। अद्भुत सौंदर्य था उसका। दोनों छोरों पर पहाड़ स्तंभ की तरह खड़े थे और उन पर मेहराब की तरह टिका था रंग-बिरंगा इंद्रधनुष। बीच की उपत्यका में चमरी चराने वाले डोकपा लोगों के तंबूनुमा घर दिखाई पड़ रहे थे। जम्पा पिताजी के साथ मंत्रमुग्ध से बढ़े जा रहे थे। एकाध जगह चमरी के हल से खेत जोतते हुए किसान भी दिखाई पड़े थे।

चाय पी जाए? पिताजी ने उनके थके चेहरे को निहारते हुए पूछा था। हां। जम्पा ने कहा। चलते-चलते सचमुच उन्हें भूख और प्यास दोनों लग रही थी। कुछ ही दूर स्थित एक छोलदारी में वे रुके थे। लकड़ी के प्याले में मक्खन-मिश्रित चाय और सत्तू खाकर वे पुनः चल पड़े थे। शाम होने से पहले ही उन्हें दूसरे गांव पहुंच जाना था जहां से अन्य साथियों को भी साथ लेकर भारतीय सीमा की ओर बढ़ना था उन्हें। ल्-दोङ् से पहले ही छु-शोर ग्य-पोन गांव पड़ा था। इस उपत्यका में कितने ही खंडहर और बस्तियों के ध्वंसावशेष दिखाई पड़े थे जम्पा को। इसमें कौन रहता है? उत्सुकता जागी थी जम्पा की। रहते नहीं, रहते थे। पिताजी ने खच्चर को एक घर के सामने रोकते हुए कहा। कहां गए? वे लोग भी गांव छोड़कर चले गए? जम्पा का स्वर दुखी था। तभी उस घर के भीतर से एक बूढ़ी महिला बाहर आई थी। आ गए तुम थुप्तेन? आओ, भीतर आ जाओ। उसने पिताजी को नाम से संबोधित कर कहा।

हां दीदी, ये जम्पा है। बच्चे तैयार हैं न? पिताजी अंदर की ओर बढ़ते हुए पूछ रहे थे। हां, सब तैयार हैं। बस, उनके बाप को समझाओ। वो भी जाने की जिद किए हुए

है। कहता है, यहां मरने के लिए कौन रहेगा? अब तुम्हीं बताओ, पूरा तिब्बत खाली करके हम उन्हें सौंप जाएं? यह कोई बात हुई? मरना ही होगा तो कहीं भी मर जाएंगे। तिब्बत में मरेंगे तो कम से कम अपनी मिट्टी में तो मिट्टी मिलेगी। चीऊ..चीऊ! पिताजी ने आवाज लगाई तो उस आदमी ने सिर उठाया था। यह उसका घरेलू नाम था शायद। क्या बात है चीऊ? पिताजी ने प्रश्न किया। भैया, देखो न, मां मुझे नहीं जाने दे रही है। मैं नहीं रहना चाहता यहां। वह रुआंसा हो उठा था। बक ले चाहे जितना, पर तुझे नहीं जाना है। थुप्तेन जा रहा है क्या देश छोड़कर? बूढ़ी औरत रसोई की ओर बढ़ते हुए बोली। जम्पा को लग रहा था कि काश! उनकी मां भी उन्हें उसी तरह रोक लेतीं। उस बूढ़ी महिला की निडरता और धैर्य पर आश्चर्यचकित थे जम्पा। मां कितना रो रही थी आते समय? पर यह बूढ़ी मां कितनी निर्भीक है?

मे आई कम इन, सर? देवयानी के स्वर से अतीत की शृंखला टूटकर वर्तमान से पृथक हो गई थी। गेशे जम्पा ने चौंककर पीछे देखा। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? वह खिड़की के पास खड़े गेशे जम्पा को देख अचकचाकर पूछ रही थी। नहीं, नहीं, आ जाओ। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। एकाएक मुंह से निकले अपने ही वाक्य पर वे झेंप से गए थे। सुधारते हुए कहा था–मेरा आशय था कि मैंने तुम्हें किसी काम से बुलाया था। जी कहिए। उसके होंठों पर मधुर हंसी तैर रही थी। कुछ बच्चे आए हैं धर्मशाला से। तिब्बती शरणार्थी अपनी भाषा छोड़ कुछ नहीं जानते। तुम उन्हें हिंदी पढ़ा दो ताकि यहां के साथ सामंजस्य बैठा सकें। अपनी झेंप मिटाने के चक्कर में उन्होंने तुरंत अपना प्रस्ताव रख दिया था। बैठने के लिए भी नहीं कहा देवयानी से। तुम दोलमा माई से मिल लो। बाकी कल तुम्हें मैं समझा दूंगा। एक परिचय बच्चों से ले लो।

जी, अच्छा। जाऊं? वह पूछ रही थी। उसके बाल आज खुले नहीं थे। लपेटकर बनाए गए उसके जूड़े में बेला का एक सफेद फूल टंका हुआ था जो कान की बगल से दिखाई दे रहा था। ओ, हां.. यदि बैठना नहीं हो तो जा सकती हो। गेशे जम्पा को अपना ही जवाब विचित्र-सा लग रहा था। जी, टाशी डेलेक। वह ठिठकी और फिर जाने के लिए मुड़ गई थी। लोहे के मुख्य द्वार पर ठक्-ठक् की आवाज सुनकर देवयानी ने अपने कमरे की बाहरी खिड़की खोलकर झांका था। इतनी रात में उससे मिलने कोई नहीं आता।

कौन? अपने कमरे से लोब्जंग ने पूछा था। मैं हूं अनचू ढोंढप्। दरवाजा खोलिए। आगंतुक ने अपना परिचय दिया था। देवयानी ने अपनी खिड़की बंद करते हुए बाहरी प्रकाश में आगंतुक का चेहरा देखा। न जाने क्यों सभी तिब्बतियों का चेहरा उसे लगभग एक समान लगता। वही गोरा-सा रंग, पतले-पतले होंठ, छोटी-छोटी आंखें जैसे गालों की त्वचा से निकली हुईं। बस वस्त्रों में परिवर्तन कभी-कभी दिखाई पड़ जाता। कुछ भिक्षु-वेश में, तो कुछ अत्याधुनिक जीन्स की पैंट और ढीली-ढाली शर्ट में। यह आगंतुक भी ढीली, सफेद शर्ट और काले रंग की जीन्स पहने हुए था।

अरे ढोंढप्, इतनी रात में कैसे? लोब्जंग मुख्य द्वार की सिटकिनी खोलते हुए पूछ रही थी। बस ऐसे ही मां। एक मीटिंग थी यहां सारनाथ में, तिब्बती यूथ कांग्रेस की। सोचा, गेस्ट हाउस में क्या रुकूं? वह भीतर आ गया था। देवयानी खिड़की की झिरी से उसे देख चुकी थी।

बहुत अच्छा किया। सीरीड् क्यों नहीं आई? लोब्जंग पीछे से गेट बंद करते हुए पूछ रही थी। अब मीटिंग में उसको लेकर क्या चलूं? वह हंसते हुए कंधे उचकाता अंदर की ओर बढ़ा था। कौन है दीदी? छोटा भाई दीपेश आकर देवयानी की बगल में खड़ा हो गया। वही जिसके बारे में उस दिन लोब्जंग बता रही थी कि उसका सौतेला दामाद है...टनचू ढोंढप्। देवयानी ने खिड़की पूरी तरह बंद कर दी।

अच्छा, अच्छा, मखन्चूजी आए हैं? वह मजाक करते हुए हंस पड़ा। अरे दीपेश, एम.ए. कर रहे हो। कब सभ्यता आएगी? इतनी

बच्चे तैयार हैं। हां, बस, उनके बाप को समझाओ। वो भी जाने की जिद किए हुए है। कहता है, यहां मरने के लिए कौन रहेगा? अब तुम्हीं बताओ, पूरा तिब्बत खाली करके हम उन्हें सौंप जाएं? यह कोई बात हुई? मरना ही होगा तो कहीं भी मर जाएंगे। तिब्बत में मरेंगे तो कम से कम अपनी मिट्टी में तो मिट्टी मिलेगी।

जोर से बोल रहे हो। सुन ले तो? देवयानी किंचित नाराज हो उठी थी। कौन है देवयानी? मां भी दूसरे कमरे से आ गई थीं। कोई नहीं मां। हमारे यहां नहीं है। वो मकान मालकिन के यहां आए हैं, मेहमान। लोब्जंग आंटी के पाहुनजी आए हैं मां। मखन्यू ढोंढप्जी। दीपेश ने धीरे से फुसफुसाते हुए मां के कंधों को हिला दिया था।

देवयानी को भी हंसी आ गई। कृत्रिम नाराजगी प्रकट करते हुए बोलीं थी-देख रही हो न मां? कल ही मकान मालकिन हम लोगों का बोरिया बिस्तर बंधवा देगी। उनका दामाद है टनचू ढोंढप्, दासेर पत्रिका का संपादक है वह, और दीपेश उसे...देवयानी की बात अधूरी ही थी, तभी कमरे का दरवाजा धकेलते हुए लोब्जंग प्रकट हुई थी। उसके चेहरे पर हड़बड़ाहट के साथ एक झेंप वाला भाव भी घुमड़ रहा था। वो मैदम, एक निवेदन था! जी बोलिए। देवयानी अपनी कुर्सी उनकी ओर खिसकाते हुए बोल पड़ी। वह सशंकित थी कि कहीं लोब्जंग ने दीपेश की बातें सुन न ली हों, पर लोब्जंग के निवेदन करते ही उसकी आशंका समाप्त हो गई थी। **(जारी...)**

कामरेड को कानूनगो पर गुस्सा क्यों आता है?

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और उसके अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की सक्रियता से बौखलाए वामपंथी-कट्टरवादी

कुछ समय पहले तक देश में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का नाम शायद कुछ ही लोगों ने सुना होगा, लेकिन पिछले एक महीने से यह आयोग सुर्खियों में है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एनसीपीसीआर और इसके अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के खिलाफ अचानक लाखों ट्विट आने लगे हैं? दरअसल, पिछले करीब दो साल में एनसीपीसीआर ने कई ऐसे मामलों को पकड़ा है, जिनको सामने लाने की हिम्मत पहले कभी किसी ने नहीं की।

ताजा मामला 'एल्ट न्यूज' और जुबैर नाम के व्यक्ति का है, जिसको वामपंथी धड़ा 'तथ्य परखने' वाला बताता है। जुबैर और उसके समर्थक इस साइट के जरिए केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कथित तथ्य खोजते रहते हैं। इसी से पता चलता है कि इनके तथ्य किस प्रकार के होते हैं।

दरअसल, पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति की जुबैर के साथ ट्विटर पर कुछ बातों को लेकर कहासुनी हो गई। इससे नाराज होकर जुबैर ने उस व्यक्ति और उसकी बच्ची का फोटो ट्विटर पर डाल दिया। इसके बाद जुबैर के ट्विटर समर्थकों ने बच्ची को बलात्कार तक की धमकी दे डाली। इससे परेशान होकर उस व्यक्ति ने एनसीपीसीआर को ईमेल से एक शिकायत भेजी, जिसमें बच्ची को लेकर आ रहे धमकी भरे ट्विट्स का जिक्र था। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रियंक कानूनगो ने इस मामले में स्थानीय पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा।

प्रियंक कानूनगो

ट्विटर पर बच्ची की फोटो डालने के कारण मामला आईटी एक्ट की धारा 67 और आईपीसी की धारा 509 के उल्लंघन का बन गया था। बच्ची को बलात्कार की धमकी देने से पोस्को एक्ट भी लागू हो गया। पोस्को एक्ट का सेक्शन 19 कहता है कि किसी बच्चे के साथ कोई लैंगिक अपराध हुआ है या होने की संभावना है, तो इस बारे में पुलिस को बताना ही पड़ेगा। जो पुलिस को नहीं बताएगा, वह धारा 21 पोस्को एक्ट में आरोपी हो जाएगा। इसलिए प्रियंक ने वह शिकायत पुलिस को कार्रवाई के लिए भेज दी। मामला गंभीर था लिहाजा पुलिस ने भी इस पर एफआईआर करके जांच शुरू कर दी। बस, यहीं से जुबैर और उसका पूरा गिरोह प्रियंक के खिलाफ हो गया। पहले तो जुबैर के पक्ष में और प्रियंक के खिलाफ लाखों ट्विट्स किए गए। खास बात यह है कि इनमें से आधे खाड़ी देशों से आए थे। इसके बाद भी आयोग इस मामले पर झुकने को तैयार नहीं हुआ तो प्रियंक और आयोग को दबाव में लाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मानहानि का मुकदमा डाल दिया गया। खास बात यह है कि जिस मामले की पुलिस अभी जांच कर रही है, उस पर न्यायालय ने 50,00000 रु. की मानहानि का मुकदमा भी स्वीकार कर लिया।

हालांकि दूसरी बड़ी बात यह है कि इस मानहानि का मुकदमा वकील कोलिन गोंसालविस लड़ रहे हैं। इनका संबंध चर्च से है। यही कोलिन शाहीन बाग मामले में भी प्रदर्शनकारियों के वकील हैं। दरअसल, कोलिन इस मुकदमे को क्यों लड़ रहे हैं, इसका भी एक कारण है। उल्लेखनीय है कि वे चर्च से जुड़े हैं और चर्च को विदेश से सेवा कार्यों के नाम पर पैसा मिलता है, लेकिन आयोग ने ऐसे चर्चों की पोल खोलता रहा है। इसलिए कोलिन गिरोह आयोग और उसके अध्यक्ष के विरुद्ध कोई भी मामला अपने हाथ से जाने नहीं देता है। जब से प्रियंक आयोग के अध्यक्ष बने हैं तब से मिशनरीज ऑफ चैरिटी, डॉन बास्को जैसे संगठनों की पोल खुल रही है। मिशनरी ऑफ चैरिटी बच्चों को बेचने का धंधा करती है। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। एक और बड़ा मुद्दा है, जिसमें प्रियंक और बाल आयोग ने जो काम किया है, वह कई ईसाई संस्थाओं को सुहा नहीं रहा है। दरअसल, चिल्ड्रन होम्स में बच्चों को बाइबल पढ़ाई जाती है, जो कि कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन था। इस मामले की जांच आयोग ने की और सरकारी रिपोर्ट में पहली बार आयोग ने लिखा कि जांच के दौरान हमने पाया कि कुछ होम्स में बाइबल पढ़ाई जा रही थी। यह सीधे-सीधे बच्चों के कन्वर्जन का मामला था। लिहाजा बाल आयोग और इसके अध्यक्ष का निशाने पर आना स्वाभाविक है।

यह मामला गंभीर है। उम्मीद है कि न्यायालय इंसाफ करेगा और जिहादी तत्वों पर लगाम लगाने का रास्ता साफ होगा। ■ **प्रतिनिधि**

हर घर जल

जल आपूर्ति विभाग
गुजरात सरकार

WASMO

GWIL

वोटर ग्रीड

- पीने के पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2950 किलोमीटर लंबी बल्क पाइपलाइन से सौराष्ट्र और कच्छ के कोने कोने तक 2000 एमएलडी पानी स्थानांतरित किया जाता है।
- सौराष्ट्र और कच्छ के 1.8 करोड़ लोगों को उनकी घरेलु आवश्यकताओं के लिए प्रतिदिन नर्मदा से 1950 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जाती है।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पानी उपलब्ध कराने के लिए जल आपूर्ति विभाग द्वारा पूरे गुजरात में 1,20,000 किलोमीटर लंबा जल वितरण पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित किया गया हैं।

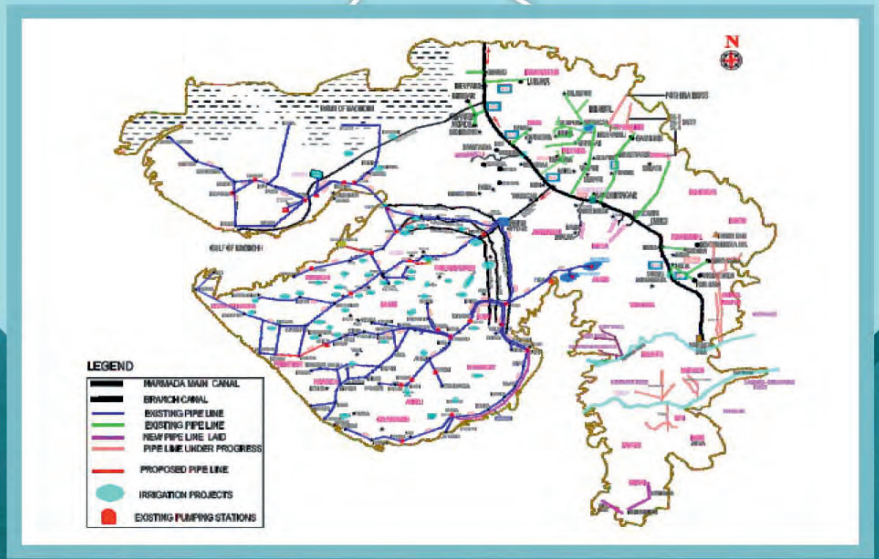

आर.एन.आई.पंजीकृत संख्या 32543/1977
21-27 सितम्बर, 2020
(19 सितम्बर को प्रकाशित, पृष्ठ-52)

पाञ्चजन्य
साप्ताहिक

दिल्ली पोस्टल क्र.डी.एल.(सी.)-01/1102/2018-20 पी.एस.ओ., नई दिल्ली-1
लाइसेंस क्र.यू.(सी.)-87/2018-20 अग्रिम शुल्क बिना प्रेषण की अनुमति 19-21/9/2020

कोविड-19

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं
आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं

कोविड-19 महामारी की कोई दवा अभी तक नहीं बनी है। इससे बचने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय करना ही बेहतर है। जीवन में प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक प्रणाली की भूमिका महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णित सरल उपायों के द्वारा व्यक्ति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बेहतर कर सकता है। आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। घर पर रहें, स्वस्थ रहें।

जय राम ठाकुर
मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

सामान्य उपाय

पूरे दिन केवल गर्म पानी पिएं।

प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान करें।

हल्दी, जीरा, धनिया एवं लहसुन आदि मसालों का भोजन बनाने में प्रयोग करें।

आयुर्वेदिक उपाय

- च्यवनप्राश 10 ग्राम (1 चम्मच) सुबह लें। मधुमेह रोगी शुगर फ्री च्यवनप्राश लें।
- तुलसी, दालचीनी, कालीमिर्च, शुण्ठी (सूखी अदरक) एवं मुनक्का से बनी हर्बल टी/काढ़ा दिन में एक से दो बार पिएं। स्वाद के अनुसार इसमें गुड़ या ताज़ा नींबू का रस मिला सकते हैं।
- गोल्डन मिल्क- 150 मि0ली0 गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी चूर्ण दिन में एक से दो बार लें।

सामान्य आयुर्वेदिक उपाय

- नस्य-सुबह एवं शाम तिल/नारियल का तेल या घी नाक के दोनों छिद्रों में लगाएं।
- कवल- 1 चम्मच तिल/नारियल तेल को मुंह में लेकर दो से तीन मिनट कुल्ले की तरह मुंह में ही घुमाएं। उसके बाद कुल्ले की तरह ही थूक दें। फिर गर्म पानी से कुल्ला कर लें। ऐसा दिन में एक से दो बार करें।

खांसी/गले में खराश के लिए

- दिन में कम से कम एक बार पुदीना के पत्ते /अजवाइन डाल कर पानी की भाप लें।
- खांसी या गले में खराश होने पर लौंग के चूर्ण में गुड़ या शहद मिलाकर दिन में दो से तीन बार लें।
- ये उपाय सामान्य सूखी खांसी एवं गले की खराश के लिए लाभदायक हैं, फिर भी यदि लक्षण बने रहते हैं तो डॉक्टर से परामर्श लें।

www.himachalpr.gov.in HimachalPradeshGovtIPRDept DPR Himachal dprhp
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार